असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

12 मार्च, 2018

षोडश विधान-सभा सोमवार,तिथि 12 मार्च, 2018 ई0
नवम् सत्र 21 फाल्गुन,1939 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर-काल । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे। तारांकित प्रश्न सं0-क 359, माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ । वित्त विभाग ।

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न सं0-क 359(श्री समीर कुमार महासेठ)

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, चूँकि क्वेश्चन हमारा बहुत स्पष्ट था, क्वेश्चन करने का मंशा था कि कहीं न कहीं इसमें सुधार हो । जो प्रक्रियात्मक चला आ रहा है, वही जवाब आया है । मेरा पूरक प्रश्न है कि सरकार द्वारा छुट्टी अनुमान्यता वाली अवधि एक वर्ष नहीं की गई है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के पास छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन के कितने मामले लंबित हैं और उन मामलों का निष्पादन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद वैयक्तिक दावा कोषांग में काफी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और अभी कुल मिलाकर 8000 मामले हैं,केवल अर्जित अवकाश के ही नहीं, सभी तरह के जो दावे हैं । यह सारा काम अभी मैनुअली वहां हो रहा है । इसलिए माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि समय लग रहा है । मैंने इसकी पूरी समीक्षा की है, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने एच0आर0एम0एस0 ह्यूमेन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी हमारे जितने कर्मचारी हैं, उन सबों का सर्विस बुक जो है, वह इलेक्ट्रोनिक सर्विस बुक होगा । अगर किसी को कोई छुट्टी के लिए आवेदन देना है, उसका ट्रांस्फर, पोस्टिंग, प्रोमोशन, आरोप लगे हैं, उनकी सारी चीजें एक जगह संकलित रहेगी और इसमें करीब एक साल का समय लगेगा एच0आर0एम0एस0 को विकसित करने में, टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है । तब तक मैंने विभाग को इस बात का निर्देश दिया है कि केवल यह जो वैयक्तिक दावा में छुट्टियों के लिए आवेदन आते हैं, अभी प्रक्रिया है कि वे विभाग में आवेदन देंगे, फिर जो उनके प्रेजाईडिंग ऑफिसर हैं, उनके डिपार्टमेंट के जो

कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, वह फिजिकल भेजेंगे कोषांग में और कोषांग उसको देखेगा और फिर भेजेगा, ये सारी चीजें ऑनलाईन हो जाय । अगर जिसको आवेदन करना है, वह ऑनलाईन आवेदन दे, विभाग जो भेजेगा और वित्त विभाग में जो जायेगा, वह भी ऑनलाईन पहुँचे और फिर प्रोसेस करके उसका जवाब ऑनलाईन भेज दिया जाय तो मैंने इसकी पूरी समीक्षा की है । मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोकहित का एक अच्छा सवाल किया है तो एच0आर0एम0एस0 ह्यूमेन रिसोसर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की सारी चीजें एक जगह संग्रहित रहेगी और सारा काम ऑनलाईन होगा । खासकर जो छुट्टी अनुमान्यता से जुड़ा हुआ मामला है, मैंने कहा है कि तत्काल एक अलग से इसका सोफ्टवेयर विकसित किया जाय, ताकि छुट्टी से जुड़े हुए जो मामले हैं, वो एच0आर0एम0एस0 आने से पहले भी इसको हम लागू कर सकें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : यह केवल हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं चूँकि बिहार में ही अगर मान लीजिए महालेखाकार कार्यालय के तर्ज पर छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन एवं तत्संबंधी वेतन पुर्जा निर्गत करने के लिए अधिकतम अवधि एक माह निर्धारित करने का अगर विचार रखती है तो हमको लगता है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा सा जो भी टाईम लगे, लेकिन महालेखाकार का यहां बिहार में उसके हिसाब से रखा जाय तो शायद ज्यादा देर 6-6 महीना, 8-8 महीना टाईम नहीं लगेगा, तो हम केवल एक आश्वासन चाहते हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी आई0ए0एस0 को छोड़कर यानी वर्ग-1 के जो पदाधिकारी हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी लोगों का दावा इसी कोषांग में आता है । हमारा ए0जी0 के यहां केवल वर्ग-1 के जो पदाधिकारी हैं, उन्हीं का केवल उनके यहां जाता है । मैं आपको केवल यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार हो और इसको अलग से मैं देखूँगा कि इसको कितना टाईमबौंड किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : उसमें केवल माननीय वित्त मंत्री जी, जो प्रश्न में मामला है, एक तो सब आप ह्यूमेन रिसोसर्स मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दीजियेगा तो ऑनलाईन आ जायेगा लेकिन प्रश्न के मूल में जो है, जो भी उपार्जित अवकाश है, उसमें अगर कोई 10 दिन एवेल करना चाहते हैं तो पहले ए0जी0 से स्वीकृति लेनी होती है, प्रश्न है कि पूरे साल के लिए जो उनका इनटाईटीलमेंट है, एक बार उनको सरकार को कॉम्यूनिकेट हो जाय और सरकार अपने लेवल से उसको करे ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : उसमें हमने अपने लेवल से उसकी समीक्षा की है, चार साल पहले यह व्यवस्था की गई थी तो उसमें बड़े पैमाने पर शिकायत आने लगी । फिर इसको वापस केन्द्रीयकृत करके दावा कोषांग में कर दिया गया है । मैं आश्वस्त करना

चाहूँगा, प्रक्रिया जो भी हो इनका उद्देश्य है कि जल्द से जल्द उसका समाधान हो तो हमलोग इसके लिए काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न सं0-985(श्री विनोद प्रसाद यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत नहर प्रखंड शेरघाटी में मौजा शेरघाटी थाना सं0-762 के गत सर्वे खतियान के अनुसार खाता सं0-968, खेसरा सं0-2957, एराजी 0.48 डिसिमिल किस्म जमीन कब्रिस्तान खाता बनाम गैर-मजरूआ आम, दूबे बगीचा कब्रिस्तान एवं खाता स0-1131 खेसरा सं0-3031 एराजी 0.24 डिसमिल के सम्पत्ति जमीन खाता बनाम गैर-मजरूआ जमींदारी लगान तकिया कब्रिस्तान है, जिसका उपयोग कब्रिस्तान के रूप में हो रहा है । दूबे बगीचा कब्रिस्तान एवं लगान तकिया कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक -9 एवं 11 पर अंकित है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक-7 तक के कब्रिस्तानों का चयन कर घेराबंदी की कार्रवाई की जा रही है । प्राथमिकता सूची में बारी आने पर प्रश्नगत कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जायेगी ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, चूँकि यह दोनों कब्रिस्तान शहरी क्षेत्र में है और वहां पर कब्रिस्तानों के आस-पास महंगी जमीन है और वहां इनक्रोचमेंट होते रहता है, जिसके चलते विवाद बढ़ते रहता है वहां पर तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वित्तीय वर्ष 2018-19 प्रारंभ होने जा रहा है तो क्या उसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन कराने का निर्देश देना चाहेंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने कहा जैसा कि 7 तक हो चुका है और ये क्रमांक-9 एवं 11 पर है, कोशिश की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न सं0-986(सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना सं0-6761 दिनांक 12.05.2015 के द्वारा श्री फिरोज अख्तर, बिहार प्रशासनिक ऑफिसर के अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई, बिहार के पद पर पदस्थापित किया गया है ।

उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री अख्तर दिनांक 13.05.2015 को अनुमंडल पदाधिकारी,बारसोई का प्रभार ग्रहण किया है । इस प्रकार श्री अख्तर 2 वर्ष 10 माह से उक्त पद पर पदस्थापित हैं ।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-434 दिनांक 1.03.2007 की कंडिका 1 (ख) में प्रावधान है कि स्थानान्तरण, पदस्थापन

के लिए स्थापना समिति नहीं रहेगी बल्कि प्रभारी पदाधिकारी ऐसे पदाधिकारियों/सेवकों जो अपने वर्तमान पद पर 3 साल पूरे कर चुके हैं, उनके स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु प्रत्येक वर्ष मई माह में संचिका उपस्थापित करेंगे ।

3. उपर्युक्त 1 एवं 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ । लेकिन आज से नहीं बल्कि 2009 में उसी प्रखंड में बी0डी0ओ0 रहे, उसके बाद 2010 में डी0पी0आर0ओ0, एस0डी0ओ0 लगातार उसी जिला में 15 से 20 वर्षों से घुम रहे हैं, जिसके कारण राजनीत, भ्रष्टाचार में ज्यादा लिप्त पाये जा रहे हैं और मनिहारी अनुमंडल में भी अनुमंडल पदाधिकारी का 5 साल हो गया लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया । ऐसे जिला में कई वरीय पदाधिकारी हैं, जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से उसी जिला में घुम रहे हैं । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना है कि वैसे पदाधिकारी को चयनित करके उसे क्या स्थानान्तरण करने का काम करेंगे ?

टर्न-2/अंजनी/दि0 12.03.18

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसका कोई नियम नहीं है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी रहे या अन्य पदाधिकारी रहे, प्रश्न यह है कि केवल तीन साल से अधिक हो गया तो जो माननीय सदस्या कह रही हैं, इसपर विचार कर के देखवा लेंगे और कोशिश की जायेगी ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, ...

अध्यक्ष : सरकार ने कहा कि विचार करेंगे । इसपर अब क्या कहना है ?

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, विचार करेंगे, यह कहना नहीं है । कहना यह है कि माननीय सदस्या ने बड़ा स्पष्ट पूछा कि ये पदाधिकारी उस कटिहार जिले में विभिन्न पदों पर वर्षों-वर्षों से पदस्थपित थे । सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम और प्रावधान है, उस पर माननीय मंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेकर ऐसे पदाधिकारी जो दस साल-आठ साल से उसी जिला में पदस्थापित हैं जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है, इसलिए सरकार इसपर तुरंत कार्रवाई करे, यही मुझे कहना है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, प्रश्न को देखा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न तो एस0डी0ओ0 के संबंध में है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-987(श्री सैयद अबु दौजाना)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-988(श्री सीताराम यादव)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-989(श्री जितेन्द्र कुमार राय)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-990(श्री मो0 तौसीफ आलम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री रामदेव राय : महोदय, मुझे इस प्रश्न को पूछने हेतु अधिकृत किया गया है ।

अध्यक्ष : कोई ऑथोराइजेशन नहीं है ।

श्री रामदेव गय : महोदय, दिया गया है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, भेजा गया है ।

अध्यक्ष : नहीं है यहां ।

श्री रामदेव राय : नहीं है तो आप कार्यालय से देखवा लीजिए ।

अध्यक्ष : नहीं मिला है ।

श्री रामदेव राय : कार्यालय से देखवा लीजिए ।

अध्यक्ष : पता कराते हैं, होगा तो हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-991(श्रीमती सावित्री देवी)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-992(डॉ0 अब्दुल गफूर)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु जिलास्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक-49 पर अंकित है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 की कंडिका-6.3.4 में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-993(श्री हरिशंकर यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत नौतन प्रखंड के ग्राम खलवा में जमाबंदी संख्या 679, खाता संख्या-386 के अंश रकबा 100 की जमाबंदी स्वामी महानंद जी के नाम से है, जिस पर आश्रम अवस्थित है । बिहार मंदिर

चहारदिवारी निर्माण योजनान्तर्गत मात्र उन मंदिरों की चहारदिवारी निर्माण किया जाता है जो बिहार राज्य धाार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित हो । प्रश्नगत आश्रम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित नहीं है ।

श्री हरिशंकर यादव : महोदय, मंदिर का चहारदिवारी एकदम खत्म है और उसको बनाना, मरम्मती कराना बहुत ही आवश्यक है, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो उसको बनवा दिया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-994(श्री हरिशंकर यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

हुसैनगंज के मौजा हरसी टोला, ग्राम-खोदाई बरी थाना संख्या-362/2012, सर्वे संख्या-3852, 3853 एवं 3859, रकवा 0.57, 0127,001 में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी तीन तरफ से की जा चुकी है, एक तरफ से खाली है, लगभग 005 भूमि अस्थायी रूप से अतिक्रमित है, इसमें निदेश दिया गया है कि तीन तरफ से घेराबंदी कर दी गयी है और सिर्फ चौथे तरफ की घेराबंदी अविलम्ब करवा दिया जाये ।

श्री हरिशंकर यादव : अध्यक्ष महोदय, जिधर छूटा हुआ स्थान है....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि तीन तरफ से घेराबंदी किया हुआ है और सरकार ने निदेश दिया है कि चौथी तरफ भी कर दिया जायेगा ।

श्री हरिशंकर यादव : महोदय, बराबर उस स्थान पर विवाद होते रहता है जहां चहारदिवारी करना बाकी है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-995(श्री शम्भुनाथ यादव)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-996(श्री अचमित ऋषिदेव)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-997(श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपूर थाना कांड संख्या-155/17 दिनांक 18.07.17 में प्राथमिक अभियुक्त अशोक कुमार एवं दूसरा अप्राथमिक अभियुक्त रामाधार महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा इसके विरूद्ध आरोप-पत्र संख्या-152/17 दिनांक 9.10.17 समर्पित किया गया है, शेष अभियुक्त एक पंकज कुमार के विरूद्ध फरारी की स्थिति में माननीय

न्यायालय से अधिपत्र प्राप्त कर दिनांक 09.01.18 को विधिवत् तामिल किया गया है एवं अभियुक्त सोनु कुमार के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बताया गया है कि सोनु कुमार विधि विरूद्ध किशोर है, जिसका केस रेकर्ड किशोर न्याय बोर्ड, समस्तीपुर भेजा गया है । सोनु कुमार को किशोर न्याय बोर्ड, समस्तीपुर में उपस्थापना हेतु कांड लंबित है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-998(श्री अशोक कुमार सिंह)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-999(श्रीमती एज्या यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु जिलास्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 की कंडिका 6.3.4 में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या-1000(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1001(श्री प्रभुनाथ प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला के अगियांव गांव प्रखंडान्तर्गत ननौर पंचायत के ननौर एवं करबासिन पंचायत के ग्राम-गोडीहा में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी, पुनः प्रश्नगत दोनों कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्ण कर ली गयी है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1002(डॉ0 शमीम अहमद)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, यह प्रश्न स्वास्थ्य विभाग को स्थांतरित किया गया है ।

अध्यक्ष : स्थगित ।

टर्न-3/शंभु/12.03.18

तारांकित प्रश्न सं0-1003(श्री ललन पासवान)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : 1-उत्तर स्वीकारात्मक है।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है।

3- राज्य सरकार का राज्य में अपने स्तर से नयी चीनी मिल स्थापित करने की कोई कार्य योजना नहीं है । राज्य सरकार द्वारा राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों एवं मजदूरों के हित में राज्य में निजी सार्वजनिक सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिलों एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु प्रोत्साहन पैकेज 2006 की घोषणा की गयी थी जिसे औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के तर्ज पर निवेश हेतु और आकर्षक एवं प्रभावकारी बनाते हुए प्रोत्साहन पैकेज 2014 की घोषणा की गयी है । कैमूर और रोहतास जिले में वर्तमान में गन्ने की खेती मुख्य रूप से गुड़ निर्माण हेतु की जाती है । इन दोनों जिलों में नयी चीनी मिल स्थापित करने का अभी तक कोई भी प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है । यदि सरकार की प्रोत्साहन योजना से प्रेरित होकर कैमूर और रोहतास जिले में चीनी मिल स्थापित करने का किसी निवेशक से प्रस्ताव प्राप्त होगा तो सरकार उन्हें नियमानुकूल वैधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी ।

श्री ललन पासवान : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि प्रश्न सही है और खोलना चाहिए, लेकिन सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है । सरकार कई निजी कंपनियों को दी है और शुरू करायी है उत्तर बिहार में और कई बार ग्लोबल मीट भी हुआ है । सरकार ने प्राइवेट निवेशकों से आग्रह किया है- कैमूर, रोहतास पूरा डालमिया बंद होने के बाद पहाड़ी इलाका है। आज भी गन्ने की खेती व्यापक होती है, उत्तर प्रदेश जाती है । कैमूर के सटे हुए इलाके से उत्तर प्रदेश लोग जाकर बेचते हैं, मंत्री जी को पता है कि नहीं है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री ललन पासवान : पूरक ही पूछ रहे हैं सर । महोदय, सरकार न्याय के साथ विकास करती है तो नया प्रस्ताव मांगने की बात.....

अध्यक्ष : आप पूरक नहीं पूछ रहे हैं । आप पूरक पूछियेगा तब.....

(व्यवधान)

श्री ललन पासवान : आपको पूछना होगा तब पूछ लीजिएगा मुझे तो पूछने दीजिए । महोदय, हम जानना चाहते हैं कि सरकार जो यह कह रही है कि प्रस्ताव आयेगा तो विचार तो सरकार को ही प्रस्ताव लाना है । महोदय, कैमूर, रोहतास में डालमिया के बंद होने के बाद क्या सरकार निजी कंपनियों से बात करके भी इस तरह का वहां चीनी मिल खोलने का विचार रखती है ? कितने ग्लोबल मीट हुए, कितने बार मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ, कई बार कंपनियों आयी कई जगह की तो सरकार जो उसपर प्रस्ताव ली है- कैमूर और रोहतास में कोई चीनी मिल निजी कंपनियों से बात करके और प्रस्ताव मंगाकर खोलने का विचार रखती है ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : महोदय, सरकार हमेशा तत्पर है कि नयी चीनी मिल स्थापित की जाय । सरकार इसपर पांच बार निविदा आमंत्रित की, निवेशकों को अमंत्रित की और अगर निवेशक जब भी इसके लिए आते हैं तो सरकार खुद गंभीर है नये मिल लगाने के लिए, स्थापित करने के लिए ।

अध्यक्ष : अभी आलोक जी को हमने कहा है पूछने के लिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बिहार में चीनी मिलें लंबे समय से बंद हैं और सरकार विकास के हर मोर्चे पर दावा करती है कि वह उसमें सुधार ला रही है, नये-नये प्रस्ताव ला रही है और उसमें प्रयास कर रही है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है । सबसे पहले सरकार को प्रस्ताव लाना चाहिए ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि सरकार स्वयं मिल नहीं खोलती है । वहां खोलने के लिए इन्होंने प्रस्ताव आमंत्रित किया है जो कहीं से नहीं आया है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि निगम के द्वारा चलायी जा रही सारी चीनी मिलें जब उसका लैंड इक्वीजिशन हो रहा था ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए आलोक जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : मैं वही पूछ रहा हूँ अभी बड़े पैमाने पर ऐसी चीनी मिलों की जमीन को चीनी मिल के इस्तेमाल में नहीं लाकर और औनपौने दाम पर प्राइवेट सेक्टर को बेचने की और आपस में बंदरबांट करने की साजिश हो रही है और इसकी पुख्ता सूचना हमलोगों के पास है।

अध्यक्ष : तो पूरक क्या है ?

श्री आलोक कुमार मेहता : अब सवाल यह उठता है कि चीनी मिल इतना बड़ा क्षेत्र है यहां जहां ईख के उत्पादन की बड़ी संभावना है । आखिर किस रॉ मेटेरियल के बेस पर सरकार उद्योग लगाना चाहती है या किसी को आमंत्रित करना चाहती है, आमंत्रित भी करना चाहती है तो सरकार ने जिस लैंड को एक्वायर किया है उस लैंड को सबसे पहले सील करे उसके बाद चीनी मिल जिसको आमंत्रित करने जा रही है.....

अध्यक्ष : आप पूरक पर नहीं आ रहे हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : इज ऑफ बिजनेश डूइंग की बात सरकार हमेशा करती रही है उस फ्रंट पर बिलकुल फेल्योर है ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्नोत्तर में एक बात की और जानकारी दी कि हम कॉपरेटिव सेक्टर के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो चीनी मिल स्थापित करें । क्या अब तक कॉपरेटिव सेक्टर से माननीय मंत्री जी या विभाग को कोई ऐसा प्रस्ताव आया है ?

अध्यक्ष : पूछ रहे हैं कि को-ऑपरेटिव साइड से कोई प्रस्ताव आया है ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : महोदय, एक निविदा रैयाम चीनी मिल लगाने के लिए आया है जिसपर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी इन्होंने रैयाम चीनी मिल का नाम लिया - ऐसे कितने मिल हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में बंदोबस्त सरकार के द्वारा किया गया है - रैयाम, सकरी और दूसरे अन्य मिल और कितने दिन पहले दिया गया और उसपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है ?

अध्यक्ष : यह प्रश्न रोहतास और कैमूर से रीलेटेड है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, चूंकि उनके उत्तर से पूरक प्रश्न उठा । डालमिया नगर के बारे में उन्होंने कहा कॉपरेटिव सेक्टर और इसमें हम आमंत्रित कर रहे हैं तो हम यह जानना चाहते हैं कि बिहार में ऐसे सिक मिल जो बंद पड़े हैं उनको भी किस प्राइवेट पार्टी को दिया गया और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि जो चीज आपने रोहतास और कैमूर जिले में डालमिया नगर के संबंध में किया है । दूसरे भी जो मिल बंद हैं उसके बारे में भी करियेगा सो पूछ रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : दूसरे मिल को इन्होंने प्राइवेट पार्टी को दिया था पांच साल पहले मगर उससे कुछ नहीं हो रहा है और वह उसका लकड़ी मशीन सब बेच दिया ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वैसे बंद पड़े मिलों उसमें डालमिया नगर के लिए हम ग्लोबल मीट कर रहे हैं तो माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि डालमिया नगर चीनी मिल है या गुरारू चीनी मिल है, वारिसलीगंज चीनी मिल है, इन चीनी मिलों के लिए आपने अलग से कोई अपने विभाग में अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके एक टेंडर ग्लोबल मिट कराने का कोई कार्रवाई किया है, अगर किया है बतायें, नहीं किये हैं तो कृपया इसपर कार्रवाई करें ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर खड़े होकर बोलने लगे)

टर्न-04/अशोक/12.03.18

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । यह प्रश्न जो है पूरे बिहार से संबंधित है, राज्य से संबंधित है । 15 साल में बंद पड़े चीनी मिलों को सरकार ने खोल नही सकी, बेचने का काम कर रही है । मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न की महत्ता को देखते हुये विशेष वाद-विवाद जो है, सदन में कराइये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी, आप पुराने सदस्य हैं, विशेष वाद-विवाद के लिए कोई विषय निर्धारित करने का तो तरीका ही अलग है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मैं लिख कर दूंगा । हम लिख कर देंगे ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या- 1004 (डॉ0(मो0) जावेद)

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के अधिकांश माननीय सदस्यगण वेल में चले आये)

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, यह जो तारांकित प्रश्न है महोदय, रोहतास एवं कैमूर से जुड़ा हुआ है, और माननीय सिनियर लिडर लोग, माननीय जो विपक्ष में बैठे हैं, चाहे

सदानन्द बाबू हों, चाहे आदरणीय सिद्दिकी साहब हों तो यह सवाल तो दूसरे स्वरूप में जो आसन का निर्देश हुआ महोदय, ध्यानाकर्षण के माध्यम से लावे तो इसका व्यापक जवाब राज्य के हित में दिया जायेगा महोदय, सरकार कहां भाग रही है ? सरकार तो जवाब देने के लिए तैयार है । लेकिन दूसरे स्वरूप में जिन-जिन चीनी मिले बंद है और कहां-कहां क्या सरकार कार्रवाई की है पूरे विस्तार से जवाब हम देना चाहते हैं । इसके लिए आप थोड़ा धैर्य रखिये, नियम के हिसाब से, जो प्रश्न है उसको लाइये ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सिद्दिकी साहब ने तो कहा है कि ये विशेष वाद-विवाद के लिए प्रस्ताव लायेंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : लम्बे अर्से से संसदीय कार्य मंत्री हैं, श्रवण कुमार जी और यह जानते हैं कि प्रश्नकर्त्ता के उत्तर में अगर कोई पूरक सवाल उठता है तो पूरक किया जाता है, ऐसा नहीं है कि यह डालमिया से ही संबंधित है, मगर अपने मंत्री जी का क्लास लिया कीजिये कि वो पूरे बिहार में लांसिंग करे रहे हैं, फ्री लांसिंग कर रहे हैं । (व्यवधान) मै बैठ जा रहा हूँ मैं तो चाहूंगा कि ठीक है कि अभी उप मुख्यमंत्री जी उठे, इन्होंने कहा, ये कहा करते थे उद्योग बंद हो गया, सारा उद्योग को खुलवा रहे हैं, पूरे बिहार में बहार है अब माननीय उप मुख्यमंत्री उठकर बोलें कि बंद चीनी मिल की स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष : माननीय सिद्दिकी जी, इस सदन में कौन माननीय सदस्य पहले क्या-क्या बोल चुके हैं उसका हिसाब तो अब होना नहीं है, यहां तो होना है कि अभी क्या होना है ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिद्दिकी जी कह रहे हैं कि बिहार में बहार है उस बहार में डेढ़ साल आप भी हिस्सेदार थे, अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री ने बड़ा स्पष्ट किया है कि सरकार किसी राज्य में उद्योग नही खोलती है, न उद्योग चलाती है । 2005 में सरकार बनने के बाद एस.बी.आई. कैपिटल्स को यह जिम्मेवारी दी गई कि बंद पड़ी सारी चीनी मिलों का सम्पत्ति का आकलन कर वो उसका विज्ञापन निकालें और पांच बार विज्ञापन निकाला गया और उसके बावजूद केवल दो-तीन चीनी मिल में लोग आये बाकी किसी में लोग नहीं आये । और अब राज्य सरकार नहीं आये यह तो हमने नीति बनाई अब नहीं आये(व्यवधान) में आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय अगर सिद्दिकी साहब और अन्य कोई इन्भेस्टर को लेकर आयें तो राज्य सरकार इसको पूरी मदद करेगी । आप ही किसी इन्भेस्टर को लेकर आइये । अब राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय यह लिया है कि जो बंद चीनी मिलों की जमीन है उसको हम बियाडा के माध्यम से अन्य उद्योग प्रारम्भ करने की दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर आपके पास

कोई इन्भेस्टर है तो लेकर आइये आप । आपको किसने मना किया ? आप लेकर आइये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आगे बढ़ने दीजिये, आगे भी प्रश्न है । आपका नहीं है क्या ? आगे चलने दीजिये, और लोगों का प्रश्न है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1004 (डॉ0(मो0) जावेद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखण्ड के छत्तरगाछ स्थित पश्चिम के कुरसाकांटा आदिवासी टोला कब्रिस्तान एवं कोल्था प0 के गुंवावाड़ी आदिवासी टोला अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु तैयार जिला के प्राथमिकता सूची में क्रमांक 115, 113 पर अंकित है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक 99 तक के कब्रिस्तान की घेराबंदी की कार्रवाई की जा रही है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिक निर्धारित की जाती है । इसी क्रमबद्ध तरीके से कब्रिस्तान की घेराबन्दी किये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कंडिका 6(3),(4) में कब्रिस्तान घेराबन्दी की योजना शामिल किया गया है ।

(राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य अभी भी सभा के वेल में थे ।)

(सदन में व्यवधान जारी)

डॉ0(मो0) जावेद : अध्यक्ष महादेय, जैसा कि मेरे प्रश्न में साफ लिखा गया है कि छत्रगाछ पंचायत के .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपनी-अपनी जगह पर चले जाइये ।

डॉ0(मो0) जावेद : अध्यक्ष महोदय, छत्तरगाछ पश्चिम के कुरसाकॉटा आदिवासी टोला कब्रिस्तान एवं कोल्था पश्चिम के गुवावाड़ी आदिवासी टोला कब्रिस्तान सर यह आदिवासी टोला को जहन में रखते हुये मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूँ कि आदिवासी जो समाज है वह सुअर पालन करती है सर, और चूंकि कब्रिस्तान उसके गांव से सटा हुआ है तो अक्सर सुअर कब्रिस्तान में चला जाता हैं जिससे तनाव अक्सर होता है तो यह सूची जो बनाई है, बनाई है, लेकिन इसको महत्ता को देखते हुये इसकी परेशानी जिनविन है, को देखते हुये इसको शीघातिशीघ्र बनाने का हम रिक्वेस्ट करते हैं और जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री से कि कब तक यह कराना चाहेंगे, थैंक्यू ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने जैसा कहा कि 99 तक की सूची कम्पलिट हो चुका है और यह जो 115 और 113 पर अंकित हैं, साथ ही उस रोज, इसी क्रम में

माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि विधायक फंड से लोग इसको कर सकते हैं, और प्राथमिकता सूची की भी बाध्यता को, उसको हटाकर के केवल सूची में होना चाहिये, विधायक भी अपनी योजना से उस काम को करवा सकते हैं

अध्यक्ष : ठीक ।

(माननीय सदस्यगण वेल से वापस अपने-अपने स्थान पर चले गये)

डॉ0(मो0) जावेद : सर, सर । भईया एक मिनट । सर, गंभीरता को हमने आपके जरिये माननीय मंत्री को बतलाया इन्होंने कहा कि 99 पर है और 113 वां और 115 वां हैं तो सर, ... क्रमशः

टर्न-5/12-03-18/ज्योति

क्रमशः

डा0 मो0 जावेद : जो राशि सरकार ने अब हमारे बी.जे.पी. के साथियों से मिलकर कब्रिस्तान की घेराबंदी का जो फंड है, वह घटा दिया है । अच्छा खासा घटा दिया है, उसमें संभव नहीं है, इसमें तीन चार साल लग जायेगा चूँकि पूरे बिहार के कब्रिस्तान का मसला है। मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 54 सवाल में 40 सवाल, इनके गृह विभाग का है और उस 40 में 24 माननीय विभिन्न सदस्यों के द्वारा कब्रिस्तान घेराबंदी को ले कर है । मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार यह 50 करोड़ रुपया जो सालाना घोषणा की है कि घेराबंदी होगी तो उसमें पाँच साल लग जायेंगे, क्या इसको बढ़ा कर इसको प्राथमिकता के आधार पर कराना चाहती है ?

अध्यक्ष : सरकार ने तो उपलब्ध राशि का वौल्यूम बढ़ा ही दिया है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसी की अर्जेन्सी को देखते हुए कि माननीय सदस्यों का जो डिमान्ड है कि विधायक फंड में भी इनक्लुड किया है, वह भी सरकारी फंड है।

(व्यवधान)

सुन तो लीजिये करिये जो करना है । आप जो कहियेगा वही नहीं जवाब होगा जवाब सुनिये । विधायक फंड भी लगभग महोदय, 318 गुणा दो कहिये और उसको पाँच गुणा करिये तो सवा तीन करोड़ से ज्यादा का फंड हो जाता है, यह कोई मामूली राशि नहीं है ।

डा0 मो0 जावेद : महोदय, दो करोड़ में क्या क्या करेंगे विधायक ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 1005 (श्री कुमार सर्वजीत)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 19-01-2018 ई.आई.डी. क्रमशः कालचक्र मैदान के प्रवेश संख्या 05 अद्धविस्फोटक दो महाबोधि सोसायटी औफ इडिया के पूर्व चहारदिवारी के दक्षिण प्रवेश द्वार के दक्षिण पूर्व स्थित

ढेलापेड़ के जड़ के पास से तीन महा बोधि मंदिर परिवार परिसर के उत्तरी चहारदिवरी के गेट नं0 4 के बाहर बरामद किया गया ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 13 में महाबोधि मंदिर में हुई बम विस्फोट की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, फलस्वरुप दिनांक 19-01-18 की घटना में महाबोधि मंदिर सुरक्षित रहा ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2013 की घटना के बाद से महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के कारण जिला पुलिस की सर्तकता तत्परता एवं अन्य एजेन्सियों के सहयोग से महाबोधि परिसर में बरामद बम को ससमय निष्क्रिय कर दिया गया, जिसके कारण कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, 2013 में बम ब्लास्ट हुआ । माननीय मंत्री जी को पता है कि वह विश्व विख्यात मंदिर है और पूरे देश विदेश से लाखों पर्यटक वहाँ पर आते हैं.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, जब 2013 में घटना घटी, वहाँ के मंदिर के सामने 100 दुकानदारों को विस्थापित सरकार ने कर दिया और 100 दुकानदार जो विस्थापित हुए, सरकार उनको अभी स्थापित करना चाहती है कि नहीं चाहती है ? क्योंकि वह जो बेरोजगार लोग हुए, उनके सामने संकट है । दूसरा हमारा सवाल है कि जब 2013 में घटना घटी । अभी 3000 पुलिस कर्मी डियूटी पर थे । सी.सी.टी.वी. कैमरा माननीय अध्यक्ष महोदय, लगाया गया था । सरकार, इसका मतलब उनको बोध गया के प्रति पता नहीं क्या सोच है, सी.सी.टी.वी. कैमरा जहाँ पर लगा, जहाँ देखना था सुरक्षा का, मापदंड वहाँ पर एक भी इनके अधिकारी और सिपाही को डियूटी नहीं दी गयी और 4 घंटा आतंकवादी घूमता रहा, सी.सी.टी.वी. कैमरा के सामने अगर किसी अधिकारी का इनका डिपूटेशन होता, तो वह व्यक्ति पकडा जाता । अब सुरक्षा के बारे में इनके माध्यम से उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की सुरक्षा का मापदंड यह है कि बोध गया के स्थानीय लोगों को 3 कि.मी. से रास्ता बंद कर देंगें, तो मंदिर सुरक्षित रहेगा ? ये तीन किलोमीटर से रास्ता इन्होंने बंद किया है । साथ साथ वहाँ पर मस्जिद है । मस्जिद में हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ने जायेंगे कि नहीं ? जब आपने रास्ता बंद कर दिया, तो हमारे मुसलमान भाई वहाँ नमाज पढ़ने कैसे जायेंगे ?

अध्यक्ष : आपके प्रश्न में तो रास्ता बंद करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री कुमार सर्वजीत : सरकार को यह मालूम है महोदय ?

अध्यक्ष : कहाँ है प्रश्न ?

श्री कुमार सर्वजीत : यह सुरक्षा का मापदंड माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : आप इसके संबंध में जो सुझाव हैं वह दीजिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिहार ही नहीं भारत की अस्मिता से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है । 2013 में जो घटना घटी, इससे पूरे अन्तर्राष्ट्रीय पर बहुत इसकी चर्चा हुई और यूं कह सकते हैं कि बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए यह मक्का की तरह है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 2013 की घटना के बाद जो राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर जो सुरक्षा की व्यवस्था की गयी, वह क्या पुख्ता व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से अब भी वहॉ बम और दूसरे आतंक में लिप्त लोग पकड़ा रहे हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो जवाब में ही कहा था कि 2013 में घटना घटी और उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गयी इसीलिए 2018 में बम पकड़ लिया गया । वही तो मूल जवाब में कहा है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि 2013 की घटना के बाद सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था वहॉ की गयी ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सबसे प्रोब्लेम तो यह है कि सुनते नहीं हैं लोग । मैंने क्या कहा– दक्षिणी प्रवेश द्वार पर चहारदिवारी के दक्षिणी प्रवेश द्वार के दक्षिणी पूर्व स्थित ढेला पेड़, जंगली पेड़ है महोदय, के जड़ के पास से ये बम बरामद हुआ और सुरक्षा अगर नहीं होती, तो घटनाएं हो सकती थीं । ससमय उसको निष्क्रिय कर दिया गया । यही सुरक्षा व्यवस्था का आकलन है और इसका परिणाम है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सुरक्षा अगर नहीं होती तो तीन बम बरामद कैसे होते ? यह माननीय मंत्री अपने उत्तर में कह रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : हम पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय । 2013 की घटना के बाद भारत सरकार और यू.पी. गवर्नमेंट वहॉ सी.आई.एस.एफ. व्यवस्था करायी । सी.आई.एस.एफ. की व्यवस्था होने के बाद माननीय मंत्री जी यह बतावें कि वहां सुरक्षा के नाम पर वहॉ के लोकल नागरिक को, आम जनता को, जो अभी वहॉ पर दिक्कत हो रही है, उसपर अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय अवधेश बाबू आप भी पुराने सदस्य हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: हैं पुराने ।

अध्यक्ष : ये पूरक सर्वजीत जी ने भी पूछा है । वहॉ के नागरिकों को होने वाली असुविधा का तो जिक्र इस प्रश्न में है नहीं । उसमें जो असुविधा होती है आप दोनों माननीय सदस्य लिखकर दे दीजिये, सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री अवधेश कुमाार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम उसी से रिलेटेड पूछते हैं कि वहॉ पर सी.आई.एस. एफ. के तैनाती के बाद .....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय अवधेश बाबू माननीय मंत्री रहे हैं । जिस दिन की घटना का जिक्र कर रहे हैं । उस दिन मिनिस्टर थे बिहार सरकार में लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि 19-01-18 की घटना है । आप मिनिस्टर थे, उसी जिले के और दूसरी बात महोदय, जब .....

अध्यक्ष : यह कह रहे हैं आप मिनिस्टर थे तो इसमें अजूबा क्या है ? आप थे मिनिस्टर । अब छोड़िये । तारांकित प्रश्न संख्या 1006 श्री फैसल रहमान । चलिए अब आगे बढ़ गया, गृह विभाग ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष : आपको जो सूचना देनी होगी माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा । अब आगे बढ़ गया है । गृह विभाग, श्री फैसल रहमान का जवाब दे दीजिये ।

टर्न-6/12.3.2018/बिपिन

तारांकित प्रश्न संख्या-1006 (श्री फैसल रहमान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी जिलास्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण ने इस जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से वर्त्तमान में संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता सूची तैयार करने का निदेश दिया है । प्राथमिकता सूची में शामिल होने के बाद घेराबंदी कार्य कराया जाएगा । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित किया जाता है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी किए जाने की नीति है । साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत भी इस कार्य को सन्निहित किया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1007 (डॉ0 (मो0) जावेद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज नगर परिषद के वार्ड नं0-1 के मजार चौक में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु जिलास्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक-99 पर और मझिया कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक 175, 169, 332, 339, 351 एवं 262 पर अंकित है। उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक-99 तक के कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य प्रारंभ हो चुका है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक संवेदनशीलता के आधार पर क्रमबद्धता और घेराबंदी कराए जाने की नीति के तहत

कार्रवाई करते हैं । साथ ही, माननीय विधायक योजना में भी इसको शामिल किया गया है ।

डॉ0 (मो0) जावेद : महोदय, माननीय मंत्री सभी कब्रिस्तान घेराबंदी में सुझाव दे रहे हैं कि एम. एल.ए. फंड से कराया जाए । अब दो करोड़ में सालाना में इतनी सारी योजनाएं हैं, कहीं पर नाला बनना है, कहीं पर सड़क बनाना है, बहुत सारी योजना है । आप जानते हैं स्कूल में बिल्डिंग बनाना है, श्मशान घाट भी है, तो फिर यह दो करोड़ में कैसे संभव है ? सर, एक ऑब्जेक्शन है हमारा कि यह जो कमिटी है डी.एम. और एस.पी. का, मेरा सुझाव है कि इसमें वहां के लोकल एम.एल.ए. को जरूर उस कमिटी में रहना चाहिए । ये तीनों मिलकर इसका फैसला करना जरूरी है । यह सुनिश्चित करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी ?

श्री शकील अहमद खाँ: महोदय, कब्रिस्तान के ताल्लुक से वहां पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के डेढ़ साल पहले के भाषण का उद्धरण करना चाहता हूं । आप रेकर्ड देख लीजिए । पूरक पूछ रहा हूं । इस बार जो थर्टी करोड़ का प्रोविजन है ऑनली, वह थर्टी करोड़ के प्रोविजन इस बार शामिल हुए हैं । पिछले से पिछले साल जब मुख्यमंत्री हमलोगों के साथ थे, तो उनका यह बयान है रेकर्ड में कि 'स्काई इज द लिमिट', जितनी जरूरत पड़ेगी, कब्रिस्तान की घेराबंदी जरूरत के आधार पर, जो आपने मानक बनाया है, उसके बुनियाद पर होगा । तो एक साल के अंदर जो यह जेहन की तब्दीली हुई है, उसकी क्या वजह है ?

अध्यक्ष : उनके प्रश्न का जवाब दीजिए । इनका तो प्रश्न था ही नहीं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: दोनों के प्रश्न का जवाब होगा । महोदय, इत्तेफाक से किशनगंज जिले का प्रभारी मंत्री भी मैं ही हूं । माननीय विधायक जब उसकी मीटिंग होगी तो उठावेंगे और इसकी विस्तृत चर्चा करके जितनी अपेक्षा है, उस बात को ध्यान में रखा जाएगा ।

जहां तक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है तो महोदय आप अध्यक्ष हैं, बजट कोई कंस्टिच्युशन नहीं है, कंस्टिच्युशन में भी अमेंडमेंट होता है, सप्लीमेंट्री डिमांड भी जब आगे आएगा तो उसके अनुसार राशि बढ़ती-घटती रहती है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1008 (श्री सुनील कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत् कब्रिस्तान जिलास्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में अंकित नहीं है । उक्त कब्रिस्तान की भूमि पर दो समुदाय के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद या तनाव की स्थिति नहीं है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कमेटी है जो संवेदनशीलता के आधार पर इसका निर्णय करती है ।

श्री सुनील कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि वहां तनाव नहीं है । मैं वहां का एम.एल.ए. हूं । हमको जानकारी है । वहां उस कब्रिस्तान के बगल से रास्ता गुजरती है और पिछली बार वहां रास्ता को लेकर झंझट हो गया था । लोग वहां कब्रिस्तान के बीच होकर रास्ता लगा देते हैं । वहां के लोगों का विरोध था और माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में कहा है वह सही जवाब नहीं बताया गया है और इन्होंने कहा कि प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है तो कब प्राथमिकता सूची में शामिल होगा ? प्राथमिकता सूची जो बन गया है सर, तो प्राथमिकता सूची में इसको शामिल कराइए ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको देखवा लीजिए । ये कह रहे हैं कि वहां तनाव हुआ था ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, यह कॉसेप्ट उचित नहीं है । ठीक ही कहा, वहां चार हजार करोड़ से अधिक पैसे खर्च किए गए हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी पर । पहले यह नीतियां नहीं थी लेकिन यह कहना कि हर कब्रिस्तान का हो, प्राथमिकता उन्हीं की होती है जहां आपस में झगड़े होने की संभावना होती है ।

अध्यक्ष : वही वो कह रहे हैं कि वहां हुआ था ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: जो ये कह रहे हैं कि झगड़ा हुआ है रास्ते के लिए, तो मैं उसको दिखवा लूँगा ।

श्री सुनील कुमार: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब तो कह दिए दिखवा लेंगे । बैठिये ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1009 (श्री अमित कुमार)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, 1-वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत के सुप्पी प्रखंड के सुप्पी, मेजरगंज और बैरगनिया प्रखंड के हिस्से को काटकर बनाया गया है । मेजरगंज सहायक थाना और बैरगनिया सहाययक गंज थाना का सृजन नहीं किया गया है । सुप्पी ओ.पी. कार्यरत है जिसमें मेजरगंज एवं वैरगैनिया प्रखंड का भाग शामिल है ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

3- उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है। वस्तुस्थिति यह है कि सुप्पी प्रखंड अंतर्गत सुप्पी थाना एवं अन्य थाना सृजन की स्वीकति विभागीय अधिसूचना संख्या-3231 दिनांक 11.4.2014 द्वारा प्रदान की गई है । उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित थाना का संचालन थाना भवन के निर्माण होने के पश्चात् प्रारंभ किया जाना है। थाना भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को दिया गया । भूमि उपलब्ध होने पश्चात् थाना भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

श्री अमित कुमार : मैं मंत्री महोदय से पूछना चहाता हूं कि भूमि के लिए दिशा निर्देश दिया गया है लेकिन अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हुआ है तो यह कब तक उपलब्ध करा देंगे, यह भी बताए ।

साथ ही हुजूर, एक क्वेश्चन गन्ना का जो प्रश्न सं0-1003 है जिसपर मैं पूरक पूछना चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पाया । मैं गन्ना मंत्री से भी यह पूछना चाहता हूं कि जो मिल बंद है उसके लिए नहीं, जो मिल चालू है और बंद के कगार पर है, किसान का भुगतान नहीं हो रहा है तो उसके लिए मंत्री कुछ कर रहे हैं कि नहीं, यह भी दिशा निर्देश दे दिया जाए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसको लिखकर भिजवा दीजिए । इसको हम एक्जामीन करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-990 (श्री (मो0) तौसीफ आलम)

अध्यक्षः माननीय रामदेव राय जी अधिकृत हैं । पूछिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के गुआबाड़ी पंचायत के ग्राम डुवाडांगी (जयनगर) कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिलास्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक-526 पर अंकित है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक 99 तक अंकित कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य प्रारंभ हो चुका है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराए जाने की नीति है । साथ ही, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत भी संशोधित मार्गदर्शिका में इसको शामिल किया गया है ।

श्री रामदेव राय : महोदय, यह तो बाद में संशोधन हुआ है और इतने दिन से लंबित है जहां कई बार तनाव हुआ है । लोगों का आवागमन उस होकर जाना बंद था और वहां सरकार इतना संवेदनशील प्रश्न को इतनी सहजता से ले रही है, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है और यह तो जानते ही हैं कि यह क्षेत्र उसी तरह का है जहां हमेशा किसी-न-किसी तरह का झंझट होता ही रहता है, तो इसलिए सरकार से आग्रह है कि प्राथमिकता के आधार पर इसको बनवा दीजिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं ।

टर्न-07/कृष्ण/12.03.2018

कार्य स्थगन सूचना

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 12 मार्च, 2018 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहला, श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ और दूसरा, श्री मो0 नेमतुल्लाह ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण उक्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

अब तो अमान्य हो गया । क्या है ?

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, पिछले दिनों से लगातार सदन नहीं था, उसके दो दिन पहले जिस तरह से पटना शहर में दिन-दहाड़े हत्या का दौर गुजर रहा है, दीघा घाट पर जिस तरह से लोगों ने हत्या की और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, चारो तरफ अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है । तो क्या अपराध का ग्राफ बढ़ता रहेगा ? आम लोग कैसे सुरक्षित रहेगा महोदय ?

अध्यक्ष : गृह विभाग से जुड़ा मामला है । अभी गृह विभाग की मांग भी आनी बाकी है ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, गृह विभाग के प्रभारी मंत्री यहीं मौजूद हैं । चारों तरफ स्थिति खराब है, चिन्ताजनक है महोदय । आम लोग सुरक्षित नहीं हैं ।

शून्यकाल

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी में माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा यात्रा के दौरान मिलने का प्रयास करनेवाले मुखिया संघ एवं शिक्षक संघ के निर्दोष लोगों पर प्रशासन द्वारा केस कर दिया गया जिससे जनाक्रोश है ।

अत: निर्दोष व्यक्तियों पर हुये केस को वापस लेने की मांग करता हूं।

श्री मो0 नेमतुल्ला : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला के मांझा, बरौली, कुचायकोट एवं सदर प्रखंड गोपालगंज, अंचल कलाम रॉहनिया, विश्वम्भरापुर, खरगौली में वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 में गडण्की नदी में कटावरोधी कार्य अपूर्ण एवं दोषपूर्ण रहने के कारण बाढ़ में हजारो परिवार को मवेशी सहित विस्थापित होना पड़ा ।

अतएव पुल-पुलिया का निर्माण कराया जाय ।

डा0 विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्र्गत एन0एच-2 के किनारे अवस्थित अनुमण्डलीय अस्पताल शेरघाटी में आधुनिक सर्जरी सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण दुर्घटना में घायल मरीजों को इलाज में कठिनाई होाती है ।

जनहित में अनुमण्डलीय अस्पताल शेरघाटी में अविलंब आधुनिक सर्जरी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनियां के मसहा आलम पंचायत में बाढ़ से किसानों के सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि में बालू भर जाने के कारण किसान त्राहिमाम् कर रहें हैं । किसानहित में आपदा मुआवजा का भुगतान करायी जाय ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत रामपुर प्रखंड के सोन उच्च स्तरीय नहर के 84 आर0डी0 - थिलोई पथ से भलुऑ गांव तक पहुंच पथ कच्ची है । आवागमन बाधित है ।

सरकार से मांग करते हैं कि उक्त पथ को पक्कीकरण करावे ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिलान्र्गत करायपरशुराय प्रखंड के कराय से सतरजाबाद होतु झरहापा, किश्तीपुर गोरबिगहा के रास्ते विनसा सलेमपुर तक जानेवाली आर0डब्ल्यू0डी0 सड़क पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त हो चुका है जिसके कारण आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना आमलोगों को करना पड़ रहा है ।

अतः सड़क को बनाने की मांग करता हूं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के रमडीहा ग्राम में दिनांक 09.03.2018 को आकस्मिक आग लगने से 48 परिवार के घर एवं उनलोगों की पूर्ण सम्पत्ति तथा कुछ पशु जलकर राख हो गया ।

जले हुये सभी परिवारों के पुनर्वास तथा पशुओं के लिये मुआवजा हेतु सरकार शीघ्र व्यवस्था करावे ।

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, 22 दिनों से समस्तीपुर के धरनास्थल पर पशुपालकों की तीन सूत्री मांगों के समर्थन में बैठे पशुपालक किसान सेवा संघ के स्थापक श्री बैजनाथ चौधरी का सुध लेने हेतु सरकार अपने किसी सक्षम पदाधिकारी को भेजने एवं उनके वाजिब मांगों पर विचार करने हेतु क्या कोई पहल कर रही है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय,कटिहार नगर थाना कांड संख्या -138/18 में हीरा पन्ना ज्वेलरी दुकान में घटित लूट में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के बावजूद भी लूट की गयी माल की बारामदगी अभी तक नहीं हुई है, न शेष अभियुक्त पकड़े गये हैं ।

अतः अविलंब माल की बरामगदी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी करे ।

डा0 राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय,पूर्वी चम्पारण जिले में विद्युत परियोजना द्वारा काम कर हरे ई0एम0सी0 कंपनी जो अवैध रूप से पैसा का डिमांड करती है । पैसा नहीं देने पर

बिजली का काम रोक दिया जाता है । जैसे- दिलावरपुर, रघुनाथपुर, उ0द0हुसैनी, पूर्वी सुन्दरापुर, द0 भवानीपुर, इन्द्रगाछी चट्टी इत्यादि सरकार कार्रवाई करे ।

ध्यानाकर्षण-सूचनाएं एवं उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, बी0 टी0 एक्ट की धारा 106 एवं 103 ए के अन्तर्गत वाद अभिलेख में पारित अंतिम आदेश के आलोक में अंतिम प्रकाशित खतियानों को संबंधित जिला अभिलेखागारों में जमा किया जा चुका है । ऐसे खतियानों में आज भी कई तरह की त्रुटियां मौजूद है, जिसमें तरमीम दर्ज करने के लिये बड़े पैमाने पर बंदोबस्त पदाधिकारी के पास आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं लेकिन इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है । इसका कारण यह है कि अधिकार वाद अभिलेखों में विषय पत्र संबंधित न्यायालय द्वारा तैयार कर संलग्न नहीं किया गया है । ऐसे मामलों के लिये Technical Manual भाग II के नियम 832 के अनुसार वाद अभिलेख में पारित आदेश के आलोक में विषय पत्र एक सप्ताह के अंदर तैयार किया जाना है एवं वैसे वादों को जिसमें विषय पत्र तैयार कर हस्ताक्षर नहीं किया गया, उसे पारित नहीं माना जायेगा।

अत: अंतिम पारित आदेश के आलोक में अंतिम प्रकाशित खतियान में तरमीम दर्ज करने के लिये जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को मार्गदर्शन निर्गत करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी 38 जिलों में कैडेस्ट्रल भू-सर्वेक्षण का कार्य एवं 16 जिलों में रिविजनल भू-सर्वेक्षण का कार्य बिहार काश्तकारी अधिनियम,1885 के अध्याय-10-धारा 101 से 115 में निहित प्रावधानों के आलोक में संपन्न किया गया है, जिसके आधार पर जमाबंदी पंजी का गठन करते हुए दाखिल खारिज लगान वसूली आदि कार्यों का संपादन किया जा रहा है । बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-103 ए के तहत खतियान का प्रारूप प्रकाशन, उसमें संशोधन एवं उसका अंतिम प्रकाशन किया गया है । खतियान के प्रारूप प्रकाशन की अवधि में प्राप्त दावों एवं आपतत्तियों के आलोक में खतियान में आवश्यक सुधार करते हुये खतियान का प्रकाशन अंतिम रूप से किया गया ।

2. बिहार काश्तकारी अधिनियम,1885 की धारा-106 में निहित प्रावधानों के आलोक में अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान में अंकित प्रविष्टियों के विरूद्ध तीन माह

के अंदर राजस्व अधिकारी के समक्ष दावा एवं आपत्तियां दर्ज की गई, जिसके आलोक में संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात् प्राधिकृत राजस्व अधिकारियों के द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसकी प्रविष्टियां तरमीम के रूप में खतियान में की गई ।

क्रमश :

टर्न-8/सत्येन्द्र/12-3-18

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री (क्रमशः): 3. बिहार राज्य में भू-सर्वेक्षण का कार्य आधुनिक तकनीक से कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष, 2011 में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 प्रभाव में आया । उक्त अधिनियम की धारा-20 में निम्न प्रावधान अंकित किया गया है:-

''बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त हस्तक, 1959 तकनीकी नियमावलियों तथा बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 में अधिकथित सर्वे एवं बंदोबस्त के लिए प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन निर्मित नियमों तथा उसके अधीन बनाये गये हस्तक तथा अधिनियम के प्रावधानों को बनाने के लिए समय समय पर निर्गत मार्गदर्शनों द्वारा यथास्थिति, अवक्रमित, संशोधित या अनुपूरित मानी जायेगी ।''

उपर्युक्त कंडिका-3 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी के न्यायालय में बिहार काश्तकारी अधनियम, 1985 की धारा 106, 108 एवं 108 ए के तहत् अनेकों वाद लंबित पाये जाने के कारण वर्ष 2017 में विभागीय अधिसूचना संख्या-21/2017-7225, दिनांक 1-9-17 के द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 में आवश्यक संशोधन करते हुए यह प्रावधान अंकित किया गया है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-106 एवं 108 के तहत दायर वाद जो सुनवाई एवं अंतिम आदेश हेतु लंबित है, का निष्पादन 12 माह की अवधि में किया जाय । उसी प्रकार उक्त संशोधन के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-108 ए के तहत दायर वादों का निष्पादन अधिसूचना निर्गत होने के 120 कार्यदिवस की अवधि में किया जाय । उक्त संशोधन के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 में निहित प्रावधान अवक्रमित हो चुके हैं, जिसके कारण उक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई नया आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा और न ही कोई वाद प्रारम्भ किया जायेगा । बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-20 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य के सभी जिलों में भू-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रारम्भ किया गया है । वर्त्तमान में राज्य के 13 जिलों यथा-बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णियां एवं खगड़िया में

प्राथमिकता के आधार पर भू-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। चूंकि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-20 के तहत भू-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से संबंधित तकनीकी नियमावली अप्रभावित घोषित किया जा चुका है । अतः उक्त तकनीकी नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में भू-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से संबंधित अग्रेतर कोई भी कार्य किया जाना नियमानुकूल नहीं होगा ।

अध्यक्षः पूरक की हिम्मत बचा हुई है ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः महोदय, विभाग ने माननीय मंत्री जी को पूरा विस्तार से उत्तर दिया है । अब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि भूमि सर्वे के दौरान कतिपय मामले में जमीन किसी की और वह जमीन खतियान में किसी पर दर्ज हो जाता है । ऐसा अमूमन होता है, जानबूझकर भी होता है और कभी कभी कार्यालय की गलती से भी होता है । जमीन के मालिक को जो प्रावधान किया गया है बिहार टेडेंसी ऐक्ट के सुसंगत धारा के अन्तर्गत, भू-बंदोबस्त पदाधिकारी के यहां वाद दायर करना पड़ता है और भू-बंदोबस्त पदाधिकारी, वह उसका निष्पादन भी करता है और निर्णय भी देता है मगर उसमें प्रावधान ऐसा है कि भू-धारी जिला भू-बंदोबस्त पदाधिकारी के यहां अनेकों वाद दायर करते हैं प्रावधानानुसार, अंतिम आदेश भी पारित हो जाता है मगर एक सप्ताह के अन्दर यदि सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होता है तो वह एक तरह से अप्रभावी हो जाता है । इसी आलोक में विभिन्न जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी ने सरकार से 2-3-16 को ही मार्गदर्शन मांगा कि ऐसी स्थिति में आदेश निर्गत होने के बावजूद जो हस्ताक्षर नहीं होता है, इससे बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं इसमें सरकार का निर्देश चाहिए क्या करना है, तो अब जो आदेश हो गया और उसका कोई एक सप्ताह में निकला नहीं तो उससे न्यायालय के आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता है , यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के इस ध्यानाकर्षण में दो ही बात का जिक्र है, एक तो है कि खतियान में जो भी दर्ज जिस रूप में है, उस पर जो लोग परिवाद करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, जो कंपिटेंट अधिकारी हैं वे जांच कर के जो अपना फैसला देते हैं, उस हिसाब से खतियान में समय पर तरमीम नहीं होता है । दूसरी बात इन्होंने एक विषय पत्र की चर्चा की है, शायद संबंधित अधिकारी को एक विषय पत्र देना होता है जो नहीं देने के कारण ये सब होता है । उस संबंध में अगर है तो है, नहीं तो माननीय सदस्य का तो बड़ा रचनात्मक सुझाव है, उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ।

श्री रामनारायण मंडल, मंत्रीः माननीय सदस्य, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी साहब काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और मैंने भी इनके प्रश्नों को बड़ा ही गंभीरता से लिया है, इसमें समय सीमा अवधि का भी जिक्र उत्तर में हमने दिया है । अगर उस समय सीमा का ध्यान रखा गया होगा तो निश्चित रूप से उसका निष्पादन भी होगा और उन्होंने जो अपनी बात कही है और

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निर्देशित हुआ है तो उन आपत्तियों को जहां सुधार करने की जरूरत होगी, उन आपत्तियों को नियमानुकूल हम सुधार करने की दिशा में कार्रवाई करेंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताया कि विभिन्न जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है और यह मार्गदर्शन कोई एक महीना, दो महीना नहीं, बल्कि 2-3-16 को ही मांगा और 2-3-16 से यह मामला पड़ा हुआ है । मान लीजिये महोदय, हमारी जमीन है और गलती से चढ़ गया दूसरे के खतियान में और फिर न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया और एक सप्ताह के अन्दर अगर उसमें सुधार नहीं होता है तो उस निर्णय का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रभावित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल रहा है । मैं एक पारा पढ़कर सिर्फ आपको बतला देता हूँ महोदय कि बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि उपर्युक्त परिस्थिति में वैसे स्वीकृत वाद अभिलेखों का वर्त्तमान में विपत्र तैयार कर अंतिम प्रकाशित खतियान में तरमीम वर्ष किया जाना नियमानुकूल होगा या नहीं? यही पूछा है, मार्गदर्शन मांगा लै लेकिन वह तीन साल से सचिवालय में पेंडिंग है ।

अध्यक्ष: इसको माननीय मंत्री जी दिखवा लीजिये । इस पत्र का जवाब मुख्यालय से गया है कि नहीं संबंधित बंदोबस्त पदाधिकारियों को ।

श्री रामनारायण मंडल,मंत्री: ठीक है ।

टर्न-9/मधुप/12.03.2018

सर्वश्री संजीव चौरसिया, संजय सरावगी एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [कृषि विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग] की ओर से वक्तव्य।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, बिहार के 17 जिलों यथा दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सुपौल, पूर्णिया, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद एवं गया जिले के लगभग 20 लाख की आबादी पान खेती पर निर्भर है । पिछले वर्ष 2017 के शीतलहर के प्रकोप में 80 से 90 प्रतिशत तैयार पान की खड़ी फसल बर्बाद हो गयी जिसका मुआवजा पान किसानों को नहीं मिला । नई खेती मार्च-अप्रैल में तैयार होता है लेकिन इस वर्ष नई खेती तैयार करना तो दूर किसानों को खाने के भी लाले पड़ गये हैं ।

अत: उपरोक्त जिलों के पान किसानों के हुए पान की क्षति का मुआवजा दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री : महोदय, समय चाहिये । वैसे ट्रांसफर हो गया है कृषि विभाग में ।

अध्यक्ष : यह तो कृषि विभाग को प्रेषित भी था । इसलिये स्थगित हुआ, अगली तिथि में कृषि विभाग जवाब देगा ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, इसके कृषि के लिये कृषि का दर्जा मिले यह विषय नहीं था । माननीय मंत्री जी से मेरी इस विषय पर बात हुई थी, यह विषय स्पष्ट रूप से था कि कृषि विभाग की तरफ से सर्वे होकर आपदा विभाग को जाना है ।

मैं यह जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन कृषि विभाग से जिला से संबंधित आकलन होकर आपदा विभाग को आया है या नहीं आया है ? चूंकि यह विषय स्पष्ट रूप से जाना था आपदा विभाग को । यह बातचीत के क्रम में हुआ था जो मिलने गया था डेलिगेशन, उसमें हुआ था कि जिला से एक आकलन करके आपदा विभाग को जाना है । माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आपदा विभाग को विभिन्न जिले से आकलन होकर आया है या नहीं आया है ?

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक बैठक हुई थी 30.03.2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की, उसी में निर्णय हुआ था कि कृषि के क्षति होने पर जो हम सहायता देते हैं उसका पूरा आकलन कृषि विभाग को करना है । कृषि विभाग आकलन करके देगा तब आपदा प्रबंधन विभाग उसको राशि उपलब्ध करायेगा । यही व्यवस्था का उस बैठक में निर्णय हुआ था ।

अध्यक्ष : यह व्यवस्था तो उस बैठक से पहले से लागू है कि अगर किसी कृषि उत्पाद या फसल की क्षति होती है, आपदा प्रबंधन विभाग को फसल क्षति का आकलन करने का तो कोई एपरेटस है नहीं । इसलिये यह व्यवस्था पहले से लागू है कि अगर कोई फसल बर्बाद होती है तो उसकी बर्बादी का आकलन कृषि विभाग ही शुरू से करता है । उसके मुआवजा राशि के बॅटवारे में होता है कि कभी आपदा प्रबंधन विभाग करता है या राशि आपदा प्रबंधन विभाग कृषि विभाग को ही दे देता है तो कृषि विभाग अपने अधिकारियों से कराता है ।

इसमें कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग दोनों समन्वय करके अगली तिथि पर इसका जवाब दीजियेगा ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)

टर्न–10/आजाद/12.03.2018

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज पथ निर्माण विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा :–

राष्ट्रीय जनता दल	–	59 मिनट
जनता दल (युनाइटेड)	–	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	–	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	–	20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	–	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	–	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	–	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	–	02 मिनट
निर्दलीय	–	03 मिनट

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, अपनी मॉंग प्रस्तुत करें ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :–

''पथ निर्माण विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 68,89,12,83,000/– (अड़सठ अरब नवासी करोड़ बारह लाख तिरासी हजार) रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राजेन्द्र कुमार, डा0 मो0 नवाज आलम, श्री महबूब आलम एवं श्री ललित कुमार यादव से

कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं और जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटाई जाय ।''

महोदय, लाचार होकर के ऐसा कर रहा हूँ । नन्द किशोर बाबू पर काफी आस्था थी, चूँकि प्रौढ़ आदमी हैं, अनुभवी भी हैं और हमारे तेजप्रताप से कुछ सीखे भी हैं । सोचे कि ये उसका लाभ लेंगे, लेकिन हमारे यहां एक कहावत है सर, हम उस कास्ट का नाम तो लेंगे नहीं, एक कास्ट है, जिसके घर में शादी होने के बाद, शादी होकर के वह लड़की आती है और उस दिन यदि उसके घर में उसके जजमान में कोई नहीं मरा तो वह कुलक्षणा कहलाती है । उसको घर से निकाल दिया जाता है । अगर कोई मर गया तो उसको विशेष रूप से चुमाया जाता है ।

हुजूर, वैसा ही दुर्भाग्य का दिन आज हमारे लिए है । आज पहला बजट पेश कर रहे हैं इस काल में, यह तो नीतीश बाबू का है लेकिन पीठ पुरायेंगे ये, लेकिन क्या आप सोचे कि आज 11 आदमी मुसरीघरारी में एट ए टाईम काल का शिकार हो गया । यही शुभलक्षणा है, ऐसे शुभलक्षणा पर घर में कौन नहीं रखेगा । भगवान करे कि नीतीश जी इनको बराबर रखें और 4 लाख रू0 का मुआवजा भेजवाना पड़े । इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपसे आशा करता हूँ, क्योंकि मंत्री-मंत्री होते हैं, आज आप मंत्री हुए, कल हो सकता है कि फिर दूसरे मंत्री हों, तीसरे हों और जब एक मंत्री चले जाते हैं तो दूसरे मंत्री की जवाबदेही होती है, नैतिक जवाबदेही होती है कि उस मंत्री जी के आश्वासन को, उसके क्रियाकलाप को, उसके कार्यक्रम को पूरा करवाये । हुजूर, जो मैं देखा हूँ कम समय में चूँकि मेरे पास कम समय है, मेरे और साथी इसपर बोलेंगे तो मैं यह देखा हूँ, मैंने पिछले 3 वर्षों का बजट भाषण पढ़ा हूँ, सुना हूँ, एक ही बात है, एक ही बात इसके निष्कर्ष में है । आप बजट तो पेश कर दिये, 2017-18 का बजट 66 अरब 35 करोड़ 90 लाख, 2016-17 का 65 अरब 97 करोड़ और 2018-19 का 68 अरब 89 करोड़, इसमें कौन अन्तर पड़ा, लगभग एक करोड़ का अन्तर बताकर आप डिंग मारते हैं, पीठ-पीठ थपथपाते हैं और आपका खर्चा कितना होता है, 50 से 60 प्रतिशत भी आपका बजट का पैसा श्रीमान् आपका खर्च नहीं हो पाता है । बिहार का गरीब राज्य के विकास के लिए आप भी प्रतिबद्ध हैं और सारे महागठबंधन के लोग भी प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध होना ही होगा, लाचारी हैं उनकी, जब इसमें हमलोग साथ-साथ हैं तो पैसा क्यों नहीं खर्च होते हैं । इसका क्या कारण है, इसका मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है और मैं नहीं समझता हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसके

संबंध में टिप्पणी दी जाती है, स्पष्ट रूप से टिप्पणी आनी चाहिए कि पैसा हम किस कारण से खर्च नहीं किये और यही बात बताया जाय । इनका सबसे बड़ा श्रोत मैं समझता हूँ सर कि अभी ये जेनरल मोड बनाये हैं, जेनरल विजन बनाये हैं 2020 जेनरल मोड कि हम सम्पूर्ण बिहार को 5 घंटा में ले आयेंगे यानी बिहार को नन्द किशोर बाबू, आप 5 घंटा में ही ले आयेंगे । लेकिन इनको पता है कि अपना घर जाते होंगे पटना से पटनासिटी तो उनको वही 5 घंटा समय लगता होगा । यह तो इनको ख्याल नहीं रहता होगा कि क्योंकि इनके पीछे सिपाही और आगे सिपाही रहता है और सलाम करने वाले लोग मिलते ही होंगे । ये तो कभी उतरकर चलकर देखें नहीं कि क्या हालात है बिहार की और अगर इन हालात को आप देखना चाहेंगे तो थोड़ा और दूर चलें । पटना हमारी राजधानी है, यह बढ़े और विकसित हो, यह सब चाहेगा, मैं भी चाहूँगा, सबको चाहना है मगर आपकी किताब मैंने जो देखी है, उसमें हुजूर केवल पटना का ही नाम है, केवल पटना का ही नाम है । नन्दकिशोर बाबू के घर के चारों तरफ केवल पटना ही पटना है और दूसरे जगह सुपौल चला गया, बांका चला गया, नालन्दा चला गया .....

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : माननीय सदस्य रामदेव बाबू, चश्मा लगाकर पढ़ते हैं, विद्वान आदमी हैं, तब आप काहे ऐसा बोलते हैं ?

श्री रामदेव राय : हम बोलते कुछ नहीं हैं, हम तो आपके ही लिए, आपके प्रशंसा के लिए, आपके यश के लिए मैं चिन्तित हूँ । कम से कम नीतीश बाबू के राज में आप भी तो लाभ ले लीजिए, वह लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं । कभी-कभी तो लोग जतियारी करता ही न है, कभी आप हमसे भी जतियारी करने के लिए आईयेगा ही । खैर जब हमलोग शासन में आयेंगे तब आईयेगा न सीट पर तो उसी तरह से हम यह कहना चाहते हैं हुजूर कि थोड़ा सा इसपर ध्यान दिया जाय क्योंकि रोड के मामले में बिहार ऊँचाई पर आया है, यह कोई शक नहीं है, हम इसको बेशक स्वीकार करेंगे । लेकिन जो गुणवत्ता उसमें होनी चाहिए, उसमें जो गति से काम होना चाहिए, उसमें काफी अन्देशा है । या तो आप आपके अभियंतागण उसपर केयरफुल नहीं है या उनपर आपका नियंत्रण नहीं है या वो दक्ष नहीं हैं । पिछली बार तो मैंने देखा था कि मंत्री लोग कुछ पश्चिमी देश का भ्रमण भी किये थे तेजस्वी जी और अच्छे-अच्छे इंजीनियर को लेकर के तो मुझे लगा था कि वे लोग नये टेकनिक से आयेंगे और बिहार में नई टेकनिक से काम करेंगे । लेकिन आप तो काम होने ही नहीं दिये ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : आप कहियेगा तो हम भी हो आयेंगे ।

श्री रामदेव राय : कोई बात नहीं, आप भी जाईए, आपको थोड़े रोकेंगे । आप जैसे थोड़े हैं कि आपको रोकेंगे । तेजस्वी जी तो तेज हैं, आपको मौका दिये हैं, इसीलिए मैंने कहा । ये दो-चार काम मैं पढ़ा हूँ उनके किताब का तो हमको अच्छा लगा कि अपने इंजीनियर को बाहर ले जाकर के नये टेकनिक का ज्ञान दिलाये, प्रशिक्षण दिलवाने का काम किये,

तेजस्वी जी टूर किये, यह अच्छी बात है, आप भी कीजिए । हमलोग इसका स्वागत करेंगे । उस गुणवत्ता के साथ हमारे बिहार में सड़क का काम होना चाहिए । आप देख लीजिए एक मिनट में । ..... क्रमशः .....

टर्न–11/अंजनी/दि0 12.03.18

श्री रामदेव राय : क्रमशः.... आप सात घंटे में छोड़ दीजिए पहुंचना, 6 घंटे में छोड़ दीजिए पहुंचना, पांच घंटे में लाना है, हम इस पर कोई तंज नहीं कसेंगे । आपको जितना मिनट में लाना हो, लाइए, अगर आप चाहिएगा तो पांच मिनट में सम्पूर्ण बिहार से यहां ले आ सकते हैं। आप ऊपर से ऊपर ले जाइए न, ऊपर–ऊपर रोड बना लीजिए न, हवाई रोड बना लीजिए और यहां चले आइए लेकिन आप चलिए अभी, जहां–जहां आपकी नयी सड़कें बनी हैं, वह आप देख लीजिए और आपका यह विजन था कि डेढ़ लेन वाले उच्च पथ को दो लेन, एक लेन वाले पथों का इंटरमीडिएट ऐट एफ लेन 550 मीटर । विभागीय पथों पर संकीर्ण एवं जर्जर पुलों का नये आर0सी0सी0 पुल–पुलिया के प्रतिष्ठान एवं राज्य के पर्यटन सांस्कृतिक महत्व, कृषि उत्पादन क्षेत्र तक जाने के लिए और रोड के कनेक्टिविटी को बढ़ाना है । लेकिन हुजूर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप इसकी जांच करायेंगे तो अभी आपके राज्य में लगभग 15 प्रतिशत सड़कें एन0एच0 एक लेन का है 15 प्रतिशत और दो लेन का भी सड़क है, उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है । एक ओर आप मरम्मत कराते हैं और दूसरी ओर वह सड़क फिर टूटती चली जा रही है। जिसके चलते सरकार की बदनामी, समय की बर्बादी और आर्थिक नुकसान होता है, बिहार का आर्थिक नुकसान हो, हम और आप दोनों मिलकर देखते रहे तो निश्चित रूप से कभी इतिहास माफ नहीं करेगा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ । इसके पहले हमलोग जानते थे कि 54 स्टेट हाई–वे एवं एम0डी0आर0 की राशि उच्च पथ में उत्क्रमित हेतु प्रस्ताव मंत्रालय को गया था और उसके लिए हमारे पूर्व के पथ निर्माण मंत्री माननीय तेजस्वी जी को भी जाना पड़ा था मंत्री जी के पास और मंत्री जी उनका अच्छा से स्वागत किये, उनकी बात को माने और कुछ काम भी किये लेकिन क्या हुआ, इसको देख लीजिए तो ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय,श्री मो0 इलियास हुसैन ने आसन ग्रहण किया)

12 पथों को अब तक राष्ट्रीय पथों में अभी तक उत्क्रमित किया जा चुका है और 42 अभी तक बाकी हैं मेरे ख्याल से ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य आपका समय पूरा हो गया ।

श्री रामदेव राय : कैसे ?

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): आपको दस मिनट है, आप खत्म कीजिए कृपया ।

श्री रामदेव राय : 20 मिनट न मुझको समय है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): और अन्य मेम्बरों को दिया गया है ।

श्री रामदेव राय : दो मिनट समय आप ले लिए जो ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : वह तो स्पीकर साहेब जानें ।

श्री रामदेव राय : मैं खत्म ही कर रहा हूँ । समय कम है तो असली बात हम कह ही नहीं पायेंगे । तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी सड़क में डेवलपमेंट होता है, अगर उसकी जानकारी पहले मेम्बर को दे दिया जाय तो मेम्बर भी अपने स्तर से उसका सही ढंग से परीक्षण ले लेंगे । (व्यवधान) हमारा तो आप दीजियेगा न, हमारा दीजिए चाहे नहीं दीजिए....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया शांति, वाद-विवाद नहीं, आप समाप्त कीजिए ।

श्री रामदेव राय : हमारा दीजिए या न दीजिए, मुझे इससे परेशानी नहीं है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य राष्ट्रीय जनता दल, जनाब ललित कुमार यादव जी ।

श्री रामदेव राय : सर, आपको एक मिनट समय देना होगा । अपने क्षेत्र की एक-दो महत्वपूर्ण बात है, मैं कहना चाहता हूँ । इसी सदन में हमारे मंत्री आश्वासन दिये थे कॉल एटेंशन पर, मेरे क्षेत्र में रूदौली बलान नदी पुल पड़ता है, मंत्री जी स्पष्ट आदेश दिये थे कि चाहे जैसे भी होगा, इस पुल को हम बनवा देंगे लेकिन दो वर्ष हो गये लेकिन इसको कोई देखनेवाला नहीं है । हुजूर, हमारे क्षेत्र में मंसूरचक से लेकर भगवानपुर तक 14 किलोमीटर तक सड़क पांच फीट का है, पी0डब्लू0डी0 की सड़क है, पांच फीट से भी छोटी सड़क है, मंत्री जी को लिखते-लिखते, सरकार को लिखते-लिखते बेदम हैं, वह पांच किलोमीटर सड़क, छः किलोमीटर सड़क में बदल नहीं सकती है ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया शांति । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी, आपका समय 20 मिनट है ।

श्री रामदेव राय : महोदय....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य खड़े हो गये, कृपया आप बैठ जाइए । आप बोलिए ।

श्री ललित कुमार यादव : सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2018-19 के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और सरकार के द्वारा जो मांग प्रस्ताव है, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ । सभापति महोदय, पथ निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा हो रही है और राज्य के पथ, जिस राज्य का पथ विकसित नहीं होगा, न सामाजिक क्षेत्र में उस राज्य की बढ़ोत्तरी हो सकती है, न आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है और न औद्योगिक क्षेत्र

में हो सकता है । पथ निर्माण विभाग का जो वर्त्तमान नीति है और मुझे लगता है कि पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर बाबू बड़े लम्बे अनुभव, मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में इधर 12-13 साल से ज्यादा लम्बा समय इन्हीं का कार्यकाल रहा है तो पथ की अच्छा स्थिति क्यों नहीं है, इन्हीं को बताना चाहिए । महोदय, हमलोग उत्तर बिहार से आते हैं और गांधी सेतु पुल की चर्चा नहीं करें तो यह बेमानी होगी । हम गांधी सेतु पर, यदि उत्तर बिहार से आते हैं, तमाम जितने जिला हैं, कितना घंटा लग जायेगा पटना तक आने में, जितना समय गांधी सेतु तक आने में लगता है, उतना समय गांधी सेतु से पटना आने में लग जायेगा । महोदय, दो पीपा पुल का निर्माण होना था, गांधी सेतु की स्थिति जर्जर है, कब से निर्माण हो रहा होगा और कब पूरा होगा, यह कहना मुश्किल है। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय जी कोई समय-सीमा बतायें कि कब गांधी सेतु का निर्माण करायेंगे ?

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि कृपया शांत रहें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कच्ची दरगाह से विदुपुर, यह भी उत्तर बिहार को जोड़ती है और दूसरा पीपा पुल, एक पीपा पुल तो चालू है महोदय, दूसरा पीपा पुल भी चालू होना था, शायद लक्ष्य था 28 फरवरी तक, क्या हुआ उसका, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बतायेंगे । इतना बड़ा घोर बेमानी उत्तर बिहार और बिहार के लोगों को जो पटना राजधानी आना चाहते हैं, उनके लिए है । महोदय, आज पथ निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आप कितना खर्च कर पाये हैं ? पिछले ही साल कितना खर्च कर पाये हैं, बालू का अभाव, गिट्टी का अभाव तो ये कहां से पथ का निर्माण करा पायेंगे, किस बल पर पथ का निर्माण करा पायेंगे ? ये गुणवत्ता के साथ कहते हैं कि पथ का निर्माण करायेंगे । हर राज्य सरकार का, जो भी सरकार होगी, उसका दायित्व है कि वित्तीय प्रबंधन अच्छा हो, बजट प्रस्तुत करना उनका दायित्व है लेकिन बजट प्रस्तुत करके सही ढंग से उसका वित्तीय प्रबंधन हो और जो खर्च हो रहा है, वह अनुशासित ढंग से हो । महोदय, पथ निर्माण विभाग ने, माननीय पूर्व पथ निर्माण मंत्री, तेजस्वी जी के समय में मेगा प्रोजेक्ट करने की नियत तिथि पर ही प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता था और उसी समय उद्घाटन की तिथि भी तय हो जाता था, जिससे होता था कि संवेदक पर या विभाग पर यह प्रेसर रहता था कि समय सीमा पर शिलान्यास हुआ है तो उद्घाटन भी नियत समय पर होगा । आज आपके पास बालू है नहीं, गिट्टी है नहीं, तो आपकी क्या नीति है, आप कैसे विकसित राज्य बनाना चाहते हैं...

(व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सदन में सबसे बुजुर्ग आप हैं, बुजुर्गों को समझाना बड़ा मुश्किल है, Please

don't mind. न जाने किस वेश में बाबा मिल जाये भगवान रे, ये तकरीर कर रहे हैं, इनसे भी कुछ सीखिए । बोलिए, ललित बाबू ।

श्री ललित कुमार यादव : सभापति महोदय, उद्घाटन की भी तिथि घोषित हो जाती थी और समय-सीमा पर सड़क बनती थी तेजस्वी जी के समय में तो उसका एक अच्छा मैसेज जाता था कि समय-सीमा पर काम करना है सरकार की राशि की भी बचत होती थी, अतिरिक्त भार भी विभाग पर नहीं पड़ता था और आज जो निर्माण हो रहा है, निर्माण भी आपको कहने में कोई हिचक नहीं है कि पथ निर्माण विभाग का क्या हाल है ? पथ निर्माण में जो निर्माण कार्य हो रहा है, कभी राजीव गांधी कहते थे कि सौ रूपया में कितना गांव जाता है । आज पथ निर्माण विभाग की स्थिति यही है महोदय । आज एक रोड को हम देखवा देते हैं, जिस रोड को आप देखिए, उसकी क्या गुणवत्ता है महोदय? एक तरफ से रोड बन रहा है और दूसरी तरफ से रोड टूट रहा है । पथ निर्माण मंत्री जी कार्यक्रम रखें...

....क्रमशः...

टर्न/12/शंभु/12.03.18

श्री ललित कुमार यादव : क्रमशः.....हम दरभंगा बिजली गुमटी से लेकर तारसराय मुरिया राजे तक पथ बना है । महोदय, हम अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे- अगले साल सड़क बनी फिर इस साल सड़क बन रही है। मैंने पूछा क्यों बना रहो हो जी तो टूट गया था इसीलिए- हमने कहा टूट गया था यह तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन साल ही में रोड बनाना जरूरी है । आपका क्या इंजीनियर है, क्या देखकर वहां रोड बनाया । इतनी बड़ी आबादी है मुस्लिमों की तारसराय और मुरिया में 10-10 हजार की आबादी है । वहां दो-दो मस्जिद है और एक नाला ड्रेनेज का भी प्रावधान नहीं है । हमलोग दो-दो बार विधान सभा में उठाये और विभागीय प्रधान सचिव को- हमलोग किसी प्रधान सचिव के यहां जाते नहीं हैं, लेकिन व्यक्तिगत जब भी गये कोई भी- आज आपको जवाब देना है, कोई सरकार रहे ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य तल्खी में नहीं आना है । शांति से सब समाधान होगा । एक मिनट अभी गफूर साहब बता रहे थे जब मैं नीचे था कि इसी आशय का एक सवाल किया था उन्होंने वह मस्जिद, नाली और रोड तो कम से कम समय में नन्दकिशोर बाबू ने बना दिया । आप भी दरख्वास्त कीजिए ये भी बनायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कोई भी सरकार आयेगी बजट में प्रावधान है राशि का और राशि अच्छे ढंग से खर्च हो । यह मेरा पैसा नहीं है, आपका नहीं है, माननीय मंत्री जी का नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह पैसा नहीं है । यह पैसा बिहार के गरीब जनता के गाढ़ी कमाई का है और इसकी लूट हो रही है । हमलोग जनप्रतिनिधि हैं और यह सबसे बड़ी राज्य की पंचायत है इस बात को यहां रखना जरूरी है । महोदय, हम रोड का नाम

बताये हैं- अभी तीन-चार महीना भी नहीं हुआ है । वह सड़क दो-दो बार बना, आप जो रोड बनाते हैं उसकी जॉच करते हैं । हमने विधान सभा में क्वेश्चन उठाया । अब कितने संज्ञान में आपको दिया जाय । तीन बार वह रोड बनने के बाद फिर बना है, रोज बनता है टूटता है और भिलेज पोरशन है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां आप क्या बना रहे हैं ब्लैक टॉप । वहां ब्लैक टॉप का क्या औचित्य है ? तीन बार उस रोड को बनाया है क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं किसी पर ? क्यों करियेगा कार्रवाई, कार्रवाई करना संभव नहीं है । महोदय, बोलना और करना दोनों में बहुत अंतर है । हम आपको बताते हैं - ऐसे ऐसे कार्यपालक अभियंता को रखे हुए हैं । आपको नगर विकास गया में ये दरभंगा कार्यपालक अभियंता थे उस समय में नगर विकास के प्रधान सचिव जो वर्तमान में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव हैं । उन्होंने कहा कि ऐसे अनियमितता बरतने वाले कार्यपालक अभियंता पर अविलंब कार्रवाई करें डी0एम0 को और डी0एम0 ने प्रपत्र-क गठित करके भेजा नगर विकास को और नगर विकास ने प्रधान सचिव जो पथ निर्माण के हैं । उन्होंने नगर विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को लिखा कि ऐसे पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता पर अविलंब कार्रवाई करें । फिर वही जब पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव बनते हैं तो कहते हैं कि नगर विकास इसपर निर्णय लेगा । महोदय, कैसे आप सड़क अच्छा बनाइयेगा, किसके बल पर नन्दकिशोर बाबू आप अच्छा सड़क बनाइयेगा । आपका धोय से खुटवारा मोड़ रोड अभी बना है - जाकर देख लीजिए । हम कितना रोड का गिनायेंगे । देखिए रामानुज जी दे रहे हैं 20 ठो- रोड है कि गड्ढा है कि कुऑ है कुछ पता नहीं चल रहा है । यह बोलना नन्दकिशोर बाबू सदन में और इसको इम्प्लीमेंट कराना देखिए उसके विरूद्ध नगर विकास के प्रधान सचिव लिखे हुए हैं पत्र- जो अभी वर्तमान में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव हैं । ऐसे पर अविलंब कार्रवाई कीजिए । पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को देखिए यह पत्र हम आपको सबमिट करते हैं इसको देख लीजिए पथ निर्माण विभाग को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव लिखे हैं । आपको देखिए वहां से डी0एम0 का प्रपत्र-क आया, अब इसके बाद क्या सरकार होती है । उसके बाद दो साल से वह कार्यपालक अभियंता है । कौन कार्रवाई करेगा, कैसे रोड अच्छी बनेगी ? नहीं करियेगा कार्रवाई क्यों- राजीव गांधी जी कहे थे कि सौ रूपया में बहुत कम पैसा गांव तक पहुंचता है। कहां जाता है यह पैसा ? आप कहियेगा कि आपकी रोड अच्छी बन रही है और हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं रोड अच्छी नहीं बन रही है । कितना परसेंट उसमें गायब होता है आप जॉच कीजिए । कौन यह पैसा खा रहा है ? कौन गरीब के गाढ़ी कमाई का राशि खा रहा है ये रूपया ? कहां जा रहा है बिहार से बाहर जा रहा है । बिहार के लोग हमलोग फटेहाल यदि एक गाड़ी पर चढ़ेंगे तो लोग को फाइव स्टार- आप जॉच कीजिए कहां लूटकर बिहार का पैसा जा रहा है ? नन्दकिशोर बाबू, सरकार के साथ इच्छाशक्ति होनी चाहिए । न्याय के साथ हम विकास करेंगे, कहने के लिए तो ठीक है न्याय के साथ विकास करेंगे । हम भी समर्थन करते हैं कि आप न्याय के साथ विकास करिये, लेकिन संभव नहीं है । शक्ति

वही है सरकार को न्याय के साथ विकास करने का । देखिए हम यह डी0एम0 का प्रपत्र-क दे रहे हैं, आपका प्रधान सचिव पथ निर्माण का पत्र दे रहे हैं। इसको महोदय, प्रोसिडिंग का पार्ट बनाया जाय, देखा जाय । आज सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि रोड में कहीं ब्लैक स्पॉट होता है उसको चिन्हित कीजिए, क्यों नहीं करते हैं ? चिन्हित नहीं करते हैं बड़ा-बड़ा गड्ढा हो जाता है और वही रोड मेनटेनेन्स नहीं हो पाता है, पैसा निकल जाता है । आप रोड बना नहीं पाते हैं । आप देखिए जॉच कीजिए, हम प्रमाण देते हैं । हमारे साथ चलिये, जहां चलिये हम दिखा देते हैं अपने क्षेत्र में । महोदय, तो सड़क निर्माण में सुरक्षा मानकों के मोनेटरिंग हेतु रोड शेफ्टी सेल का गठन किया गया, जो अभी निष्क्रिय है । जिसके कारण दुर्घटना भी बढ़ी है और मानक के अनुसार रोड भी नहीं बन रहा है । जो रामदेव बाबू उठा रहे थे । हम कह रहे हैं कि महागठबंधन से अलग होने के बाद कितना गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण आप किये हैं। हमको थोड़ा बताइये, अपने जवाब में आप बतायेंगे । हम गिनती करा देंगे, गिनती को करने में डबल इंजन की सरकार है । डबल इंजन, एक इंजन यहां एक इंजन वहां है और आप अभी नहीं विकास कीजिएगा तो कब कीजिएगा । माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इतना महत्वाकांक्षी हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए । क्यों बिहार का विकास होगा । हमको विशेष पैकेज मिलना चाहिए, बिहार का विकास होगा । अब तो डबल इंजन की सरकार है । अब मांगिये न किसको कह रहे हैं । बिहार की जनता भी देख रही है किसको कह रहे हैं । आप दीजिए डबल इंजन की सरकार है । बिहार की सारी सड़कों को आप बनवा दीजिए । आप 385 जर्जर स्क्रू पाइल को जब तेजस्वी जी मंत्री थे तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम 2018 तक आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करा देंगे । क्या हुआ आपका, कितना आप आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करा दिये ? आप बतायेंगे अपने जवाब में। आप कितने सिंगल लेन को इन्टरमीडियेट लेन में, कितने इन्टरमीडियेट लेन को डबल लेन में - आपको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है एस0एच0 रोड है, एन0एच0 रोड है, सबकी अपनी सीमा है, लेकिन देखिए क्या स्थिति है ? आपको तो अभी तेजस्वी जी थे तो 3630 कि0मी0 एस0एच0, एम0डी0आर0 और एन0एच0 को परिवर्तित करने भारत सरकार के मंत्री गडकरी जी से मिले । अब तो आपके उपर भी हैं, आप नीचे हैं । इसका क्यों नहीं अनुपालन कराते हैं, क्यों नहीं कार्यान्वयन कराते हैं ? महोदय, तेजस्वी जी थे तो उनके समय में वाट्सऐप पर जनता से प्राप्त शिकायत पर ध्यान दिया जाता था । उसका निवारण भी होता था, उसका निदान भी होता था, लेकिन अभी क्या स्थिति है ? यह अभी बतायेंगे । ठीक है जब का हो, लेकिन उसका हमको लग रहा है कि निष्क्रिय है । जब हमलोगों की शिकायत को आप नहीं सुनते हैं तो जनता की शिकायत को कहां से सुनेंगे ? हमलोग आपके विभाग का चक्कर लगाकर विधान सभा में जो-जो मुद्दा बताये हैं एसेम्बली क्वेश्चन करके देख चुके हैं । थक गये हैं, नहीं हो सकता है हमसे, हम सक्षम नहीं हैं । आपके वर्तमान सरकार की व्यवस्था में, जो वर्तमान सरकार की व्यवस्था है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं । सरकार की इच्छाशक्ति नहीं है । न्याय के

साथ विकास का ढोल पीट रही है सरकार । न्याय के साथ विकास नहीं कर रही है । ये सब धोखा है महोदय । आपका एयरपोर्ट एलीवेटेड एक्सप्रेस फॉम बिहटा टू पटना का क्या हुआ, आपका पायलर रोड बोरिंग रोड का क्या हुआ, तेजस्वी जी द्वारा वैशाली कोरिडोर, बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट का कोई प्रगति नहीं दिख रहा है । जो उनके समय में निर्णय लिया गया उसका क्या हुआ ? आप यह थोड़ा बतायेंगे । नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पहले 90 और 10 के अनुपात में राशि दी जाती थी । बिहार राज्य जैसे गरीब राज्य को आप 60 और 40 कर दिये हैं । आप डबल इंजन की सरकार हैं और यह बिहार की जनता को दोहरी मार दे रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न–13/अशोक/12.03.2018

श्री ललित कुमार यादव : क्रमशः ... आपको यह निर्णय करना होगा, आप 90 : 10 उसको 60 : 40 पर अभी वर्त्तमान में ले आयें आप गरीब राज्य जैसा वहन कर पायेगा यह सम्भव नहीं है आप अनुरोध कीजिये, आप डबल इंजन की सरकार हैं, आप केन्द्र में अनुरोध करिये यह गरीब राज्य है, 90:10 का पहले जो मापदण्ड था उसको लावे । और बिहार का कल्याण करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, बिहार में सड़कों के क्षेत्र में आप जाल बिछायेंगा, लेकिन जब आपकी नीति और नीयत, अपका न विजन है और न मीशन है, न नीति है और न नीयत ठीक है तो कहां से बिहार का विकास होगा । कहां से बिहार का विकास होगा, बिहार की जनता के साथ जो धोखा हुआ महोदय, आप इसको भूल नहीं सकते हैं, कहीं पर भी चौक चोराहा पर चर्चा होती है, अब तो डबल इंजन की सरकार है । कैसे पलटी पार कर इधर से उधर गये, कैसे जनता के मैनडेट का अपमान हुआ, जनता सवाल पूछेगी महोदय, जनता बैठी हुई है इंतजार में, समय आने दीजिये, समय पर जवाब आपको इसका मिलेगा लेकिन बिहार का विकास तो करिये । आप जिस कारण से भी डबल इंजन की सरकार बनाये विकास करिये बिहार का, बिहार की जनता विकास चाहती है । महोदय, आपका जमीन अधिग्रहण का जो प्रस्ताव है, अभी जमीन अधिग्रहण का जो प्रस्ताव है उसमें भी सुधार करना होगा । आप की सड़क, जमीन अधिग्रहण के कारण बहुत सी सड़क नहीं बन रही हैं । आपको महोदय, आपको वर्ष 2006 से 2011 तक बीच में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के रख–रखाव पर राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि, 2006–2011 के बीच में महोदय, केन्द्र सरकार के यहां लम्बित है । अब तो डबल इंजन की सरकार है वह तो मंगवा दीजिये, अब क्या दिक्कत है । 2006–2011 तक जो राष्ट्रीय उच्च पथ की मरम्मति में जो रख–रखाव पर जो केन्द्र सरकार का दायित्व है और वह खर्च जब केन्द्र सरकार ने नहीं किया तो वह खर्च बिहार सरकार के स्तर से की गई, वह राशि अभी तक बिहार जैसे गरीब राज्य को नहीं

मिल रहा हैं । अब डबल इंजन की सरकार है चाहिये कि यह राशि लौटा दे बिहार सरकार को ताकि निर्माण कार्य में प्रगति होगी । महोदय, बहुत ऐसी मुद्दे हैं, आज पथ अधिग्रहण किया जा रहा है महोदय, आज पथ अधिग्रहण किया जा रहा है महोदय क्या हो रहा है? भेद-भाव हो रहा है, हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं । मनिगाछी से धनश्यामपुर सड़क जो 19 कि.मी. की सड़क हैं, जीरो से 19 कि.मी. की सड़क है, जीरो से पांच कि.मी. छोड़ दिया गया और साढ़े पांच से 19 कि.मी. ले लिया गया महोदय, जब सिढ़ी नहीं रहेगा तो हम आगे कैसे जायेंगे ? फोर लेन की तरफ से छोड़ दिया और आगे ले गया । जब कि 2004 का पहली अधिसूचना है, मनिगाछी से घनश्यामपुर, हम अधिसूचना संख्या हम बतला देते हैं, यह अधिसूचन संख्या आपका है और क्रमांक संख्या 63,69,73,77,79,83,85,88 ये पी. डब्लू पथ, धरौरा से मौजमपुर वाजितपुर है, यह धोईघाट से गौसा घाट है और ये एन.एच.-57 से फोर लेन तक को जोड़ती है और ये सब सड़क 2004 में अधिग्रहित है, एन.ओ.सी. भी प्राप्त है । जो सड़क आज उठाया विभाग, जिसको मन में हुआ सो पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर लिया, आप सबसे लम्बा काल रहे हैं मंत्री (व्यवधान)

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, आप बोलते जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : आप सबसे लम्बा काल मंत्री रहे हैं और यह जवाब आप ही को देना होगा, कोई दो दिन के लिये आया, दो महीना के लिये आया उससे हम हिसाब नहीं और सरकार, सरकार होती है, जो वर्त्तमान में बैठी हुई है .....

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): आप अपनी समस्या रखिये, समय बर्बाद हो रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : इस तरह महोदय, पथ निर्माण में 2004 में अधिग्रहण है, क्रमाक संख्या इसका 63,69,73,77,79,83,85,88 ये पी.डब्लू.डी. पथ हम बतलाये महोदय, एन.एच. 57 से गौसा घट से घोई घट पी.डब्ल.डी. सड़क तक, मनीगाछी से धनश्यामपुर तो था अधिगृहित, जीरो से पांच छोड़ दिये और साढ़े पांच से 19 ले लिये। क्या नीति है आपकी, क्या नीति हैं, कहां से, कौन सी नीति है ?

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): आप कृपया समय पर ध्यान दें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप दो मिनट का समय मेरी पार्टी की ओर से बढ़ा दीजिये ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): कोई तुक है क्या ?

श्री ललित कुमार यादव : तुक है महोदय । मैं चीफ व्हीप हूँ । चीफ व्हीप की अनुशंसा पर आसन निर्णय लेता है महोदय । तो मेरी अनुशंसा है, उस पर आप निर्णय लीजिये ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): जब चीफ व्हीप लागू करेंगे तो वह लागू हो जायेगा कि कुछ नियम कायदा है ?

श्री ललित कुमार यादव : नियम है महोदय । नियम के तहत ...

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): बोलिये, बोलिये । आप समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह चिकनी से शिवराम- लुलुआ चौक पथ है महोदय । बाजिपुर देवना पथ भाया कुमरौल तक है, बहेड़ा बाजार से कटवासा पथ है तो यह कहने का मतलब है कि ये 2004 में अधिग्रहण हुआ तो वर्ष 2004 के बाद अभी तक आप कितना रोड अधिग्रहण किये ? सबसे लम्बा काल मंत्री आप रहे हैं, कोई नीति होती है महोदय, कोई विजन होता है, कोई मीशन होता है लेकिन इनका न तो कोई नीति है, न कोई मीशन है और न कोई विजन है । आप 2004 के रोड में अभी तक कार्य प्रारम्भ हुआ ? और आज आप जिस सड़क का मन हुआ ले लेते हैं । आपके अधिसूचना संख्या है, यह मेरा नहीं है, यह आपका ही का अधिसूचना किया हुआ है, इसमें आप पिक एण्ड चूज करके आप ले रहे हैं । महोदय, यह सरकार न्याय के साथ विकास का ढिंढोरा पीट रही है, ये न्याय के साथ विकास नहीं कर रहे हैं।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): अब आप समाप्त करिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, पुनः आपने समय दिया, आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): बेहतर तकरीर, तार्किक भाषण के लिये आपको धन्यवाद । मैं अब आग्रह करूंगा जनता दल(यू0) के माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, आपका समय दस मिनट ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, मैं पथ निर्माण विभाग के वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, वर्त्तमान एवं बदलते बिहार के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक विकास में पथ निर्माण विभाग की भूमिका अग्रणी है । महोदय, पथ निर्माण विभाग उच्च गुणवत्ता एवं त्वरित निर्माण के मूल मंत्र के आधार पर योजनाओं का कार्य कराने पर बल देती है । विगत कई वर्षो में पथ निर्माण विभाग के द्वारा वृहत स्तर पर पुलों एवं पथों का निर्माण किया गया है, सड़कों के रख-रखाव हेतु नये अनुरक्षण नीति के तहत कार्य हो रहा है । महोदय, राज्य में तीव्र गति से आवागमन हो, इसका ध्यान रखा गया है । राज्य के किसी भी हिस्से में माननीय मुख्यमंत्री के अवधारणा के अनुरूप पांच घंटा के अन्दर राजधानी पटना में पहुंचने के लिए विभाग कार्य कर रहा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पथों की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य एवं पुलों का निर्माण किया जा रहा है । महोदय, जहां सघन आबादी है वहां बाईपास एवं एलिवेटेड पथों का निर्माण किया जा रहा है । भारत सरकार के पी.एम. पैकेज में 54 हजार 700 करोड़ की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है । कुछ निविदा पूरी हो गई है, कुछ प्रक्रियाधीन है, कुछ का डी.पी.आर. तैयार हो रहा है । महोदय, राज्य के सभी जिलों को फोर लेन राजधानी की जोड़ने की योजना है और उसी तरह से जिला मुख्यलाय को प्रखण्ड मुख्यालय से जोड़ने की योजना है । महोदय, इस तरह

महोदय, गंगा पथ दीघा एम्स एलिवेटेड रोड, महात्मा गांधी सेतु का जिर्णोधार, फ्लाई ओभर, सिक्स लेन का कार्य, लोहिया पथ चक्र, नदियों पर पुलों का जाल जैसे, गण्डक नदी पर, कोशी नदी पर पर , सोन नदी पर बागमती नदी पर, फल्गु नदी पर कराया जा रहा है । क्रमशः

टर्न-14/12-03-2018/ज्योति

क्रमशः

श्री विरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, पथ निर्माण विभाग की हालत को बेहतरीन रुप से आप जानते हैं। आपके कार्य काल में कुछ पथों का बहुत अच्छी तरह से काम हुआ था लेकिन आज पथ निर्माण विभाग ने पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया है और जिसतरह की सड़क हमारे यहाँ थी जैसे औरंगाबाद से, हमलोग आते थे तो औरंगाबाद से आने में हमको आपके रोड को पकड़ना पड़ता था, आपके बिक्रमगंज -नासरीगंज होकर जाना पड़ता था । आरा होकर आना पड़ता था लेकिन औरंगाबाद से पटना आते थे तो इसतरह के गढ्ढे थे महोदय कि हमको पॉच छः घंटे लगते थे लेकिन आज के दिन में अब औरंगाबाद से पटना दो घंटा से ढाई घंटा मुश्किल से लगता है । यह है पथ निर्माण विभाग की उपलब्धि और पथ निर्माण विभाग द्वारा सारे क्षेत्रों में पुल पुलिया, सड़क का जाल बिछाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री के न्याय के विकास के अनुरुप किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि यह और आगे तीव्र गति से होगा । तीव्र गति से होगा । महोदय, मुझे कम समय है इसलिए मैं, अब माननीय मंत्री जी का ध्यान, अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ । महोदय, हमारी एक सड़क है जो जपला से होकर डिहरी ऑन सोन जाती है कोइरीडीह-तेतरिया होकर बड़ेम होकर, उस सड़क के रास्ते से बारुन से होकर जब माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे थे तो तख्ती लेकर बच्चे लोग खड़े थे और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुछ जो खराब पोरशन था, उस समय उसको तुरत ही पी.सी.सी. में तब्दील किया गया । रोड बनी लेकिन आज जो स्थिति है कोईरीडीह से बड़ेम तक बहुत ही रोड की जर्जर स्थिति है और उसमें बालू तथा गिट्टी लदे हुए ट्रकों की भरमार रहती है, वह आपको झारखण्ड एरिया से बहुत सारे वाहन चलते हैं और उसका इतना लोड है उस सड़क पर कि उसको फोर लेन होना चाहिए । जपला से उधर आपको जो झारखंड एरिया में है, छतरपुर से जपला तक वह आपको फोर लेन हो गया। सड़क के मामले में जो अच्छा बिहार का नजरिया जाता था देश दुनिया में, वह अभी खराब नजर आ रहा है इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करुंगा कि उस सड़क को फोर लेन के रुप में तब्दील करें । उसपर बहुत ज्यादा लोड है और दूसरी चीज एक और मैं कह रहा हूँ कि नवीनगर से कोईरीडीह रोड उसका एक ब्रांच है, नवीनगर से कोईरीडीह, माननीय मंत्री जी की अनुशंसा के आलोक में ही पथ निर्माण विभाग में

लिया गया और निर्माण हुआ लेकिन सिंगल बना है । वह सिंगल रोड में बहुत बालू एवं गिट्टी लदे ट्रक भी गुजर रहे हैं, इसलिए उसको भी डबल करने की कृपा करें और इसके साथ एक सड़क है चतरा-नवीनगर-टण्डवा-हरिहरगंज 53 कि.मी. की सड़क है । यह सड़क दोनों तरफ पथ निर्माण की सड़क स्टेट हाई वे को जोड़ती है इस सड़क को पथ निर्माण विभाग में ले ले इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : भारतीय जनता पार्टी, माननीय सदस्य श्री रामप्रीत पासवान, 5 मिनट ।

श्री रामप्रीत पासवान : 7 मिनट है सभापति महोदय, मेरा समय । सभापति महोदय, विपक्ष के साथियों के द्वारा वर्ष 2018-19 में पेश किए गए पथ निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और माननीय मंत्री जी के पक्ष में भी खड़ा हुआ हूँ । महोदय, किसी राज्य की तरक्की के लिए सड़क का विकास बहुत ही जरुरी है । हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है विकास और सड़क का जाल पूरे राज्य में बिछा है । हमारे माननीय मंत्री पहले भी 2006 में मंत्री बने थे पथ निर्माण विभाग के, जो वर्षों से जर्जर सड़क थी, उसको कोई देखने वाला नहीं था आजादी के बाद और उस सड़क को भी बनाया गया । हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं, इनके समय में गढ्ढे में सड़क थी या सड़क में गढ्ठा था यह लोग स्वतः जानते हैं जब मैं पहली बार विधायक बनकर आया तो मधुवनी से यहाँ आने में 12 घंटा समय लगता था या समस्तीपुर से घूम कर आईये या मुजफ्फरपुर से तो अब मैं आता हूँ तीन घंटे में ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया शांति, माननीय सदस्य पहले कितने मिनट में आते थे?

श्री रामप्रीत पासवान : मिनट में नहीं, पहले 12 घंटे में आते थे मधुबनी से यहाँ, जब गढ्ढे में सड़क थी और सड़क में गढ्ढा ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब कितने में ?

श्री रामप्रीत पासवान : अभी तीन घंटे, साढ़े तीन घंटे में मधुबनी से आते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया सावधानी बरतेंगे दुर्घटना से, जो स्पीड की बढ़ोत्तरी हुई ।

श्री रामप्रीत पासवान : कोई स्पीड नहीं रहती है, वह चालक जानता है कि मुझे गाड़ी कैसे चलाना है । इतनी अच्छी सड़क है । सभापति महोदय, इतनी अच्छी सड़क है कि कटोती प्रस्ताव तो इन लोगों को लाना ही नहीं चाहिए । इन लोगों को तो और उसमें पैसा देना चाहिए कि उनके भी क्षेत्र में भी सड़क बननी है । ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष वालों के क्षेत्र में ही सड़क बनती है । हमारे जो मित्र हैं उनके क्षेत्र में भी सड़क बनती है और सड़क की ऐसी जाल बिछी है । हम अपने प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी

को बधाई देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू हुयी तो गांव गांव टोला टोला में जो कभी लोग कालीकरण नहीं देखा था वह कालीकरण सड़क बनी, अब आपके रिजीम में तो कच्ची और खरंजा था । मेरे रिजीम में कालीकरण सड़क बनी और जो टोला है उस टोला को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने सड़क बनाने का निर्णय लिया है जी.टी.एन.एस.वाय. के तहत और छोटे छोटे टोला में भी मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सड़क बन रही है और पूरे राज्य में यह कालीकरण की सड़क और पी.सी.सी. सड़क का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। आजादी के समय जो लकड़ी का पुल था जो छोटा छोटा पुल था, उस पुल का चौड़ीकरण करके, काठ के पुल को हटाकर आर.सी.सी. पुल बनाया गया और छोटी छोटी नदी पर भी पुल बनाया गया । मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आदरणीय अब तो दुनिया में नहीं हैं पंडित विनोदा नंद झा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं चौथा वर्ग में पढ़ता था उनका शिलान्यास किया हुआ और जब चुनाव होता था तो चुनाव में वहाँ शिलान्यास का बोर्ड लगता था और जब मैं वोट मांगने के लिए गांव में गया तो लोग हमको नदी की तरफ ले जा रहे थे एक लाईन से पाँच शिलान्यास किया हुआ था और किसी ने बनाने का काम नहीं किया था, सूखी साईफन दिखायी दिया और जब 2006 में हमलोगों की सरकार बनी तो हमारे पथ निर्माण मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के चार साल में सह साईफन बना और रोड चालू हुयी । वर्षों लोग नाव पर चलते थे । वहाँ 17 पाया बन कर खड़ा था और 13 पाया बनने के लिए वह पुल पंडित विनोदा नंद झा, आदरणीय मुख्यमंत्री के समय से उस समय तक लंबित था इसीलिए सभापति महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सड़क का जाल बिछा है, हमारे सदस्य ललित बाबू कह रहे थे । उनके समय में जो सड़क बनती थी ये गुणवता की बात करते हैं अभी गुणवतापूर्ण सड़क बनती है और रोड के किनारे टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है और जब टेलीफोन अपने विभाग को करते हैं तो तीन दिन के अंदर में यह एम्बुलेंस गाड़ी जाती है और जहाँ टूटा हुआ है उसकी मरम्मत होती है । मैंने ये भी देखा है और मैं अपने से करवाया हूँ । मैं विधायक हूँ और जब रोड पर चलता हूँ तो यह नंबर मैं देखता हूँ । इनके समय में यह कहाँ व्यवस्था थी । ये लोग बोलते हैं जब उधर चले जाते हैं तो बोलना शुरु करते हैं और इधर आते हैं तो भूल जाते हैं कि सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, गुणवतापूर्ण बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए । ये आप लोग करते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया शांति ।

(व्यवधान)

श्री रामप्रीत पासवान : सभापति महोदय, पिछले दरवाजे से नहीं सीना तान कर आने वाला व्यक्ति हूँ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : विषय पर आईये ।

श्री रामप्रीत पासवान : सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री के नेतृत्व में छपरा शहर से 3.5 कि.मी. लंबी राज डबल फेयर वाईड का निर्माण किया गया है । सरकार द्वारा आरा छपरा के बीच में गंगा नदी पर उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल बन रहा है ।

क्रमशः

टर्न–15/12.3.2018/बिपिन

श्री रामप्रीत पासवानः क्रमशः अब लालबत्ती जल गई । महोदय, हमको दो मिनट का समय दिया जाए ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): पांच से पार कर गए हैं आप ।

श्री रामप्रीत पासवानः जी । मात्र दो मिनट । माननीय मंत्री जी का ध्यान हमारे क्षेत्र में कमला नदी है और एक प्रखंड है अंधराठाढ़ी । अंधराठाढ़ी का दो पंचायत जो नदी के उस पार में है और वहां जाने के लिए लोगों को पच्चीस किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए मोतीपुर से लेकर भगुवार के बीच में कमला नदी पर एक आर.सी.सी. पुल का निर्माण कराया जाए । बहुत ज्यादे पैसे का बजट नहीं होगा और आपने जो मेरे क्षेत्र में आर.डब्लू.डी. सड़क का पथ निर्माण विभाग में जो आपने सम्मिलित किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और सरकार का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): धन्यवाद । शुक्रिया । राष्ट्रीय जनता दल । माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश । आपका समय 13 मिनट ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट कटौती प्रस्ताव के पक्ष में एवं सरकार के माध्यम से जो बजट पेश किया गया है उसके विरूद्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं और दल के प्रति मैं आभारी हूं ।

महोदय, बजट तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पेश किया गया है लेकिन इसका क्या अंजाम है, कितना परिणत हुआ है विकास के रूप में, यह जो बजट है, उसमें वह परिलक्षित नहीं है । महोदय, अंधकार में सबों को, बिहार के लोगों को अंधकार में रखा गया है कि किस तरह से बजट को उस तरह से नहीं किया गया है ।

महोदय, यह जुमलेवाजी वाली सरकार जो है, बहुत मुश्किल से महागठबंधन की सरकार से अलग होकर और जे.डी.यू. के कलेजे पर, अभी माननीय रामप्रीत जी बता रहे थे, विधायक महोदय, कि मैं सीना ठोक करके मैं सरकार में आया हूं यानी जे.डी.यू. के सीने पर चढ़कर...

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): किसने कहा ?

श्री विजय प्रकाशः अभी रामप्रीत जी बोले हैं महोदय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): सीना ठोक कर आया जाता हैं । इतना ही अकल है ? बोलिए।

श्री विजय प्रकाशः महोदय, यह दुर्भाग्य है कि जो जनता का जनमत था, उसको दरकिनार करके आपलोगों ने सत्ता में आने का काम किया, लेकिन आज जो सड़क की हालत है, बहुत ही बुरी स्थिति में सड़क है ...

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया शांति । कृपया शांति ।

श्री विजय प्रकाशः हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव काम किया करते थे । याद है कई पुलों का समय अवधि के अंदर, जो समय अवधि तय किया गया था, उसके अंदर शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया । हम एक छोटा-सा वाक्या माननीय मंत्री जी से कहना चहते हैं । 18 महीने में तेजस्वी यादव ने कई पुलों का शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया लेकिन माननीय पथ निर्माण मंत्री महोदय, आपको याद होगा । पीछे में बैठे हुए हैं लखीसराय के विधायक । जो लखीसराय के बाइपास का पुल बनना था, माननीय मुख्यमंत्री जी एम.पी. चुनाव के पहले जाकर घोषणा किए थे कि आज कौन-सा तारीख है, ठीक अगले वर्ष हम इसी तारीख को आकर उद्घाटन करने का काम करेंगे। यदि यहां पर बैठे हुए विजय जी, उनकी अन्तर्रात्मा, माननीय मुख्यमंत्रीजी का तो अन्तर्रात्मा नहीं जागेगा विकास के लिए, लेकिन विजय जी, आपकी अर्न्तरात्मा जागे कि बताइए कि यह बात सही है या गलत और माननीय मंत्री पथ निर्माण, आप भी अपने अंतर्रात्मा को जगाइए कि क्या कारण है आज लगभग छः साल हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्रीजी के मुँह से निकला हुआ शब्द आज भी झूठा साबित हो रहा है । क्या कारण है कि जिस तरह से भारत में बैठे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जुमलेवाजी करके लोगों को दिग्भ्रमित करके ...

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्रीः महोदय...

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया आपके भाषण से शायद आहत हुए हैं, इनको दो सेकेंड बोलने दीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,मंत्रीः इनको बता दें कि सही बयानवाजी हो और जिसकी चर्चा कर रहे हैं आज उस रोड से ये गुजरते भी हैं और क्यों रूका रहा, इनके जो 18 महीने के शासनकाल में उसका नजरअंदाज किया गया जिसके कारण वो उपेक्षित रहा । आज वह फिर चालू बहुत जल्द होने जा रहा है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): आप बोलिए ।

श्री विजय प्रकाशः माननीय महोदय, यादाश्त कमजोर है उनका । मैंने पुल का चर्चा किया, वे रोड की चर्चा करते हैं । दुर्भाग्य है । दुर्भाग्य है आपका, दुर्भाग्य है, आप बैठ जाइए ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): समय का ध्यान रखिए विजय जी ।

श्री विजय प्रकाशः मैं पुल का चर्चा करता हूं और अमुक आदमी रोड की चर्चा करते हैं लेकिन कहना चाहता हूं कि जिस तरह से घोषणा करने के बाद अमुक कामों को नहीं किया जाता है और आप बजट में पेश करते हैं कि हमलोग ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं ? यह 18 महीने में जितने कामों को, हमें बताएं माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं कि 18 महीने में कम-से-कम दस बार हमारे प्रतिपक्ष के नेता तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री गडकरी साहब से मिलकर कई कार्यों को कराने का काम किया गया और उनसे मांग किया गया जाकर लेकिन आज छः महीना गुजर चुका है, आप कितने बार गडकरी महोदय से मिले होंगे कि राज्य की माली हालत है, राज्य में जो पैसा नहीं है, एक तो आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, स्पेशल पैकेज नहीं दे रहे हैं, कम-से-कम तो रोड में कुछ पैसा दे दीजिए । कितने बार माननीय मंत्रीजी गए हैं ? मंत्रीजी जापान चले गए घूमने के लिए, बहुत अच्छी बात है ...

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया शांति । आपसे में बात न करें ।

श्री विजय प्रकाश : बहुत अच्छी बात है जो माननीय मंत्रीजी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गलबहिया किए और जापान चले गए । हमको शक था, कहीं जिस तरह से फेकूवाज बातों का चर्चा माननीय प्रधानमंत्रीजी करते हैं, जुमलेबाजी का...

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): इधर देखिये । शांति । शांति । कृपया । बोलने दीजिए मंत्रीजी को ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, इस प्रकार के शब्दों का इश्तेमाल नहीं होना चहिए । माननीय प्रधानमंत्रीजी के बारे में इस प्रकार के शब्दों के चयन से परहेज करना चाहिए महोदय । महोदय, मैं एक लाइन इनको कहना चाहता हूं -

'यार, कुछ तो कर आदाबे महफिल का लिहाज,
यार ये पहलू बदलना छोड़ दे ।'

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): शुक्रिया । शुक्रिया । ठंढे दिल से बोलिए समस्या ।

श्री विजय प्रकाशः महोदय, जिस तरह से जुमलेवाजी करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए हैं कि जुमलेवाजी और फेकूवाजी में क्या अंतर हो सकता है । हम नहीं समझते हैं । ये बताएं कि क्या अंतर हो सकता है ? जिन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, उसी तरह से लगता है कि इनलोगों में कंपिटिशन है । चले गए विदेश । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए विदेश और विदेश में जाकर जापान को और दूसरे देशों को चैलेंज करके आए कि इससे बढ़िया हमारे यहां का रोड है । हमको लगा कि कहीं माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे बड़े

भाई नन्द किशोर बाबू गए हैं, कहीं वहां जाकर इस शब्द की चर्चा तो नहीं कर देंगे कि बिहार सबसे टॉप और अव्वल दर्जे पर है लेकिन धैर्य रखकर कुछ ईमानदारी बरत कर आए । हम हृदय से आपका शुक्रिया अदा करते हैं ...

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): समय की ओर देखिए । समस्या बताइए ।

श्री विजय प्रकाश: इसीलिए जिन सवालों का, माननीय नन्द किशोर बाबू ने अभी जो पढ़ने का काम किया, हम एक छोटा शब्द पढ़कर आपके सामने में बताना चाहते हैं, जो शब्द बोले हैं, उसपर हम बोलना चाहते हैं यही कि पिछले बजट में माननीय नीतीश कुमार जी ने लिखवाया था कि बजट में इन शब्दों का प्रयोग करें कि –

'किसी को जुमले पसंद है, किसी को फिक्र है नाम हो ज्यादा,
मगर हमारी कोशिश यह है कि बातें कम हो, काम हो ज्यादा ।'

यह माननीय मुख्यमंत्रीजी तेजस्वी जी से कह कर कि इन शब्दों का प्रयोग करो और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पेश करने के लिए दिए थे पिछले बजट में।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): समस्या बताइए ।

श्री विजय प्रकाश: इसीलिए आज हम पूछना चाहते हैं कि आपका विजन क्या है ? ट्वेंटी-ट्वेंटी में जो सिंगल रोड था ... क्रमश:

टर्न-16/कृष्ण/12.03.2018

श्री विजय प्रकाश (क्रमश:) : जो डेढ़िया रोड था, जिसको डबल करना था, माननीय तेजस्वी जी का यह सपना था, उसका क्या हुआ ? उसकी चर्चा है कि नहीं है ? छपरा डबल डेकर फ्लाई ओवर ब्रीज का जो सी0आर0एफ0 के द्वारा प्रस्ताव कराया गया था, आप सिर्फ इतना ही किये हैं कि उसको आप कैबिनेट में रखने का काम किये हैं जबकि पहले से छपरा का डबल डेकर जो कि राज्य में पहला है, देश में दूसरा है कि नहीं है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे राज्य में पहला डबल डेकर रोड का प्रस्ताव दिया गया था । आज यह स्थिति है, पूरे बिहार में आप कामों की चर्चा क्यों करते हैं ? महोदय, समय की कमी है । इसलिए हम माननीय मंत्री महोदय से हम अपने इलाके की कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहते हैं । सभापति महोदय, हमारे यहां एक रेलवे ओवर ब्रीज से सीधे बरहट ब्लॉक की ओर कुकुरझप डैम होते हुये गुरमाहा जानेवाली सड़क, जो जमालपुर और मुंगेर की ओर जाती है, वह शायद सैंक्शन भी हुआ है, ग्रामीण विकास विभाग से उसको पथ निर्माण विभाग में लेकर बनाया जाय, जिससे 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी । माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दीजियेगा ।

सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं कि एन0एच0 33 (ए) का नरियाना पुल है । यह बहुत ही गंभीर बात है कि लगभग 6 महीने से नरियाना पुल का एक पाया धंस गया, जिसके कारण कई घटनायें और दुर्घटनायें घटी है, कई मौत भी हुई हैं लेकिन उस आजतक कोई काम नहीं हो रहा है । लगभग 6 महीना बीत चुका है। महोदय, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वहां किसी दिन भी घटना घट सकती है, वहां ओवर ब्रीज के अंदर-अंदर नदी के बीच लोग रंगबाजी टैक्स वसूलने का काम करते हैं जिसके कारण वहां दो जातियों के बीच कभी भी सभी बिखराव हो सकता है, मतभेद हो सकता है । सुल्तानगंज से जानेवाली जो सड़क है,जो भागलपुर के इलाके में हैं, उसमें बेली ब्रीज है, जिसपर अभी तक 10 वर्षों से बड़ी ट्रक पार नहीं कर रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है।

(व्यवधान)

तेजी से काम नहीं लगा हुआ है । कहां काम लगा हुआ है ?

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : इनका समय कम है ।

श्री विजय प्रकाश: जमुई से खैरागढ़ी होते हुये कौआकोल-नवादा को जोड़ा जाय, ललदईया पुल पर सिमलतल्ला चांनन जाने में 5 घंटे लगते हैं, एक-दो घंटे में दूरी तय हो जायेगी, इसलिए उसको जोड़ दिया जाय ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आप कृपया समाप्त करें । आपका समय पूरा हो गया ।

श्री विजय प्रकाश : हुजूर,अभी तो पांच मिनट ही हुआ है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : हम यहां घड़ी लेकर बैठे हैं ।

श्री विजय प्रकाश : एक मिनट हुजूर । हम कहना चाहते हैं कि अतिपिछड़ा वर्ग का होस्टल जो जमुई में है, वह आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय में बना था, लेकिन आज वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है । माननीय मंत्री जी, उसको भी ध्यान दीजियेगा । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में राशन कार्ड का, अन्नपूर्णा और अंत्योदय योजना को तो खत्म ही कर दिया गया, डोर टू डोर डिलिवरी में कमीशनखोरी पूरा चल रहा है, तेल सब्सिडी खत्म दिया गया, डीलर क्या करेगा ?

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपा आप बैठ जाईये । धन्यवाद।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, एक जरूरी बात हम माननीय मंत्री,खाद्य आपूर्त्ति से कहना चाहते हैं कि लगभग 5 दिन पहले भी आपसे से मिलकर हम बोले थे एक ललन सिंह नाम का एफ0सी0आई0 गोदाम का ठीकदार है, वह एक गरीब महिला, वहां जो जिला में एक छोटा पदाधिकारी है खाद्य विभाग का, एक लीना सिंह, जो कमजोर परिवार से आती है,

उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसने एफ0आई0आर0 भी की है, फिर भी ललन सिंह का डीलरशीप खत्म नहीं किया जा रहा है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करेंगे । आप बैठ जाईये ।

श्री विजय प्रकाश : सरकार की तरफ से यहां से जो आदेश गया था प्रभार देने का, वह प्रभार छिना गया है, माननीय मंत्री इस पर ध्यान देने का काम करेंगे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : मा0स0श्री विजय प्रकाश जी, आप बैठ जाईये । माननीय सदस्यगण, अच्छी बातें अच्छी होती है । हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ा मुश्किल से पैदा होता है चमन में दिदावर पैदा । यह पहली बार मुख्यमंत्री और पथ मंत्री, जो जापान गये थे, उसकी प्रशंसा इन्होंने उन्मूख भाव से किया है । इनको धन्यवाद। यह अच्छी बात है ।

जनता दल (यूनाईटेड) माननीय सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, जनाब आपका 5 मिनट है ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 के पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांग पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, जापान की चर्चा हो रही है, यह बढ़ते बिहार का यह लक्षण है कि आज हम टेकनोलॉजी में इतना बढ़ गये हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार दुनियां के जो अन्य हिस्से हैं, उसके अनुरूप हमारे राज्य की सड़कें सुन्दर हो । आप कह रहे थे ढाई घंटे में । हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसीलिये गये थे कि हम ढाई घंटे में यहां सुरक्षित यहां पहुंच जाय, उस तकनीकी के लिये वे जापान गये थे । तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कभी हम बिहार के बारे में सुने थे कि किसी के गाल की तरह बिहार का सुन्दर रोड होगा । आज उससे सुन्दर रोड हमारे बिहार में है । महोदय, आज लग रहा है कि बिहार में पथ निर्माण विभाग के प्रयास से और माननीय नन्द किशोर बाबू जैसे मजबूत इरादे और प्रतिबद्ध मंत्री हैं और इनका दृष्टिकोण बड़ा है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी जिनको लगता है कि बिहार देश और दुनियां में नाम करे चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो, आर्थिक विकास के लिये जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वह है पथ निर्माण विभाग । पथ निर्माण विभाग में आज सड़क का नजरिया बदला है । आज पटना 3 से 4 घंटे में आ जाते है । चाहे किशनगंज हों, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे नेपाल सीमा पर सीतामढ़ी और मधुबनी हो, चाहे वह पश्चिमी चम्पारण हो या पूर्वी चम्पारण हो तो कहना चाहते हैं कि लोगों की सोच और दृष्टि बदला है ।

महोदय, पथ निर्माण मंत्री से चाहेंगे कि सारे लोग मिलकर सुन्दर बिहार बनाने के लिये संकल्पित हों जिसमें पथ निर्माण विभाग की भूमिका बड़ी अच्छी होगी । साथ ही राज्य सरकार की न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुये सभी क्षेत्रों और वर्गों को लेकर सरकार कृत-संकल्पित है। राज्य के विकास की रणनीति में समावेशी

न्यायोचित सतत् होने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति पथ पर आधारित है । सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो । किसी भी राज्य की चतुर्दिक विकास विकास में आधारभूत संरचना के बिना कृषि आधारित औद्योगिक विकास, उत्पादनों की बाजारीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है । आधारभूत संरचना के बिना विकास के पहियों को गति देना संभव नहीं है । आधारभूत संरचना की विकास की प्रथम सीढ़ी पथ निर्माण विभाग है जो राज्य की जनता के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है ।

साथियों खासकर हम बजट में जो हम देखें हैं चाहे वह इन्डो-नेपाल के सड़क की बात हो या प्रधानमंत्री पैकेज की बात हो या धार्मिक स्थल की बात हो, लगता है कि इस बजट में हरेक दृष्टि से विकास की बात की गयी है, एक दूसरे से जोड़ने की बात की गयी है । हम खासकर माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहेंगे कि इन्डो-नेपाल जो सड़क है जो पिछले 3-4 साल से, हम कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहेंगे, 3 साल पहले टेंडर हो गया है, खासकर झौरी चौक से लेकर भुतहा तक जो 28 किलोमीटर है, टेंडर हुये 4 साल हो गया है, लेकिन आज तक वह नहीं बना है। हम उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इन्डो नेपाल जो सड़क है, जहां भी बना है, उसकी स्थिति आज जर्जर हो गयी है, टेंडर के बावजूद वह अभी तक नहीं बना है । इसलिए निश्चित रूप से विभाग को चाहिए कि जो भी वहां इन्डो नेपाल की सड़के है, उसे बनाया जाय ।

महोदय, दूसरा हम मांग करते हैं कि जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थल है, नेपाल के सखरा भगवती अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्म स्थल है, हम चाहेंगे कि महादेव मठ से लेकर नेऊरभरपुरी नेपाल की सीमा तक उसको पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से जोड़ा जाय,आर0सी0डी0 सड़क से जोड़ा जाय, जिससे भारत और नेपाल के लोगों को आने-जाने में सुविधा हो ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य आप समय देखिये और क्षेत्रीय स्तर पर आ जाईये ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : जी, क्षेत्रीय समस्याओं पर आ रहे हैं । मधुबनी जिलान्तर्गत ही तेनुआही एन0एच0 104 से लेकर खुटौना बाजार तक जो 15 किलोमीटर की सड़क है, जो दोनों तरफ एन0एच0 और एस0एच0 को जोड़ती है लेकिन बीच में आर0सी0डी0 रोड के चलते वह अच्छी स्थिति में नहीं है, वह पूरी तरह से व्यापारिक स्थल है, उसको पी0डब्ल्यू0डी0 में लेकर उसको दोहरी सड़क बनाना चाहिए ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : एक मिनट और दिया जाय। हम चाहते हैं कि एन0एच0-57 से लेकर नेपाल सीमा तक एक बेहतर रोड बनाया जाय जो बीच में खाली है । हम चाहेंगे कि एन0

एच0 57 अररिया संग्राम अंधराठाढ़ी होते हुये भूतपट्टी एकहरी झिकटियाही और झलोन नेपाल के सीमा तक अधिग्रहण कर इन्डो–नेपाल सड़क है उसमें अधिग्रहित कर उसका विस्तार किया जाय । इन्हीं चन्द बातों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : रचनात्मक सुझाव के लिये आसन की तरफ से आपको धन्यवाद । राष्ट्रीय जनता दल, डा0 मो0 नवाज आलम । आपका समय 10 मिनट है ।

टर्न–17/सत्येन्द्र/12–3–18

श्री मो0 नवाज आलम: सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और प्रस्तुत जो बजट है, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, बहुत सारे साथियों ने अपने अपने विचार रखने का काम किया है । मैं खासकर अपने माननीय सत्ता पक्ष के साथियों से भी कहेंगे कि जनहित के मुद्दे पर सरकार के सामने अपना ध्यान आकृष्ट करना यह आपका दायित्व बनता है और हमलोग के इस सदन में भी लिखा हुआ है कि विरोधी दल सरकार के अंग होते हैं महोदय । महोदय, बहुत सारी चीजें सारे साथियों ने रखने का काम किया है इसलिए अपने नाकामियों के जनहित के सवालों पर अगर जो है माननीय सदस्य चूप रहते हैं तो सचमुच में वह जो है अपने जनता के साथ मेनडेट के खिलाफ, आप धोखा देने का काम करते हैं । ठीक किसी ने कहा है–

जो चुप रहेगी जुबानें खंजर,
लहू पुकारेगा, आस्तीन का ।

साथियो, अगर आप इस सदन में जनता से, जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ आपको यहां लाने का काम किया है, आप उनकी उम्मीदों पर अगर खरा नहीं उतड़ते, जनहित के सवालों को उठाने का काम नहीं करते तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप जो है जनता के साथ, सदन के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे साथियों ने ठीक ही कहा है, हमलोग के अनुभवी माननीय मंत्री जी है लेकिन हमने देखा है राजनीतिक जीवन में, 90 के दशक से मैं देख रहा हूँ। साथियों, पथ निर्माण विभाग हमलोग जिस इलाके से शाहाबाद से आते है, शाहाबाद का इलाका चलने के लायक नहीं था, जब हमलोग चलते थे यही जो धरहड़ा ब्रीज है, वह ब्रीज गिर जाता है लोग त्राहिमाम हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है लेकिन सभापति महोदय, उस वक्त आप भी पथ निर्माण मंत्री थे आपने जो उसके लिए करने का काम किया था एक टाईम बॉड के साथ, लगभग एक माह, दो माह में उस पुल का निर्माण करने का काम किया था जिसके लिए मैं उस दिन एक

कार्यकर्त्ता के हैसियत से, एक समाजसेवी की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से, आपके वहां उस उद्घाटन समारोह में देखने पहुंचा था । महोदय, इसी तरह से पूरे पीरो से तमाम उस इलाके में चलने के लिए रोड नहीं था, लगभग हमें लगता है 100 ब्रीज, छोटे बड़े जो हैं उसको आपने बनाने का काम किया था लेकिन आपके बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बड़ा जीर्णोद्धार का निर्माण हो । उस पुल का निर्माण आपने जो है भागलपुर की सकरी, तमाम ऐसे बड़े बड़े जो है, आपने पुल का जो जाल बिछाने का काम किया था , लाईफ लाईन बनाने का जो काम किया था, वैसा इस बजट में कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है । कुछ समय पहले ठीक ही एक साथी ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव जी ने 18-19 महीने के शासनकाल में कुछ अच्छा करने का सपना संयोया था, उसको उन्होंने सरजमीन पर कहीं न कहीं उतारने का काम किया है । उनके ऊपर हम कहेंगे कि वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, नहीं तालिम दी जाती परिन्दों को आह्ट उड़ानों की । इसलिए महोदय, इस बात को कहते जो तेजस्वी जी, जिनके लहू में माननीय जन जन के नेता लालू प्रसाद जी का जो सपना है उनकी धरोहर है उसको उड़ान भरने की ताकत सचमुच में उन्होंने अपने बाप के गोद से सीखा है, उन्होंने उसको सरजमीन पर उतारने का जो काम किया था 18-19 महीने में महोदय, उसी का नमूना है कि छपरा से जो डोरीगंज पुल है उसका उद्घाटन करने का काम किया, जो एक सराहनीय कदम है । महोदय, हम जानना चाहते हैं इस सरकार के माननीय मंत्री जी हमारे गार्जियन स्वरूप है लेकिन हम लगातार, जब से हम सदन में आये हैं, हम छोटे से कार्यकर्त्ता हैं महोदय, जब से हम सदन में आये, लगातार चाहे मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हो, चाहे आपका जो विधान-सभा के पटल पर हो, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे हैं लेकिन एक भी काम, आज पूरा शाहाबाद के लोग परेशान हैं जाम की समस्या से, दो-दो घंटा हमलोगों को विधान-सभा आने में बिलम्ब होता है, कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है, आपने जो बनाया था ,आपने जो ब्लैक स्पॉट का नाम दिया था, जो आपने ब्लैक स्पॉट का नाम दिया था उसी का परिणाम था, बहुत सारे एक्सीडेंट में कहीं न कहीं कमी होती थी हम बताना चाहते हैं महोदय, ब्लैक स्पॉट पर आज जो है पीरो-बिहियां पथ पर देवचंद पुल है एक महोदय, वह देवचंद पुल पर लगातार लगभग कम से कम 20-25 लोग अभी दो माह में मृत्यु हुई है महोदय, हम जो है सरकार से जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा विजन है, आपका कौन सा काम करने का तरीका है । दूसरा है महोदय, हमारे क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण सड़क है उसमें बहुत से छोटे छोटे पुलिया हैं, लगातार वहां एक्सीडेंट होते रहता है लेकिन कोई सरकार का ध्यान नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में, माननीय मंत्री जी को, प्रधान सचिव जी को लगता है 50 वार लिखकर देने का काम किये लेकिन अभी तक उस पर अमली जामा

कोई पहनाने का काम नहीं किया गया इसलिए हम इस प्रस्ताव का निश्चित रूप से इस बजट का विरोध करते हैं । बिनटोली लकड़िया पुल जो लकड़ियापुर बार्ड नं0-30 में आता है महोदय और उस लकड़िया पुल पर लगातार एक्सीडेंट होता है । गरीब समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, माननीय मंत्री जी आप भी अति पिछड़ा समाज के बीच से आते हैं, आपके कार्य का क्या विजन है? एक भी रोड का अधिग्रहण माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह लकड़िया पुल निश्चित रूप से बनेगा । प्रधान-सचिव ने भी उसको देखने का काम किया है लेकिन आजतक उसका डी0पी0आर0 बनकर आपके विभाग में गया है, अधिग्रहण का प्रस्ताव गया है महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा विजन है, इसलिए माननीय मंत्री जी आप कहते हैं विकास की बात, एन0एच0-30 जो है मोहनियां, चलने के लायक नहीं है, आप जो कहते हैं कि तीन घंटे में पटना पहुचेंगे, हम जानना चाहते हैं सदन के तमाम सदस्यों से कि एन0एच0 की जो हालत है कि उसमें ठेहून भर गबरा है, आप उसको कैसे सुधारने का काम करेंगे? हम जानना चाहते हैं, आपका जो पुराना पुलिस लाईन छोटकी सलेमपुर उसके चौड़ीकरण हेतु लगातार समीक्षा बैठक में आपके सामने रखने का काम किया है लेकिन नहीं हुआ । मुझे लगता है कि ये सरकार सिर्फ जुमलेवाजी की सरकार है अपना विजन, करने का तरीका जो है निश्चित रूप से मुझे लगता है नहीं है इसलिए कि विभाग में प्रस्ताव आता, फाईलों में दौड़ता रहता हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप इसको गंभीरता से लेते हुए अगर सचमुच विकास करना चाहते हैं या सिर्फ जुमलावाजी करना चाहते हैं, अपना आईना दिखाना चाहते हैं, आपके जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरा के सरजमीन पर बोली लगाने का काम किया था महोदय, बोली लगा एक करोड़ दूं, दो करोड़ दूं, सौ करोड़ दूं, सवा सौ लाख करोड़ दूं, महोदय, एक भी काम सरजमीन पर देखने को नहीं मिला, बिहार के पैकेज के मामले में भी जीरो साबित हुए इसलिए हम बताना चाहते हैं, अगिआंव-गढ़हनी पुल का, इसी तरह से जर्जर स्थिति है एन0एच0-33, जो है बक्सर जिला में, उसकी भी खराब हालत है, चंदवा पुल जो है, देवचंद पुल का मामला इसी तरह से है महोदय, हम माननीय मंत्री से, जिस तरह से आपने कहा था जाम की समस्या के बारे में, आप कहते हैं जाम की समस्या का हमने प्रस्ताव दिया था माननीय मुख्यमयंत्री जो सदन के नेता है, बिहार के मुखिया हैं, हमलोग किसके पास गुहार लगायेंगे महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री हाथ उठाने का काम करते, वह जो जाम की समस्या है और जाम की समस्या के लिए रिंग रोड बजट में लाने का काम हमने किया था और रिंग रोड का डी0पी0आर0 भी बना था लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ महोदय । (क्रमशः)

टर्न-18/मधुप/12.03.2018

...क्रमशः ...

श्री मो0 नवाज आलम : इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को हम इस बात को बताना चाहते हैं कि आपका कोई भी काम चाहे महात्मा गॉधी सेतु का मामला हो, आपको बजट के मामले में, बजट पहले की तुलना में 2018-19 स्कीम मद में 201.17 करोड़, स्थापना मद में प्रतिबद्ध व्यय में 52.5 करोड़ और प्राक्कलन मद में 253.22 करोड़ आपको अधिक दिया गया लेकिन आपका कोई विजन नहीं है । इसलिये माननीय महोदय, दो पीपा पुल बनने का मामला था, एक बना । आज तक उसका डी0पी0आर0 है, कहीं कोई काम आपके सामने नहीं आया ।

महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं । महोदय, सबसे बड़ी समस्या है इस काम के रूकावट के लिये बालू की समस्या के मामले में आप कहते हैं कि हम विकास करेंगे, कौन-सा विकास करेंगे ? बालू की ऐसी जटिल समस्या है, भवन निर्माण मंत्री जी भी बैठे हैं, हमलोगों के डी0एम0 का ऑफिस समाहरणालय है, वह पूरी तरह आज तक चार सालों से लम्बित है, कार्यालय कहीं किसी दूसरे जगह किराये पर चलता है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें ।

श्री मो0 नवाज आलम : पिछड़ों के लिये छात्रावास की इसी तरह से बुरी हालत है । पिछड़े की वकालत करते हैं ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, अब ज्यादा समय न लेते हुये समाप्त करें ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, आखिरी बात कहते हुये कुछ सुझाव देते हुये हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि आज आरा शहर पहला ऐसा शहर है जहॉ तमाम रोड जल-जमाव से डूब रहा है, उसका कोई हाल लेने वाला नहीं है । नगर निगम की भी वही हाल है । सेंटीग्रेट मोड़ से बिंद टोली मारूति नगर होते हुये बलवत्ता होते हुये ....

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य नवाज आलम, लिखित दे दीजिये, माननीय मंत्री संजीदा हैं, करेंगे, अवश्य करेंगे । आपने अच्छा सुझाव दिया है, कम समय में इतना किसी का सुझाव नहीं आया जो आपने दिया है ।

श्री मो0 नवाज आलम : ठीक है, सर । धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : शुक्रिया ।

लोक जनशक्ति पार्टी, माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी, बड़े अफसोस के साथ, 2 मिनट आपका है ।

श्री राजू तिवारी : सभापति महोदय, 2 मिनट देने के लिये धन्यवाद । मैं सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ । मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो रोड है - एक रोड एस0एच0 74 से पशुपति चौक होते हुये पिपरा सिद्धी मलाही गहेरी और इंगलीश होते हुये घिउआढ़ार, दूसरा है संग्रामपुर एस0एच0 से बरियरिया होते हुये अरेराज, अरेराज बहुत

प्रसिद्ध मन्दिर है, इन दो रोड के लिये आपके माध्यम से मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ चूँकि क्वेश्चन में मंत्री जी ने कह दिया है कि ये दोनों रोड आपका पी0डब्लू0डी0 में ले लिया जायेगा । इसलिये मैं आसन के माध्यम से मंत्री जी को लाख-लाख बधाई देता हूँ और गोविन्दगंज के निवासियों की तरफ से भी शुभकामना देता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : सुझाव रखिये ।

श्री राजू तिवारी : सर, सुझाव की बात जहाँ तक है, मेरा काम हो गया है, मैं बधाई देने के लिये खड़ा हूँ, दो मिनट में बधाई ही दे दिया । धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : शुक्रिया ।

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी । माननीय सदस्य श्री ललन पासवान, अफसोस के साथ, 2 मिनट आपका है ।

श्री ललन पासवान : सर, न्याय के साथ विकास कर दीजियेगा ।

सभापति महोदय, मैं सरकार के पक्ष में खड़ा हूँ, माननीय नन्दकिशोर यादव जी पहले भी मंत्री रहे हैं, मेरे यहाँ कई सड़कों का निर्माण इन्होंने स्टेट हाईवे में कराया था और आज हम फिर आग्रह करना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी और एन0डी0ए0 गठबंधन में जो सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है, मेरी एक सड़क है माँ मुंडेश्वरी से तारा चंडी धाम, एन0एच02 मोहनियाँ से भभुआ, भभुआ से माँ मुडेश्वरी, माँ मुंडेश्वरी से भगवानपुर अमाव होते हुये चेनारी, मल्लीपुर दरियांव तक तारा चंडी धाम, पाँच धामों को जोड़ने वाली सड़क है, पिछले बार भी सरकार में स्टेट हाईवे की चर्चा हुई थी, सरकार ने स्वीकार किया था और हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि पाँच धामों को जोड़ने वाली सड़क है माँ मुंडेश्वरी, गुप्ताधाम, गीता घाट आश्रम, तारा चंडी धाम, शेरगढ़ किला, आग्रह करेंगे कि इसको जोड़ दें, स्टेट हाईवे बना दें, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है ।

दूसरी बात सभापति महोदय, कुदरा-चेनारी स्टेट हाईवे से महलर से किनर चोला होते हुये शिवसागर एस0एच0 तक एक सड़क है जिसको मैं अधिग्रहण के लिये आग्रह करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से । महोदय, बसनारा से नेउरी सदोखर तुर्की होते चंदनपुरा लोधी 10 कि0मी0 की सड़क है, हमारा इलाका पूरा उग्रवाद प्रभावित है, सड़क टूट जाती है तो बहुत प्रशासनिक दृष्टिकोण से बड़ा दिक्कत होती है । तीसरा है, शिवसागर चेनारी एस0एच0 से छोटका केनार होते हुये भाटी से मझुई होते हुये रायपुर चोर वेदा दर्शनाडीह पी0डब्लू0डी0 पथ, इसको जोड़ दें । एन0एच0 2 सासाराम से आउवा घटट्ीकन से धनुआ सउजा मीतान्दा होते हुये पी0डब्लू0डी0 बेदा दर्शनाडीह पथ, तीन-चार सड़क है, एक सड़क महोदय, एन0एच0 2सी0 बना रहे हैं माननीय मंत्री जी, अकबरपुर यदुनाथपुर, डेहरी से यदुनाथपुर अकबरपुर 40 कि0मी0 176 करोड़ का, उपर

वाली सड़क जो एन0एच0 2सी0 ओरिजनल है, जो अकबरपुर से पहाड़ के नीचे जाती है यदुनाथपुर और एक पी0डब्लू0डी0 की सड़क है जो अकबरपुर के नीचे से जाती है यदुनाथपुर, दोनों सड़क जो पर्यावरण के चलते रूका हुआ है, माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको करा दें । दो सड़क पहले से प्रोपाजल है, मोहनिया एन0एच02..

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया समाप्त करिये ।

श्री ललन पासवान : महोदय, मात्र दो सड़क के बारे में मैं कहना चाहता हूँ । एन0एच0 2 डेहरी से यदुनाथपुर रेणुकोट 75 में जोड़ने का प्रोपोजल सरकार ने भारत सरकार को भेजा है, छः राज्यों को जोड़ने वाली सड़क है । दूसरा सड़क है एन0एच0 2 मोहनिया से भगवानपुर, अधवारा होते राबर्ट्सगंज 7 और 76 मिर्जापुर, दोनों प्रोपोजन भारत सरकार के लिये बिहार सरकार ने भेजा है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : धन्यवाद ।

श्री ललन पासवान : माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग अगर बन जाता है तो न कि मेरा, बम्बई तक जाने की दूरी 500-600 कि0मी0 कम होगी । हमारा सम्पूर्ण बिहार का और भारत का अंतिम छोर तक यह जोड़ने का काम करेगा । यही बात कहते हुये आपको धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : धन्यवाद ।

इंडियन नेशनल कांग्रेस । माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ, आपका 10 मिनट समय है ।

श्री सिद्धार्थ : सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिये मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ।

आज पीपुल्स वर्क डिपार्टमेंट का बजट पास हो रहा है, मैं माननीय मंत्री जी का दो महत्वपूर्ण विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । एक तो पूरे बिहार में सड़कों का निर्माण हो रहा है, यह बात सत्य है लेकिन जहाँ भी बसावट है, गरीबों की झोपड़ी है, वहाँ पर सड़क के साथ नाला का निर्माण नहीं किया जा रहा है । सड़क बन जा रही है और सड़क ऊंचा बन रहा है, सारा पानी घर के अन्दर चला जा रहा है। एक ऐसा सर्कुलर आपके माध्यम से विभाग में जाय कि जहाँ भी बसावट हो और घर हो, उस घर के साथ नाला का निर्माण जरूर हो वरना उन गरीबों के साथ सड़क निर्माण का कोई फायदा नहीं है । मेरे ही क्षेत्र में तितवास और बाघाकोल गाँव में सड़क बन गई और सारे दलित-गरीब के घर में पानी घुसा रह रहा है । आखिर क्या लाभ है ? ट्रैक्टर, ट्रक और गाड़ी जा रहा है और उनके घर में पानी घुस रहा है ।

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सड़क तो बन जा रही है लेकिन मेन्टेनेंस का जो समय है, मेन्टेनेंस का जो पैसा है, वह सही ढंग से एकदम खर्च नहीं हो रहा है। अधिकारियों के साथ मेल-मिलाप करके, साल-दो साल बाद सड़क बुरे हाल में हो जाती है, मेन्टेनेंस का पैसा अपना लेन-देन करके निकाल लिया जाता है । मेन्टेनेंस के लिये

एक विशेष कमिटी बनाई जाय जहॉ भी सड़क का मेन्टेनेंस का जो भी समय है, उस समय के साथ मेन्टेनेंस भी चलता रहे । यह दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है और मेरा मानना है कि सदन में बैठे हुये सारे माननीय सदस्यों के साथ यह घटना हो रही है, उनके क्षेत्र में हो रहा है । इन दोनों चीज पर मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाय ।

महोदय, आज हमारे क्षेत्र में, विक्रम प्रखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है पतूत बाजार से बिहटा प्रखंड परेव बाजार तक, लगातार ट्रकों का आना-जाना वहॉ पर लगा रहा है, इस रोड को पास करवा दिया जाय, जल्द से जल्द बनवा दिया जाय । तीसरा है, पीपा पुल से जनपारा गॉव में यहॉ भी वही स्थिति है । अगर कोई बीमार पड़ जाय तो ट्रकों का यह स्थिति है कि आवागमन अवरूद्ध हो जाता है । तीसरा, एक लख पर पुल है जिसके कारण निरन्तर चार-चार पॉच-पॉच घंटा नौबतपुर लख पर जाम रहता है । यह तीन काम बहुत ही आवश्यक है और समझिये कि मुख्य मार्ग है । ये तीन चीज का मैं निवेदन करूंगा कि इसे तुरंत करवाया जाय ।

...क्रमशः...

टर्न-19/आजाद/12.03.2018

.... क्रमशः .....

श्री सिद्धार्थ : चौथा एक जिला किशनगंज में पोठिया बजार में देवीचौक से सोनापुर है और झिझुआबारी से पोठिया है, इसे पी0डब्लू0डी0 में स्थानान्तरण करके बनवा दिया जाय । एक छपरा प्रमंडल की समस्या है मांझी-जय छपरा पथ निर्धारित मानक के अनुसार नहीं बनाया गया है । उसी प्रमंडल में अभी भी बसडीहा और शाहपुर भाया जमालपुर पथ का निर्माण हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि दोनों पथों की जॉच करायी जाय और वहां के वर्तमान विधायक की उपस्थिति में जॉच करायी जाय ।

आज पथ निर्माण विभाग के साथ-साथ सिविल सप्लाई का भी दिन है.....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : वर्तमान विधायक कौन है वहां ?

श्री सिद्धार्थ : श्री विजय शंकर दूबे जी हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अच्छा-अच्छा ।

श्री सिद्धार्थ : महोदय, आज सिविल सप्लाई का भी दिन है, मैं अपना कुछ पक्ष है, जो सरकार को बताना चाहूँगा । महोदय, नवम्बर से धान अधिग्रहण हो रहा है, सी0एम0आर0 चावल गिराने के लिए पिछले 15 दिनों से बिहटा गोदाम खाली नहीं है । पैक्स ट्रक पर चावल रखकर के बिहटा गोदाम ले जा रहे हैं और ले आ रहे हैं, यह स्थिति है । 15 दिन हो गया है और गोदाम में चावल रखने के लिए आज जगह नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी कष्ट की बात है कि बिहार में किसान की सबसे बड़ी आबादी है

और जो साल भर मेहनत करके अनाज उपजा रहा है, उसकी अनदेखी की जा रही है । न्यूनतम लक्ष्य से ऊपर खरीददारी करने वाले पैक्सों को एस0एफ0सी0 के द्वारा इनफोर्समेंट नहीं बनाया जा रहा है । जिसके कारण जो भी धान पैक्स खरीद लिया है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है और पूरा साईकिल रूका हुआ है । पूरा पटना ग्रामीण इलाका में पूरा साईकिल जो है सरकुलेशन है अधिग्रहण का और पेमेंट पूरा का पूरा रूका हुआ है । नियमानुसार जैसे ही सी0एम0आर0 चावल एस0एफ0सी0 को उपलब्ध कराया जाता है, उसके 36 घंटे के अन्दर भुगतान होना चाहिए । स्थिति यह है कि 22.02.2018 के बाद कोई भी भुगतान पटना जिला में नहीं किया गया है । यह दुर्भाग्य की बात है कि जो काम 36 घंटा के अन्दर होना चाहिए, वह पिछले 15-20 दिनों में नहीं किया गया है । महोदय, पिछले साल तक यही नियम था कि जो भी एस0एफ0सी0 को सी0एम0आर0 चावल उपलब्ध कराया जाता था, उसे एक्सेप्टेंस दिया जाता था एस0एफ0सी0 के द्वारा और सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक जो है, पैक्स का सी0सी0 बढ़ा देता था। पूरे साल इस साल एक्सेप्टेंस देने के बाद भी कॉपरेटिव बैंक ने पैक्सों का सी0सी0 नहीं बढ़ाया है, यह तो एक सरकुलेशन है । उधर से पैक्स लेता है और एस0एफ0सी0 को देता है, भुगतान होता है लेकिन पूरा साईकिल चौपट हो गया है । महोदय, मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से 28.02.2018 को मैंने ध्यानाकर्षण दिया था, जिसमें माननीय सहकारिता मंत्री और सप्लाई मंत्री ने मुझे जवाब दिया था कि इस वर्ष 2017 में धान अधिप्राप्ति के लिए 32200 किसानों द्वारा निबंधन कराया गया है । कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 28.02.2018 तक मात्र 12000 किसानों का धान अधिग्रहण किया जा सका है जो कि 50 प्रतिशत से भी कम है । नवम्बर से लेकर फरवरी तक 50 प्रतिशत से भी कम अधिग्रहण किया गया है तो एक महीना में क्या 50 प्रतिशत हो जायेगा ? दूसरी सबसे बड़ी बात है माननीय मंत्री जी ने बताया था कि मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा धान का अधिग्रहण हुआ है । मैं आपको ये वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप ही के बिहार स्टेट फुड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लि0 के प्रबंध निदेशक की दिनांक 1.12.2017 पत्र सं0-21517 जिसमें इन्होंने साफ यह दर्शाया है कि इस राज्य में धान की उत्पादकता अधिक होने के फलस्वरूप पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा न्यूनतम लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति किये जाने की विशेष व्यवस्था किया जाय । इस साल धान का उत्पादन विशेष हुआ है और निश्चित रूप से सरकार का यह लक्ष्य होना चाहिए कि शतप्रतिशत धान अधिग्रहण किया जाय । अगर पैक्स के द्वारा धान अधिग्रहण नहीं किया जाता है तो यह राज्य का दुर्भाग्य होगा । आप सोच लीजिए कि अगर बिचौलिए या व्यापारी को धान देते हैं तो तुरंत पैसा .....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, पथ संबंधित समस्या आपका खतम हो गया ?

श्री सिद्धार्थ : सर, एक मिनट लेंगे, बहुत जरूरी है । सर, विक्रम व्यापार मंडल है, विक्रम व्यापार मंडल में 31.01.2018 से लेकर अभी तक डेढ़ महीना हो गया है, अभी तक किसी भी किसानों का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है । दूसरा एक आवश्यक सूचना है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ । वर्ष 2014-15 में एस0एफ0सी0 के द्वारा विक्रम प्रखंड में धान अधिप्राप्ति की गई थी । किसानों को अभी तक 2854 क्विंटल धान, उस समय चूँकि धान अधिप्राप्ति होता था, लाल पर्चा पैक्स को दिया जाता था । आज तक 4 साल हो गया, 2854 क्विंटल धान का भुगतान नहीं किया गया है । महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर सरकार किसानों का धान का पैसा रखकर क्या करेगी, आखिर इसका क्या औचित्य है .....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, शांति-शांति । आसन का थोड़ा सुनिए । आपने दो बार कहा कि सदन के माध्यम से, माध्यम होगा आसन ।

श्री सिद्धार्थ : महोदय, मैं अंतिम विनती करूँगा कि जो भी धान अधिग्रहण हुआ है 2014-15 में 2854 क्विंटल, जो एस0एफ0सी0 के पास उपलब्ध है । आखिर एस0एफ0सी0 को क्या औचित्य है उसको पैसा रखने का .....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : ठीक है, आगे बढ़िए ।

श्री सिद्धार्थ : बकाया पैसा किसानों को दे दिया जाय । दूसरी सबसे बड़ी समस्या है आज हमारे बिहार में, किसानों को उचित समय पर जो साईकिल है, उसको मेनटेन नहीं किया जा रहा है । आज जब तक इस साईकिल को मेनटेन नहीं किया जायेगा, निश्चित रूप से शतप्रतिशत धान की अधिप्राप्ति नहीं हो पायेगी । जब तक सभी किसानों को हर परिवार को पैक्स से नहीं जोड़ा जायेगा, तब तक पैक्स बनाने का औचित्य ही पूरा नहीं हो सकता है । अगले साल पैक्स का चुनाव है, मैं महोदय से कहूँगा कि ऐसा सरकुलर निकाला जाय कि हर व्यक्ति का धान खरीदा जाय और सभी लोगों को पैक्स से जोड़ दिया जाय । ज्यादा से ज्यादा लोग पैक्स से जुड़े ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : कृपया आप इधर देखिए ।

श्री सिद्धार्थ : महोदय, सभी लोगों को पैक्स से जोड़ दिया जाय । किसानों का विकास तभी संभव है, जब हर किसान परिवार पैक्स से जुड़ा हुआ हो । बहुत,बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : धन्यवाद । भारतीय जनता पार्टी माननीय सदस्य श्री दिनकर राम जी, आपका समय 5 मिनट है हुजूर ।

श्री दिनकर राम : महोदय, आप दो मिनट ही कर दीजिए हुजूर लेकिन बोलने दिया जाय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : बोलिए ।

श्री दिनकर राम : महोदय, जब सरकार 2005 में बनी, माननीय सी0एम0 नीतीश कुमार, माननीय डिप्टी सी0एम0 श्री सुशील कुमार मोदी जी, पथ निर्माण मंत्री नन्द किशोर जी, उस

समय बिहार में गर्दा उड़ता था, चर्चा का विषय बना हुआ था । हमारे साथी रो रहे हैं । उस समय रोड नाम का कोई चीज नहीं था, रोड में गड्ढ़ा या गड्ढ़ा में रोड था, वही लोग बता देंगे । जब रोड बन रहा था तब चर्चा का विषय बिहार में था कि पूरे बिहार में गर्दा उड़ रहा था । जवाब देंगे नन्द किशोर यादव जी, जवाब दिये रोड बना और उनका मन माना नहीं । इसके पहले क्या रोड था, वे ही लोग बतावेंगे ।

महोदय, 2018-19 के बजट के पक्ष और कटौती प्रस्ताव जो साथी दिये हैं, उसके विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मैं 2018-19 के लिए पेश पथ निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, किसी भी राज्य की तरक्की के लिए सड़क का विकास होना अत्यंत आवश्यक है । महोदय, पथ निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है । सरकार यातायात को सुगम बनाने हेतु सड़कें का जाल बिहार में फैला रही है । सरकार की मंशा यही है कि राज्य के किसी भी कोने से पटना 5 घंटे में राजधानी पटना पहुँच जा सकें, इस दिशा की ओर निरन्तर अग्रतर प्रयास की जा रही है .....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्यगण, बुजुर्ग हैं, इनकी बात को सुनिए प्यार से आपलोग ।

श्री दिनकर राम : महोदय, सैदपुर नाला पथ, राजेन्द्रनगर से अगमकुँआ तथा अगमकुँआ से पहाड़ी मोड़ तक राष्ट्रीय उच्च पथ 30 पर अवस्थित नन्दलाल छपरा से पटना-मसौढ़ी पथ तक.. ... (व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : शांति-शांति । बोलिए दिनकर बाबू ।

श्री दिनकर राम : माफ करेंगे, अगर आप बनवाये थे, प्रस्ताव लाये थे तो आप बोलें, मैं बैठ जाऊंगा। उनके विचलित करने से हम विचलित होंगे क्या ? .... क्रमशः .....

टर्न-20/अंजनी/दि0 12.03.18

श्री दिनकर राम :....क्रमशः.... महोदय, सरकार द्वारा छपरा शहर में 3.5 किलोमीटर लंबा राज्य का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है । महोदय, आरा-छपरा के बीच गंगा नदी पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल, दाउदनगर (व्यवधान)

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : शांति । विजय जी, पिता तुल्य हैं । शांति, आप बोलिए ।

श्री दिनकर राम : अगर किये रहते तो यह तमाशा नहीं बोलते, हम यह खेला नहीं बोलते । आपने कुछ किया नहीं बिहार में, आप घबराइए नहीं । महोदय, सरकार द्वारा छपरा शहर में 3.5 किलोमीटर लंबा राज्य का पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जा रहा है । महोदय, सरकार आरा-छपरा के बीच गंगा नदी पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल, दाउदनगर-नासिरीगंज के बीच सोन नदी पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल, बख्तियारपुर से ताजपुर के बीच गंगा नदी पर चार लेन पुल, पटना के कच्ची

दरगाह से वैशाली जिले के बीच 6 लेन पुल, अंगुनीघाट एवं सुल्तानगंज के गंगा नदी पर टू-प्लस-टू लेन उच्चस्तरीय पुल, गंडक नदी पर चकिया-केसरिया-सत्तरघाट उच्चतसरीय आर0सी0सी0 पुल, मुजफ्फरपुर-सारण के बीच गंडक नदी पर बंगरा घाट उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल, दीघा घाट पर गंगा नदी पर रेल-सह-रोड.....

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य दिनकर बाबू, हो गया आपका । शांति ।

श्री दिनकर राम : नहीं-नहीं, अभी नहीं हुआ है । पहुंच पथ गंडक नदी पर धनहा-रतवल द्वारा राज्य के किसी भी क्षेत्र से राजधानी पटना आने के लिए सुगमता होगी । महोदय, सरकार ने पटना में जाम से मुक्ति दिलाने की ओर भी अग्रसर हे ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया, अब आप समाप्त कीजिए । आपका समय समाप्त हो गया । जो समस्या है, वह आप दे दीजिए, मंत्री जी ससमय कर देंगे .....

श्री दिनकर राम : सर, दो मिनट और । महोदय, सरकार द्वारा राज्य उच्च पथों के निर्माण कराने की सैद्धांतिक सहमति दी है । महोदय, सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत दो किलोग्राम गेहूँ एवं तीन किलोग्राम चावल, 8.57 करोड़ लाभुकों को प्रति माह 4.57 लाख मेघा टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): कृपया शांति, दिनराक राम जी, हो गया । बहुत काफी, आपने अच्छे सुझाव दिये हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद ।

श्री दिनकर राम : महोदय, एक मिनट । माननीय लोग आज हल्ला कर रहे हैं, वे कल कहां थे, रोड में गड्ढ़ा या गड्ढ़े में रोड की स्थिति उस समय थी । मैं बधाई देता हूँ अपनी सरकार को जो रोड के मामले में क्रांति लायी ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): धन्यवाद । अब सी0पी0आई0एम0एल0 के जनाब महबूब आलम, अफसोस के साथ दो मिनट ।

श्री महबूब आलम : महोदय, तीन मिनट होना चाहिए । हमलोग तीन विधायक हैं, और आप दो मिनट का समय दे रहे हैं ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन): तीन मिनट से एक सेंकेड ज्यादा नहीं । कमिटमेंट इज कमिटमेंट।

श्री महबूब आलम : मैं सभापति महोदय आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैंने पथ निर्माण विभाग के बजट को देखा है और यह बजट हमारी उम्मीदों की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती है महोदय । महोदय, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि "हजारों ख्वाहिशें ऐसी हो कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर कम निकले ।" तो महोदय, हमलोग जब विधान सभा में आये तो उस समय दो गठबंधन था- एक महागठबंधन और एक राष्ट्रीय गठबंधन, बीच में इस गठबंधन की अदला-बदला हो गयी और इस वक्त मुझे लगता है मेरे मूल्यांकन से कि जनता ने जो विश्वास दिया था, उस विश्वास का अपमान करते हुए यह नापाक गठबंधन है। महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए

कहना चाहता हूँ, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि सीमांचल का उपेक्षित जिला है कटिहार । महोदय, कटिहार से बलरामपुर- बारसोई जाने की एक सड़क है पथ निर्माण की, उस सड़क की लम्बाई का डाटा दिया गया है 62 किलोमीटर, सचमुच में यह सड़क 70 किलोमीटर के आस-पास है और यह सड़क बलरामपुर की जनता को, कटिहार जिला की आधी जनता महानंदा नदी से कटी हुई है और उनको कटिहार तक आने के लिए कम-से-कम चार घंटे का समय लगता है महोदय । यह सड़क, वर्ष 1977-78 में बनी हुई सिंगल सड़क है, मैं इसके चौड़ीकरण की बात बार-बार कहता रहा हूँ और इस मुद्दे पर जो पिछली सरकार थी और पिछली सरकार के जो माननीय पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने प्रथम चरण में ही सड़क के चौड़ीकरण का कार्य लिया था और अब तक यह काम शुरू हो जाता लेकिन इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ कि यह प्लाानिंग में प्रथम चरण में उन्नयन में पथ निर्माण की 6 सड़कें हैं और द्वितीय चरण के उन्नयन में आठ सड़कों में यह कटिहार- बलरामपुर की सड़क है । महोदय, कटिहार जिला बाढ़ से प्रभावित क्षेंत्र है और कदवा और बलरामपुर विषम बाढ़ की विभिषीका से प्रभावित रही है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गये थे और बारसोई से कटिहार आने के लिए चार-चार रेलवे की गुमटियां है महोदय और अगर चारों रेलवे गुमटियां से पाला पड़ जाये तो आपको कटिहार से बारसोई तक जाने के लिए और बारसोई से कटिहार आने के लिए चार घंटे का समय लगता है महोदय । मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी लेकिन मेरी उम्मीद पूरी होने की नजर नहीं आ रही है । किसी भी सुदूर क्षेत्र से पटना तक पहुंचाने के लिए उनका जो वादा था कि पांच घंटे का, मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि बलरामपुर वासियों को तीन घंटे के अन्दर पहुंचा दें ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : महबूब आलम जी, अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री महबूब आलम : बलरामपुर का तेलटा हेडक्वार्टर है महोदय, बलरामपुर प्रखंड का प्रखंड हेडक्वार्टर तेलटा है महोदय, वह सड़क जर्जर हो गयी है, 6 महीना में उसका पुल बना हुआ ध्वस्त हो गया, उस पुल-सड़क को बनाने की कृपा की जाय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : धन्यवाद आपको । आपका हो गया । शांति ।

श्री महबूब आलम : इसकी दो लाख आबादी है, एक भी पथ निर्माण विभाग की सड़क नहीं है महोदय ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : अब मैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य, योर कमिटमेंट इज फोर थ्री मिनट....

श्री महबूब आलम : इसको मैं पथ निर्माण विभाग में शामिल करने का आग्रह करता हूँ ।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव, आपका समय सात मिनट है। चार बजे से सरकार का जवाब होगा । आप सात मिनट बोलिए, दो मेम्बर और हैं ।

कृपया शांति । महबूब आलम जी, बैठ जाइए । बैठिए माननीय सदस्य । श्री प्रहलाद यादव ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, मेरा 13 मिनट समय था और आप सात मिनट कह रहे हैं।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : स्थिति के मुताबिक कटौती हो गयी है । आप आसन को सहयोग कीजिए । आप बोलिए ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, आज जो पथ निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, समय बहुत कम है, इसलिए जो हमारी क्षेत्र की समस्या है, उसी की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ । माननीय पथ निर्माण मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैंने कई एक चीज मांगा था, माननीय मंत्री जी से भी मिले थे, पदाधिकारी से भी मिले थे लेकिन आज तक निदान नहीं हुआ । एक पुल है लखीसराय में, जो किउल स्टेशन और लखीसराय स्टेशन से पड़ता है दक्षिण, इधर भी आपका रोड है और उधर भी है, दोनों के बीच में किउल नदी है । वर्षों से मांग है लेकिन आजतक पूरा नहीं हुआ है । वर्ष 2005 में इस पुल की स्वीकृति भी मिल गयी थी, हम वर्ष 2005 में हट गये, बीच में आप लोगों की सत्ता आयी और उसके बाद जो पुल का पैसा था, वह दूसरे भाग में कनवर्ट हो गया । यही हुआ, जबकि दस पंचायत चानन है और 28 पंचायत सूर्यगढ़ा है, जब रोड से आते हैं या गाड़ी से आते हैं तो पुल से मुख्यालय जाने में, अगर बन जाता है तो बहुत कम दूरी पड़ेगा और बहुत आसान होगा लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक नहीं हुआ । मुंगेर में भी समीक्षा बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी लखीसराय गये थे, वहां भी समीक्षा बैठक हुई

क्रमशः...

टर्न-21/शंभु/12.03.18

श्री प्रहलाद यादव : क्रमशः.....वहां भी आश्वासन मिला और आपके यहां से भी आपका भी पत्र आया । हमारे यहां आपका भी पत्र आया कि बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने इस योजना का अनुशंसा किया है । दूसरी बात है कि 2-3 कि0मी0 का एक मुरवरिया से ओलीपुर लखीसराय में ही पड़ता है, पथ निर्माण विभाग की रोड है । उसके लिए भी कई साल से लिखकर दे रहे हैं नहीं हो रहा है । एक क्यूल स्टेशन से जमुई जाता है, क्यूल गोपालपुर पथ निर्माण विभाग का- आपका आधा सड़क बन गया धनवा से गोपालपुर 12 कि0मी0 सड़क है ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : आसन की तरफ देखिए ।

श्री प्रहलाद यादव : वह भी नहीं बना है । एक है एन0एच0-31 गड़ही लखीसराय में पड़ता है। गड़ही से क्यूल स्टेशन 2 कि0मी का रोड है । उसका मरम्मति होना था, घनी आबादी है । दो टोला है एक हकीमगंज एक खगौल । वहां नाला बनाना था और ढक्कन से ढंकना था । एक जिला मुख्यालय लखीसराय से जमुई रोड जाती है । वह राजकीय रोड है

उसके बीच में दो घनी आबादी वाला गांव पड़ता है एक खैरी एक महसोनी । जिस समय रोड बन रहा था उस समय नाला का प्रावधान नहीं दिया परिणाम हुआ कि वर्षा होता था तो पानी से पूरा का पूरा रोड भी और गांव भी जलमग्न रहता है । यह स्थिति बनी हुई है । एक हमारे विजय भाई बोले थे, पहले तो विपक्ष में थे अभी विजय भाई मंत्री हैं । हमलोगों के मंच पर ही घोषणा हुआ था कि अब दुबारा सितम्बर या अगस्त में आयेंगे तो उस पुल का हम उद्घाटन करेंगे । अभी तक उस पुल की यही स्थिति है कि ओवरब्रिज है लखीसराय बाइपास से वह भी अभी पेंडिंग है । इस तरह से जो मेरी मांग है बहुत छोटी है । हमलोग बराबर मांगते रहे हैं लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है । इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जन महत्व की ये सब सारी योजनाएं हैं । हमलोगों का छोटा-छोटा कोई पथ निर्माण का ज्यादा नहीं है । इसलिए आपलोगों से आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से इसपर ध्यान दीजिएगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति जी को अपनी ओर हार्दिक अभिनन्दन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, चूंकि हमारा समय ही कट गया इसलिए क्या बोलें ।

सभापति(श्री मो0इलियास हुसैन) : बड़ा ही सारगर्भित भाषण के लिए आपको धन्यवाद । भारतीय जनता पार्टी माननीय सदस्य जनाब श्री तारकिशोर प्रसाद । दो मिनट है तारकिशोर बाबू आपके लिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : सभापति महोदय, पथ निर्माण विभाग आज से ही नहीं एन0डी0ए0 प्रथम और एन0डी0ए0 द्वितीय के कालखंड में पूरे बिहार का एक उज्ज्वल चेहरा रहा है। चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, लेकिन बिहार के बारे में जब कोई अच्छी बातें हुई है तो उसमें पथ निर्माण विभाग की अहम भूमिका रही है । पूरे देश में बिहार ने जो परिवर्तन की एक अंगड़ाई ली उसमें पथ निर्माण विभाग ने एक बड़ी भूमिका निभाई है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

दीघा से दीदारगंज 21 कि0मी0 लम्बा फोन लेन गंगा पथ के निर्माण के अलावा ऐसी सैंकड़ों योजनाएं हैं जो लगातार आज दिख रही है । समय की कमी है, मैं कटिहार के सवाल पर थोड़े बिन्दुओं पर अपनी बात को रखना चाहूंगा । कटिहार नगर में एक डा0 राजेन्द्र प्रसाद पथ है जो विभागीय पथ है । कटिहार में जो जाम की स्थिति बनती जा रही है, विकास के कारण जो आबादी बढ़ी है और विकास के जो कई आयाम बने हैं उसमें कटिहार में एक फ्लाइओवर का होना बहुत आवश्यक है । खासकर के मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि दो सड़कें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं उसे पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित होना आवश्यक है क्योंकि उसमें आबादी भी बढ़ी है । अभी हमारे महबूब भाई भी कटिहार पर बोल रहे थे- कटिहार, डंडखोरा, बलुआ टोला, पररिया, गोरखर सोती होते हुए कामरू तक एक लंबी पथ है। इस पथ को पथ निर्माण विभाग में हम लेने का आग्रह कर रहे हैं । कटिहार प्राणपुर पथ तक से

इमली गाछ, परतैली, पत्थलबाड़ी होते हुए हपलागंज, कुरैठा आर0सी0सी0 पथ तक का जो ग्रामीण पथ है उसे भी स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, अंत में एक मिनट । एम्स जो पटना है उससे जुड़ा हुआ विषय है । महोदय, जब पुरानी बाइपास सड़क में 70 फीट के पास एम्स के पास एन0एच0-81 तक 220 फीट सड़क का अधिग्रहण हो चुका है । लेकिन फोरलेन सड़क को शीघ्र बना देने की आवश्यकता है जिससे कि एम्स तक जाने में जो हमारे मरीज हैं जो उनके परिजन हैं उनको काफी सुविधा हो । अंत में महोदय सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि पूर्णियां, कटिहार, मनिहारी, अमदाबाद जो एक महत्वपूर्ण पथ है । जो माननीय मंत्री नन्दकिशोर यादव जी ने ही उस सड़क की स्वीकृति दी थी । उसे भारत माला योजना में आप निश्चित रूप से शामिल करना चाहेंगे । अंत में महोदय.....

अध्यक्ष : यह तीसरी बार अंत में है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, 65 कि0मी0 लंबी कटिहार छींटाबाड़ी झौवा बलरामपुर राज्यपथ 98 जिसकी चर्चा महबूब साहब ने की थी । वैसे अभी कटिहार से इनके घर तक जाने में मात्र दो घंटा लगता है, लेकिन इसका चौड़ीकरण आवश्यक है । इसका चौड़ीकरण करा दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार, 4 बजे से सरकार का उत्तर होगा इसलिए 2 मिनट में आप जो कहना चाहें कह डालिये ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, मैं पथ निर्माण विभाग के अनुदान की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आपने मुझे मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ । अपने नेता को धन्यवाद देता हूँ और पूरे जाले विधान सभा के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ । महोदय, दो मिनट में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, हमको तो माननीय मंत्री जी को लिखकर के ही देना पड़ेगा । लेकिन सदन में एक बात का दुख है महोदय कि पांच-पांच लोग आज नोमिनेशन कर गये राज्य सभा के लिए और जिस कारण से जीतन बाबा इधर से कूदकर उधर गये, उनपर कृपा नहीं किया ये परिवार प्रेमी लोग इसका हमको दुख है हुजूर । इस बात को हम कहना चाह रहे थे, लेकिन.....

अध्यक्ष : जिवेश जी, यह भी आपको पथ निर्माण का मुद्दा लगता है ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, दुख है और मौका मिला तो कह दिये । अब ललित भाई यहां बैठे हुए हैं सदन में हम अपने नेता से निवेदन करेंगे कि 20 महीना जिन लोगों ने सरकार चलायी है इस बिहार के अन्दर और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल के विधायकों को चिन्हित करके उसके काम को नहीं करने का काम इनलोगों ने किया है। हम अपने नेता से निवेदन करेंगे कि आप ऐसा नहीं करियेगा, आप राजधर्म को निभाइयेगा। महोदय, मैंने लिखित पत्र दिया पुराने पथ निर्माण मंत्री को आपको सुनकर ताज्जुब और आश्चर्य

होगा कि एक ही सड़क का आधा सड़क ओ0पी0आर0एम0सी0 में शामिल कर लिया गया और आधी सड़क में चूंकि भाजपा विधायक का था इसलिए उसको छोड़ दिया गया। श्रीमान् भोला यादव जी सदन में बैठे हुए होंगे उनके क्षेत्र का सड़क हो गया ओ0पी0आर0एम0सी0 में और वही सड़क, वही नाम एक ही सड़क आधी सड़क रह गयी, चूंकि वह दूसरे विधायक का था जो विपक्ष में बैठने का काम करता था। इसलिए हम अपने नेता से निवेदन करेंगे कि आप ऐसा नहीं करेंगे । हुजूर, आज नहीं हैं सदन में नेता प्रतिपक्ष उनको रहना चाहिए था - बजट के सुधार में अपने भाषण में वह कह रहे थे कि शराब बन्दी इतना अच्छा काम मुख्यमंत्री जी किये, इसकी चर्चा विदेश में हो रही है और वे चर्चा कर रहे थे कि पांच सौ का दारू पंद्रह सौ में मिलता है तो क्या वे पीते हैं, क्या वे खरीदते हैं, क्या वे व्यापार करते हैं, अगर इस तीन काम को वह नहीं करते हैं तो क्या उनके नॉलेज में है कि कोई बेचता है, अगर कोई बेचता है तो उसको पकड़वाने का काम क्यों नहीं करते हैं ?

अध्यक्ष : चलिए अब ।

श्री जिवेश कुमार : और अंत में हुजूर, 30 सेकेंड लेंगे । हुजूर, मिथिला पर एक कृपा कर दीजिए ।

अध्यक्ष : आप कहां-कहां शराबबन्दी पर घूम रहे हैं ।

श्री जिवेश कुमार : एक मिनट हुजूर । हम तो माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि मिथिलांचल पर एक कृपा कर दीजिए । खिरोई नदी के पश्चिमी तटबंध पर शोभन से लेकर मटिया तक थोड़ा टेक्नीकल प्रोब्लम है दो विभाग की मंजूरी की आवश्यकता है जल संसाधन से उसको लेकर कर दीजिए तो संपूर्ण मिथिला का सात-आठ जिला इससे लाभान्वित होगा और यह सुंदर सड़क बनकर तैयार हो जायेगा । आपको और पूरी सरकार को इतना सुंदर बजट देने के लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री,पथ निर्माण विभाग ।

टर्न-22/अशोक/12.03.2018

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के द्वारा वर्ष 2018-19 के अनुदान मांग प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करते हुये मुझ हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा आवागमन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के प्रयोजन से रोड नेटवर्क का सुनियोजित विकास किया जा रहा है महोदय । महोदय, आज के इस पूरी चर्चा में 15 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं महोदय और जो लोग विचार व्यक्त कर रहे थे, दो प्रकार के भाव उजागर हो रहे थे । मैं उस भाव की चर्चा जरूर करना चाहता हूँ,

एक भाव जो इधर से आ रहा था, लग रहा था कि बैचेनी है महोदय, लग रहा था कि हाहाकार है महोदय, जब मैं हाहाकार मैं देख रहा था महोदय तो मुझे चाणक्य की एक पंकित याद आ गई । मैं जरूर आपके सामने कहना चाहता हूॅ । महोदय, चाणक्य ने कहा था " विरोधियों के टोली में अगर हाहाकार हो तो समझ लो देश का राजा महान और चरित्रवान है और देश प्रगति पथ पर अग्रसर है " महोदय । महोदय इसका प्रमाण भी है । विरोध के स्वर आ रहे हैं तो आने भी चाहिये, विरोधी पार्टी में है तो विरोध तो करेंगे ही करेंगे । लेकिन महोदय विरोध के स्वर के साथ साथ एक बात का भरोसा भी उनके मन के अन्दर था कि अगर हम अपने क्षेत्र के समस्याओं के बारे में नंद किशोर यादव को बतलायेंगे, पथ निर्माण विभाग के मंत्री को बतलायेंगे मेरा समाधान हो जायेगा, यह भरोसा भी था उनके मन में । यह मेरे लिये प्रसन्नता की बात है, मुझे यह आनन्द देता है, लोगों ने कहा है कि परिश्रम के पसीने से जब सफलता के फसल खिलती है तब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाइयां मिलती है, मुझे मिलेगी महोदय, मैं जानता हूॅ । महोदय, जब चर्चा हो रही थी रामदेव बाबू से शुरू हुई, दूर दूर तक गई और पूरी चर्चा में एक बात का और बड़ा प्रचार किया गया महोदय, मैं उसकी चर्चा आगे करूंगा, अभी नहीं करूंगा । प्रारम्भ में करूंगा तो सब छोड़ कर भाग जायेंगे । महोदय, झूठ का पहाड़, महोदय झूठ का पहाड़ खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं उसकी चर्चा मैं थोड़ा बाद में करूंगा ।(व्यवधान) महोदय, मैं सभी के बारे में जवाब दूंगा और सब माननीय सदस्यों ने जो एक बात कहा है, मैं विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि ये शब्द वापस ले लीजिये । राज्य सराकर, वर्त्तमान बिहार सरकार कभी भी इस बात का विचार नहीं करती है कि पथों के निर्माण के बारे कोई भेद भाव किया जाय किसी मेम्बर के साथ, किसी इलाके के साथ- मैंने कभी नहीं किया और महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूॅ महबूब आलम जी ? आपने जिस सड़क के बारे में बात की है, आप विश्वास करिये, इसका डी.पी.आर. बन रहा है, इसमें जमीन की आवश्यकता है मुझे आपकी मदद की आवश्कता है महोदय, मैं चाहूंगा कि उसमें 80 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, उस प्रोजेक्ट को शामिल किया है स्टेट हाई वे बनाने के लिए और मैं कोशिश कर रहा हूॅ भू-अर्जन के लिए कैसे न्यून किया जाय मैं इसका प्रयास कर रहा हूॅ । महोदय, मैं केवल कह रहा था एक बात का मन से विचार निकालिये मैं इसलिये कह रहा हूॅ कि विकास जाति नहीं देखता है, विकास क्षेत्रवाद नहीं देखता हे, विकास विकास चाहता है । और जिस समय हमलोगों ने विकास का कार्य प्रारम्भ किया 2005 में माननीय मुख्यमंत्री के इस बार के नेतृत्व में, क्या हाल था, मैं उस बात को आज दुहराना नहीं चाहता हूॅ। आप को, खुद को एहसास है इस बात का । मैं उसको नहीं कहना चाहता ।

लेकिन आप याद कीजिये, उस समय मैंने दो निर्णय किया था, मैंने एक निर्णय किया था कि हम जिस सड़क को बनायेंगे उस सड़क की पूरी लम्बाई में बनायेंगे । बैठे हुये हैं इलियास साहब, इनके विभाग का बजट कितना होता था, इनको मालूम है, आपके मालूम होगा । वे बना नहीं पाते थे बजट कम था लेकिन जब हमारी सरकार बनी, विकास वाली सरकार बनी तो विकास वाली सरकार ने तय किया कि हम जो सड़क बनायेंगे पूरी लम्बाई में बनायेंगे, चाहे वह 60 कि.मी. हो, 80 कि.मी. हो, 100 कि.मी. हो और जब सड़कें पूरी लम्बाई में बनेगी महोदय तो विधायको का चेहरा नहीं देखेगी महोदय, पार्टी का चेहरा नहीं देखेगी महोदय, विकास का चेहरा देखेगी, हमने वह उदाहरण पेश किया है । इसलिये आपकी जो चिंता हैं, आप चाहेंगे तो एक-एक उठाये गये प्रश्नों के बारे में बतला सकता हूँ कि हमने क्या निर्णय लिया है । इसमें समय ज्यादा लगेगा, अगर समय बचेगा तो मैं जरूर आपके प्रश्नों का जवाब, एक-एक प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करूंगा । मैं महोदय जेनरल बात करना चाहता हूँ । महोदय, आप जानते हैं कि जब हम पहली बार सरकार में आये, एक बात जान लें लोग, ये जब-जब हम साथ हाते है तो एक नया रास्ता बनता है और किसी ने ठीक ही कहा महोदय, और यह विश्वास है लागों का महोदय, साथ है तो विश्वास है और हो रहा है विकास महोदय, यह विकास, विकास सब का साथ सब का विकास तो है ही महोदय, न्याय के साथ विकास है । महोदय, यह जो विकास है महोदय यह विकास सब को साथ लेकर चलने है वाला विकास । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ पहली बार जब सरकार में आये तो आपको याद होगा महोदय(व्यवधान) महोदय, जब हम पहली बार सरकार में आये तो महोदय, हमलोगों ने तय किया था कि(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलिये न मंत्री जी ।

(व्यवधान)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : हम आयेंगे, जवाब देंगे, बैठिये न । बतायेंगे । महोदय, में इनकी बैचेनी समझ रहा हूँ, ये जानते हैं कि जब झूठ का पहाड़ खुलेगा तो क्या हाल होगा इनको, इनको मालूम है । अभी कह दूंगा तो आगे क्या करूंगा । विचार करिये, मैं कहूंगा । महोदय, मैं कह रहा था हमलोग पहली बार जब सरकार में आये तो हमलोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर तय किया कि हम बिहार में सड़को का जला बिछायेंगे, पुल पुलिया का विकास करेंगे महोदय, और हमलोगों ने तय किया सुदूर इलाके से कोई पटना आना चाहे, जब राजधानी आना चाहे, राजधानी आये तो उसको छः घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिये महोदय इस निश्चय के साथ हमलोगों ने अपना काम प्रारम्भ किया और आप जानते हैं कि बाद के दिनों में हमलोगों ने छः घंटे का लक्ष्य पूरा किया, जब छः घंटे का लक्ष्य पूरा हो

गया तो माननीय मुख्यमंत्री ने फिर से निर्देश दिया महोदय, कि अब इस समय को और कम किया जाय, अब पांच घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया । काम प्रारम्भ हुआ है महोदय, (व्यवधान) ठीक है, अभी के समय में हुआ, आप कुछ नहीं बाकी हम कर रहे हैं । आप चिता मत कीजिय, आपने जो किया मुझको मालूम है । अरे कुछ तो फूल खिलायें हमने, हमें और कुछ फूल खिलाने हैं, मुश्किल यह है कि बाग में अब तक कांटे पुराने हैं । महोदय, मैं कांटों को चुन-चुन कर निकाल दूंगा महोदय, चिंता मत कीजिये महोदय । लेकिन मैं बिहार की जानता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाहे कांटे कितना भी तंग करने की कोशिश करे, फूल खिलते रहेंगे महोदय और खुशबू देते रहेंगे महोदय । हम काम करते रहेंगे, विकास करते रहेंगे । महोदय, हम लगातार एक योजनावार ढंग से पांच घंटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महोदय, हम काम कर रहे हैं । और जो महोदय जो काम कर रहें हैं, कई मित्रों ने बहुत हमारे बड़ी अच्छी चर्चा की है महोदय इसकी सराहना करता हूँ, जो व्यवहारिक कठिनाइयां है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि एक सड़को का चौड़ीकरण का सवाल, इन्टमिडियेट लेन को टू लेन में बदलने का सवाल, सिंगल लेन को इन्टरमिडियेट लेन में बदलने का काम महोदय, एक साल में नहीं हो सकता हैं, जो अनुभवी लोग है वे जानते हैं । इन सब के निर्माण के लिए बड़ी धन राशि की आवश्यकता होगी, और सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हम क्रमवार ढंग से काम करेंगे । महोदय, अगर सारे पथों का निर्माण कार्य पूरा हो जाय इस साल में तो पथ निर्माण विभाग आगे से क्या करेगा महोदय ? ऐसा कभी होता नहीं है, कहीं विश्व में ऐसा नही होता है महोदय कि एक ही साल में और महोदय मुझे ये ओलाहना दे रहे हैं महोदय, मैं तो जुलाई में आया हूँ, में जुलाई में आया और आप सब जानते हैं कि पथ निर्माण विभाग के कार्य जुलाई से लेकर नवम्बर-दिसम्बर तक बंद हो जाते हैं बारिश के कारण महोदय तो मुझे तो तीन-चार महीना हुआ आये हुये तो तीन चार महीना का क्या हिसाब ले रहे हैं ललित बाबू, आपने क्या हिसाब लिया मैं जरूर उसका जिक्र करना चाहता हूँ । ललित बाबू की बात कह कर आगे बढ़ूंगा और महोदय मैं ललित जी को कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसे सवाल, अधूरे सवाल आपको नहीं करना चाहिये । हो सकता हैं कि आपको तेजस्वी जी से चिढ़ हो, हो सकता है नाराजगी आपको हो लेकिन सदन के अन्दर अपने नेता को कठघरा में खड़ा करने का आपने प्रयास किया है यह मेरी लिए आश्चर्य का विषय है । महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि इन्होंने महोदय एक एक्सक्यूटिव इंजीनियर की चर्चा की थी, उस समय महोदय आप नहीं थे, मननीय इलियास साहब थे चेयर पर, उन्होंने कहा था कि एक्सक्यूटिव इंजीनियर हैं नगर विकास

विभाग में जिस पर नगर विकास विभाग ने कार्रवाई के लिए लिखा, महोदय पथ निर्माण विभाग में आया, मैं नहीं था उस समय, मैं नहीं था पहले की बात हैं, लेकिन पथ निर्माण विभाग ने जो स्पष्टीकरण दिया था उसको फिर से उन्होंने मंतव्य के लिए नगर विकास में भेजा और नगर विकास विभाग ने महोदय उस स्पष्टीकरण को, इंजीनियर के स्पष्टीकरण को योग्य मान लिया, स्वीकार कर लिया और महोदय और वो जो जब पथ निर्माण विभाग में आया महोदय तो उसकी दरभंगा में प्रतिनियुक्ति 2016 में हुई ।...

... क्रमशः...

टर्न-23/12-03-2018/ज्योति

क्रमशः

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : वो जो पथ निर्माण विभाग में आया तो दरभंगा में उसकी प्रतिनियुक्ति 2016 में हुई और तब से वह दरभंगा पथ प्रमंडल की हालत है । 2016 में मैं नहीं, आपके नेता पथ निर्माण विभाग के मंत्री की कुर्सी पर बैठे थे आप इसका ध्यान रखिये । मैं जानता हूँ कि आर.जे.डी. में आपकी उपेक्षा हो रही है, इसका यह अर्थ नहीं है कि सदन के अंदर अपने नेता को आप कटघरे में खड़ा करिये, यह अपेक्षा मुझे आपसे नहीं थी । ये लोग मुझे भटकाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं रास्ते पर आते रहूँगा। आप चिन्ता मत करिये । महोदय, मैं कह रहा था फिर से विकास का एक नया दौर प्रारम्भ हुआ है । बिहार की जनता के मन के अंदर फिर से इस बात का भरोसा जगा है कि वर्तमान सकार है, जिस सरकार ने बिहार के विकास की एक नयी कहानी लिखी है। जिस सरकार ने विकास के अंदर सड़कों, पुलों के निर्माण के बारे में पूरे देश के अंदर एक नया मानक बनाया था महोदय, फिर से यह जोड़ी आ गयी है बिहार में तो लोगों को लग रहा है कि और कुछ होगा और आगे बढ़ेगा और काम होगा । मैं विश्लेषण करुंगा महोदय, लेकिन आज कल ये लोग डबल इंजन की बात ज्यादा कर रहे हैं, आजकल ये लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं, पैकेज की बात करते हैं । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो बिहार का विकास है । कोई भी राज्य सरकार आप जानते हैं कि सड़कों के मामले में तीन प्रकार की सड़के होती हैं । एक तो नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, एम.डी.आर. होता है । नेशनल हाई वे के निर्माण का सारा खर्चा भारत सरकार देती है- स्टेट हाईवे और एम.डी.आर. हम बनाते हैं और राज्य के अंदर नेशनल हाई वे का निर्माण अगर ठीक से नहीं हो, उसका विकास नहीं हो, तो सड़कों का विकास दिखता नहीं है । महोदय, इसलिए एक मेरे मित्र ने कहा । एक बात याद करिये, आपने अच्छी बात कही । जब बिहार में पहली बार सरकार में आए महोदय, नेशनल हाईवे की हालत बड़ी बुरी थी । मुख्यमंत्री ने कहा मुझे अगर नेशनल हाईवे का

निर्माण नहीं होगा, उसकी मरम्मती नहीं होगी, तो लोगों को बिहार की सड़क विकसित होते हुए नहीं दिखायी देगी । मैं तो गुहार लगाया दिल्ली के अंदर लेकिन जो उस सरकार में थे, जो सरकार आपके भरोसे काम कर रही थी, उस सरकार ने मुझे पैसा नहीं दिया । 900 करोड़ से अधिक राज्य सरकार ने भारत सरकार की सड़कों पर खर्च किया । जब ये सरकार में दिल्ली में शामिल थे, इनके भरोसे सरकार चल रही थी और आज बात कर रहे हैं सड़कों की । किसने विरोध किया ? उसी राज में उसी सरकार में जब मैंने गुहार लगाया कि पैसा दो, मुझे वापस करो, उस सरकार ने फाईल पर लिख दिया कि पैसा नहीं दिया जा सकता है और आप अभी कह रहे हो, मांगने की बात । हम सब बता देंगे । महोदय, ये लोग पैकेज की बात करते हैं। मैं चाहता था कि नेता प्रतिपक्ष बैठते तो मैं बहुत सारी बातें कहते । महोदय, आज ये लोग आलोचना करते हैं । आज प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हैं लेकिन जब पथ निर्माण मंत्री जी यहाँ बैठते थे, इनके तो प्रशंसा करते थे भारत सरकार की । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ । मेरे पास जब तेजस्वी यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे महोदय, उनका बजट भाषण है मेरे पास, मैं पढ़कर उसको सुनाना चाहता हूँ । उन्होंने कहा है ''मुझे सदन को जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि इन प्रयासों के फलस्वरुप राष्ट्रीय उच्च पथ उप भाग का आवंटन वर्ष 2015-16 के 848 करोड़ की तुलना में 2016-17 में बढ़कर दुगुणा अर्थात् 1548 करोड़ कर दिया गया है । इसी प्रकार एन.एच.ओ. प्रोग्राम के तहत एन.एच. के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का लक्ष्य 120 कि.मी. से बढ़ाकर ढाई गुणा अथात् तीन सौ कि. मी. कर दिया गया है । महोदय, मैं सदन को आश्वासन देना चाहूँगा कि माननीय नितीन गडकरी जी ने मुझमें और मेरी सरकार में जो विश्वास व्यक्त किया है हम उस पर पूरी तरह खरे उतरे हैं ।

(व्यवधान)

मैं वही कह रहा हूँ । महोदय, मैं वही कह रहा हूँ । आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं । मैं स्वीकार करता हूँ तेजस्वी जी गए, वहाँ वही जाते थे और जाकर प्रयास किया लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं.....

(व्यवधान)

जानकारी कुछ सीख लो अच्छा होगा, आगे भविष्य में काम आयेगा । यह ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि वे गए महोदय, जाता तो मैं भी था, जाते तो नीतीश कुमार भी थे, 10 साल लेकिन 10 साल में क्या हुआ ? लेकिन यह नरेन्द्र मोदी की सरकार का परिणाम था, एक बार जाता है वह मंत्री, जिसमे विरोधी पार्टी की सरकार है, लेकिन तब भी महोदय, बिहार के विकास के लिए एन.डी.ए. की सरकार की परिपक्वता के कारण भारतीय जनता पार्टी का मंत्री सहर्ष बिहार के विकास के लिए बड़ी धन राशि देता है । यह इसका प्रमाण है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, बिहार विधान सभा का पुस्तकालय इस बात का गवाह है देश के तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री टी.आर.बालू जी ने इसी सचिवालय में आ कर 904 करोड़ रुपया दिया था । आपको याद होना चाहिए ।

अध्यक्ष : मंत्री जी आप बोलिये ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैं कह रहा था । ये लोग पैकेज की बात करते हैं । मैं भूल गया उस पैकेज को । मैं उन्हीं की भाषण को कोट करना चाहता हूं महोदय । मैं चर्चा करुंगा । चलिए मैं आगे चर्चा करुंगा । महोदय, मैं कह रहा था कि ये लोग पैकेज की चर्चा कर रहे थे । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने जो बिहार को पैकेज घोषित किया महोदय, उसमें 54,700 करोड़ रुपया केवल बिहार के सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए । यह बड़े गर्व की बात थी । होना क्या था महोदय, यह जो पैकेज था, पता नहीं उस समय के लोग क्या चाहते थे, महोदय, उस समय के लोगों के मन में था 54700 करोड़ मेरे पास आ जाय, हम अपने कलम से उसका हिसाब करें, हम टेण्डर करें, आवंटन करें । बेचैनी इसी की थी महोदय । भारत सरकार ने तय किया, भारत सरकार का पैसा है एन.एच.आई. बनायेगा । एन.एच.आई. बनायेगा और यह जा.....

श्री विजय प्रकाश: माननीय प्रतिपक्ष के आज जो नेता हैं वही सबसे पहले सवाल उठाये थे कि यह जो टेण्डर की प्रक्रिया होती है, वह अफसरों तक ही रहेगी, मंत्री तक नहीं जायेगा ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, विजय प्रकाश जी को अधूरी जानकारी है । उन्होंने नंद किशोर यादव का इतिहास नहीं पढ़ा है और नंद किशोर यादव जब पथ निर्माण विभाग में था, तो कौन सा नियम लागू था, इनको पता नहीं है । तेजस्वी यादव जी ने केवल मेरे बनाए गए नियम का पालन किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है । मैं आगे बढ़ रहा हूँ महोदय । महोदय, मैं कह रहा था आपसे कि यह जो पैकेज है 54,700 करोड़ से बिहार के अंदर लगभग 82 योजनाओं का कार्यान्वयन होना है । इन 82 योजनाओं में 45 योजनाओं की निविदा महोदय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है, कार्य आवंटित कर दिया गया है और अधिकांश योजना में काम प्रारम्भ हो गया है । 12 योजना ऐसी है, जिसकी या तो निविदा हो गयी या निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है और 25 योजनाएं ऐसी है, जिसका डी.पी.आर. बनाना है और प्रक्रिया में है, वह चल रही है । महोदय, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनको जानकारी होनी चाहिए कि यह जो पैकेज था, इस पैकेज में 30 हजार करोड़ रुपये का करीब बनाना था एन.एच.आई. को और 24,000 करोड़ रुपया का बनाना था एम.ओ0आर. टी.एच. को जो बिहार में एन. एच. डिवीजन है, उसके माध्यम से इन सब पर डी.पी.आर. बनने थे । चिन्ता आपको होनी चाहिए कि भारत सरकाार के पास पैसे के लिए, दर दर भटकते थे, उनके पास भीख मांग कर आते हैं, उस सरकार ने पैसा दिया और हमने डी.पी.आर. तक नहीं

बनाया और उसके डी.पी.आर. बनाने की प्रक्रिया भी हमने प्रारम्भ की और आप कहते हैं कहॉ हैं पैकेज, तो चर्चा करते हैं गांधाी सेतु का, अरे भाई और आपके नेता, प्रतिपक्ष भी कहते हैं, कहॉ है पैकेज ? इस पैकेज में गांधी सेतु के जीर्णोद्धार का काम शामिल है । जिसके पास आंख नहीं होगा, वह भी कहेगा कि गांधाी सेतु के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। अरे, कौन सा काम चल रहा है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : जीर्णोद्धार का काम पैकेज में आता है देश के अंदर कहीं भी माननीय मंत्री जी ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : मैं बताता हूँ । महोदय, दर्द है बड़ा मन के अंदर । महोदय, गांधी सेतु जब बना महोदय, 1982 में पहला लेन बना है, 1987 में दूसरा लेन बना और 1991 से ही उसमें मरम्मत की आवश्कता महसूस की गयी लेकिन महोदय जब तक वहॉ कौंग्रेस की सरकार रही, पैसा नहीं मिला, जब अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार आयी, तो पैसा मिला रिपेयर के लिए और बाद में जब उसका सर्वे हुआ महोदय, यू.पी.ए. की सरकार में, तो लोगों ने कहा कि जब यह सुपर स्ट्रक्चर जब तक बदलोगे नहीं आप, इसका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है लेकिन उसमें यू.पी.ए. की सरकार ने टुकड़े टुकड़े में पैसा दिया । कभी 20 करोड, कभी 30 करोड़, कभी 35 करोड़- पैसे खर्च हुए लेकिन उपयोग ठीक नहीं हुआ महोदय, लेकिन यह एन.डी.ए. की सरकार थी, नरेन्द्र मोदी की सरकार थी, अगर लोगों ने कहा कि पूरा सुपर स्ट्रक्चर बदलना चाहिए, तो एक साथ पूरे सुपर स्ट्रक्चर को बदलने के लिए एक साथ राशि आवंटित किया । यह हमारी सरकार है। यह विकास समर्थित सरकार है । बोलो नहीं बीच मे, नहीं तो फंस जाओगे । महोदय, मैं कह रहा था, पैकेज का अर्थ क्या समझते हो भईया मालूम नहीं । पैकेज का अर्थ समझते हो कि बैग में कोई आपको दे देगा, तो अलग बात है ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन : विस्तार में वह बता चुके हैं कि पैकेज के नाम पर बिहार के लोगों के साथ किस तरह का धोखा दिया गया है ।

अध्यक्ष : आप बोलिए मंत्री जी ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैं कह रहा था कि पी.एम. के पैकेज में सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसकी चर्चा तो मैने किताब में किया है । किताब की बात दुहराना नहीं चाहता । बैठ जाओ भईया । बैठिये न बताते हैं ।

(व्यवधान)

सब बातों का जवाब पहले यहॉ पूछ लेना चाहिए था आपको ।

क्रमशः

टर्न-24/12.3.2018/बिपिन

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्रीः ...क्रमशः ... महोदय, जिन लोगों के पास, महोदय इनका दर्द स्वाभाविक है महोदय । बीस महीने में जो समाधान नहीं करा सके, अब इनको चूंकि समाधान मुझसे कराना है थोड़ा मन के अंदर गुस्सा है । शांत कर लो, हम पूरा करेंगे यार ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पी.एम. पैकेज में पांच सौ किलोमीटर सड़क को शामिल किया, पैकेज, इस बात की चर्चा हुई थी कि एन.एच. के पांच सौ कि0मी0 सड़क को शामिल करके बिहार सरकार तय कर दे कौन-कौन सड़क शामिल होगा । रामदेव बाबू सुनिये, आपकी बात कर रहा हूं मैं । तो पी.एम.पैकेज में पांच सौ कि0मी0 सड़क को चयनित करे मुझे भेजना था जो उस पैकेज के तहत बनेगा तो महोदय, यह 12 सड़कें हमने चयनित की है । पता नहीं रामदेव बाबू क्यों नाराज रहते हैं महोदय । इस 12 सड़कों की सूची में महोदय, पहला सड़क, नंबर वन, हाजीपुर से बछवाड़ा भाया महनार, मोहद्दीनगर ,यह चयनित करके हमने भेजा । इसका डी.पी.आर. बनाकर भेज दिया । अब उसका टेंडर होगा और पी.एम. पैकेज से उसके निर्माण का कार्य होगा महोदय । महोदय, उसके अलावा गावा, सदगावा, गोविंदपुर, फतेहपुर, महोदय, नवादा जिले से झारखंड को जोड़ने के लिए एक सड़क का काम किया जा रहा है महोदय, उसको भी हमलोगों ने एन एच में हमलोग घोषित किया महोदय और उसमें हमलोगों ने ककोलत को भी उसके साथ कनेक्ट किया है महोदय । उसके अलावा महोदय पंडुगा में पुल के निर्माण की बात लोगों ने की थी, वह भी उसमें शामिल है महोदय । भागलपुर से ढाका मोड़ होते हुए हॅसडीहा, उसके बाद चौतरवा, धनहा, दमकुआ बाजार, बंशी, पडरौना, जपला, बंगवा, नवीनगर, वारून, रोसड़ा, दरभंगा, मेहसीझापा भाया तेतरिया, सीवान, महाराजगंज, जनता बाजार, बनियापुर, सुन रहे हैं, सुनवे नहीं करिएगा तो कैसे होगा, आपके सड़क का नाम लेते हैं, सुनिये विजय जी, जमुई से खड़गडीहा, चकौर, सारवा, चकाई रोड, सरायगंज, लालगंज, गणपतगंज, महोदय, यह 12 सड़कें ऐसी हैं जो पांच सौ किलोमीटर के घेरे में आ रही थी । इसको हमने डी.पी.आर. बनाकर भेज दिया है महोदय । आने वाले दिनों में ये भारत सरकार के माध्यम से निर्माण का काम किया जाएगा ।

महोदय, इसके अलावा ....

(व्यवधान)

महोदय, इसके अलावा भारत माला योजना के तहत महोदय, भारत सरकार ने कई और प्रमुख सड़कों का पुल निर्माण का निर्णय लिया है महोदय । मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि कि औरंगावाद से दरभंगा तक ...

(व्यवधान)

बैठ जाइए न, समझ गए, बैठ जाइए । बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

महोदय, मैं कह रहा था, महोदय बिहार को दक्षिण उत्तर की ओर जोड़ने के लिए हमने पहले भी कोशिश की थी महोदय कि साउथ-नॉर्थ कॉरिडोर बनाएंगे महोदय, लेकिन भारत माला योजना के तहत मेरा सौभाग्य है कि भारत सरकार इसकी स्वीकृति दे दी है । महोदय, औरंगाबाद से दरभंगा एक सड़क के निर्माण का काम, फोर लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा महोदय और हमने भारत सरकार से आग्रह किया है कि इस सड़क को आप बढ़ा करके इसको आगे जयनगर तक बढ़ा दीजिए ताकि औरंगाबाद, सीधे हम नेपाल के बॉर्डर पहुंचने का काम करें महोदय और महोदय, इसका मैंने एलायन्मेंट भी तय किया है महोदय । यह औरंगाबाद से चलेगा, जहानाबाद होते हुए जहानाबाद में बाइपास पर आएंगे महोदय, वहां से होते हुए कच्ची दरगाह, विदुपुर पार करते हुए ताजपुर से दरभंगा होते हुए जयनगर तक यह पथ जाएगा महोदय । उसी की योजना के तहत एक और भारत माला में सासाराम-पटना, यह भी एक सड़क भारत सरकार ने स्वीकार किया है, पता नहीं, मेरे मित्र कहां गए ? बड़े गुस्से में थे । सुनिये, ऐ आरा के माननीय विधायक जी, सुनो भाई, आपके काम की बात करता हूं तो सुनते ही नहीं हो आप । महोदय, सासाराम से पटना एक सड़क फोर लेन बनाने का भारत सरकार ने भारत माला के तहत तय किया है, हमने उसका भी मार्गरेखन महोदय, तय कर दिया है। वह सासाराम से चलेगा महोदय और जब आरा आएगा, तो आरा के उत्तर में तो हमारा फोर लेन पहले से सड़क चयनित है जो पटना से जाने वाला है, वहां बक्सर तक तो मैंने इस सड़क के बारे में तय किया है कि आप सासाराम से आरा आइएगा और आरा के दक्षिन से बाइपास बनते हुए यह बिहटा आएगा, वहां से मनेर जाएगा और मनेर से फिर जे.पी.सेतु होते हुए यह आगे का रास्ता अपना तय करेगा, यह हमने अभी सड़क का रेखन महोदय, तय किया है....

(व्यवधान)

बैठिये, बैठिये, महोदय । रजौली-बख्तियारपुर और आरा-मोहनिया, यह दो ऐसा कोढ़ था महोदय, यह कोढ़ के लिए मैं किसी और को दोषी नहीं मानता हूं । ये दोनों सड़कों के फोर लेन का निर्णय महोदय, मैंने खुद लिया ।

(व्यवधान)

अरे बैठो न यार । बैठो । इनलोगों की आवाज तो अकेले हम दबा देंगे, तुम लोग क्यों जोर लगा रहे हो ?

(व्यवधान)

बैठिये न ! महोदय, रजौली-बख्तियारपुर, बैठिये, महोदय, रजौली-बख्तियारपुर सड़क बना ही नहीं, तो उसका क्या जांच कराना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

महोदय, मैं कह रहा था कि रजौली-बख्तियारपुर और आरा-मोहनिया, ये पूरे सदन की चिंता का विषय है महोदय और मैं इसमें किसी को दोष नहीं देता महोदय । चूंकि मैं खुद भी जब पथ निर्माण मंत्री था, मैंने उन दोनों सड़कों के फोर लेन का निश्चय किया था महोदय । मैंने कोशिश की महोदय लेकिन संयोग से मैं बीच में मैं हट गया, नहीं बन पाया, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं आपको और सदन को बताना चाहता हूं कि यह जो रजौली-बख्तियारपुर सड़क है, उसके फोर लेन के निर्माण का निर्णय भारत सरकार ने कर लिया है और जब तक वह फोर लेन का, अभी डी.पी.आर. वगैरह बन रहा है और जब तक यह निर्माण का काम नहीं होगा, तब तक उसके रिपेयर का काम प्रारंभ हो जाए, यह रजौली-बख्तियारपुर में काम प्रारंभ हो गया है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है । जून-जुलाई तक उसके रिपेयर का काम पूरा हो जाएगा महोदय । महोदय, आरा-मोहनिया, भारत सरकार के यहां गए थे ये लोग, हमारे पहले के जो हमारे माननीय मंत्री थे आरा-मोहनिया को कहने गए थे कि भारत सरकार ले ले । भारत सरकार ने एक ही बात कहा महोदय, उसमें डिस्प्युट था तो भारत सरकार ने बार-बार उनको कहा कि आप डिस्प्युट खतम करो या उसकी लायबिलिटी ओन करो, हम ले लेंगे, हम बना देंगे । लेकिन महोदय, पता नहीं विभाग कैसे चलता था, मुझे मालूम नहीं है । इन लोगों ने उस काम को पूरा नहीं किया लेकिन अब आरा मोहनिया के अंदर जो डिस्प्युट है, उस डिस्प्युट के समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं, साथ-साथ बिहार सरकार ने भारत सरकार को लिख कर दे दिया है कि इसमें डिस्प्युट में अगर कोई लायबिलिटी बिहार सरकार पर आएगी तो बिहार सरकार उसको ओन करेगी और भारत सरकार लेने के बाद सड़क को अपने अंडर में ले लिया है । महोदय, उसके निर्माण का काम शीघ्र प्रारंभ होगा । उसके रिपेयर का डी.पी.आर. बनने का काम शुरू हो गया है । जून महीने तक महोदय, उसका टेंडर पूरा हो जाएगा। 2018 में उसके रिपेयर का काम प्रारंभ होगा और उसके एक साल के बाद उसके फोर लेन का भी काम होगा महोदय ।

(व्यवधान)

मैंने कहा कि उसके अगले साल फोरलेन का भी काम प्रारंभ होगा, उसका भी डी.पी.आर. बनेगा । महोदय, पहले उसको बराबर करना है । कष्ट होता है ।

(व्यवधान)

बैठिये, बैठिये । बोल लेने दीजिए । आधा घंटा हो गया भईया । अभी बोलने दीजिए न । (व्यवधान)

सुन तो लीजिए न ! उन्नीस मुद्दे पर बोलना है, अभी तीन ही पर आए हैं । बताइए कैसे बोलेंगे ?

महोदय, आप गोपालगंज की चिंता मत करिए । गोपालगंज में एलिभेटेड रोड हम बना देंगे ताकि आपको कठिनाई नहीं हो ।

महोदय, पटना से, आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री, जब गडकरी जी आए थे, मेरे मित्र कहते हैं कि साहब, कई बार हमारे मंत्री गए, उसमें भारत सरकार के मंत्री से मिलने । आप कई बार गए ? अंतर यही है दोस्त । यह विश्वसनीयता का अंतर है । आपके मंत्री को बार-बार वहां दरवार करना पड़ता था लेकिन हमारे सरकार की विश्वनीयता है कि वो मंत्री बिहार आते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर चर्चा करते हैं । यह अंतर है विश्वास का । यह विश्वास का अंतर है ।

महोदय, मैं कह रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी इच्छा थी, अच्छी बात भी है, महोदय, भारत सरकार एक सड़क बना रही है जो गाजीपुर से लखनऊ होते हुए, लखनऊ से दिल्ली सड़क बनी है, गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ेगी । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि भाई, यह गाजीपुर से जोड़ेगी तब पटना का क्या होगा ? तो बक्सर से गाजीपुर को जोड़ने का भी काम एक्स्प्रेस-वे से किया जाए ताकि पटना-बक्सर फोर लेन बन ही रहा है तो पटना से सीधे गाजीपुर, लखनऊ होते हुए दिल्ली जाने का एक नया मार्ग बिहार के लोगों को उपलब्ध हो जाएगा । महोदय, इसके लिए भारत सरकार सहमत हो गई है । उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है ।

दूसरा महोदय, हमलोग का बनारस से बड़ा लगाव है । बनारस अनेक प्रकार की चीजों के लिए विख्यात भी है महोदय, तो बनारस कैसे नजदीक पड़ जाए और नजदीक लोगों को कैसे हो जाए, इसीलिए पटना से बनारस एक नया मार्ग बन जाए, इसके लिए भारत सरकार से हमलोगों ने अनुरोध किया है और भारत सरकार का रूख सकारात्मक है ।...क्रमशः...

टर्न-25/कृष्ण/12.03.2018

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री (क्रमशः) महोदय, रामजी का नाम लेंगे तो बिगड़ जायेंगे लोग । हमलोग सीताजी वाले हैं । महोदय, हमलोगों का सौभाग्य है, इस देश के लोग, जिनको भगवान मानते हैं, उस भगवान के बगल में जो महिला बैठती है, वह महिला बिहार की बेटी है, हमारी मां है, सीता मां है । लेकिन सीता स्थान का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था, वह अबतक प्रोपर नहीं हो पाया है । महोदय, बड़ी संख्या में हर साल, जब मैं मंत्री नहीं था, उसके पहले जब मैं विधायक था, तो उस समय मैं देखता था दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में सीता स्थान जनकपुर की ओर जाना चाहते थे । महोदय, उनके मन में धारणा थी कि भगवान श्रीराम जिस मार्ग से अयोध्या से मां सीता को वरण करने के लिये गये थे, उस सड़क मार्ग से ही ये लोग वहां जाना चाहते थे । लेकिन सब जगह रास्ते नहीं थे । उनको टेढ़े-मेढ़े रास्ते से होकर उनको जाना

पड़ता था । महोदय, मुझे आपको बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने, भारत सरकार ने एक नये रास्ते के निर्माण का निर्णय लिया है । महोदय, जो रास्ता अयोध्या छावनी से प्रारंभ होगा, वहां मौड़ाखास, रीयलसफी कलवारी, बरहज, रोपणछपरा, मेहरौना घाट से गुठनी, बिहार में प्रवेश करेगा और वहां से मैरवा, सीवान, मसरख, सत्तरघाट, केशरिया, चकिया, शिवहर, सीतामढ़ी, सुरसंड होते हुये महोदय जनकपुर के निकट वह भारत नेपाल सीमा पर जायेगा और भारत सरकार ने इस पथ का नाम दिया है राम जानकी पथ ताकि अगर कोई रामजी के अयोध्या से निकल करके जानकी जी के स्थान तक जाने का उन्होंने जो मार्ग चुना था, उस मार्ग पर एक पक्की और अच्छी सड़क बनाने का काम सरकार करेगी ताकि जो लोग अपनी आस्था प्रकट करना चाहें, वह पूरा हो सके । महोदय, इसका डी0पीआर0 बनाने का काम शुरू हो गया है और आनेवाले दिनों में इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा ।

महोदय, मिथिला के लोग बैठे हैं । मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि जो भगवती स्थान, उचैठ है, वहां से भी बेनीपट्टी, मधुबनी होते हुये भेजा के पास जायेगा और कोसी नदी पर भेजा पर एक नया पुल निर्माण होगा और वहां से मेहशी, बंगाल, बरियाही होते हुये सहरसा तक जायेगा । यह जो उत्तर बिहार के अंदर विशेष कर मिथिलांचल के अंदर ।

(व्यवधान)

लगता है कि आपको भगवान बुद्ध की धरती से कोई मतलब नहीं रहा । अगर मतलब रहता तो आप यह नहीं कहते । वह तो मैंने पहले ही प्रारंभ कर दिया है पटना–गया डोभी और बिहारशरीफ–राजगीर–गया फोरलेन का काम । बैठिये ।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पुराने लोगों को ध्यान में होगा, नेशनल हाई–वे डेवलपमेंट का काम आदरणीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था । उनकी सरकार जब बनी महोदय, उन्होंने नेशनल हाई–वे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया और एन0एच0डी0पी0–1 के तहत देश के जो चार बड़े महानगर हैं उनको जोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया– दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई और उन्होंने उसका नाम दिया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना । महोदय, उसके माध्यम से बिहार में भी सडकें आयीं, जो पुराना जी0टी0 रोड है, उसके निर्माण का काम हुआ और चौड़ीकरण का काम हो रहा है । महोदय, उसके बाद एन0एच0डी0पी0–2 आया और इसके तहत महोदय, भारत को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जोड़ने का निर्णय हुआ और जो ईस्ट–वेस्ट कोरीडोर है, उसमें हमारे यहां सडकें आयी जो बिहार में गोपालगंज से प्रवेश की और वहां से पीपरा कोठी होते हुये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, झंझारपुर होते हुये वह चली गयी पूर्णियां की ओर । महोदय, उसके बाद एन0एच0डी0पी0–3 आया । महोदय, मैं चर्चा जो करना चाहता हूं उस एन0एच0डी0पी0–3 के तहत एन0एच0 के सड़कों के

चौड़ीकरण का निर्णय लिया और एन0एच0डी0पी0-3 के तहत, रामदेव बाबू को याद होगा, इलियास साहब को याद होगा, 1 हजार 15 कि0मी0 सड़क फोरलेन में तबदील करने का निर्णय सरकार ने किया । महोदय, संयोग से 2004 में हमारी सरकार चली गयी, दूसरी सरकार आ गयी और दूसरी सरकार ने उस फोरलेन के काम में काट-छांट करने का काम किया । महोदय, पहले से जो तय था, कैसी विडम्बना है ? मैं दो-तीन उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं । महोदय, कोई आदमी बक्सर से चलेगा तो बक्सर, आरा, पटना, मोकामा तक फोरलेन से वह जायेगा, भारत सरकार फोर लेन बना रही है । लेकिन मोकाम से मुंगेर जायेगा तो उसको टू लेन सड़क पर चलना पड़ेगा । लेकिन मुंगेर से भागलपुर होते हुये मिर्जाचौकी जायेगा तो भारत सरकार फोरलेन बनाने के लिये तय कर चुकी है, उसका डी0पी0आर0 बनने का काम पूरा हो गय है, टेंडर होने वाला है । उसके आगे फोरलेन बनेगा, महोदय, अब जरा कल्पना कीजिये । बक्सर से चलेगा तो मोकाम तक वह फोरलेन और मोकामा से मुंगेर बीच में टू-लेन और मुंगेर से मिर्चाचौकी फोर लेन ।

(व्यवधान)

मुझे बोलने दीजिये । बैठिये । बता रहे हैं । आप सुनिये तो । वही तो हम बता रहे हैं । आप सुनते ही नहीं हैं । तो हम क्या करें ? सुनिये, समझियेगा तो आप को जानने में सुविधा होगी ।

महोदय, यह एन0एच0 है और नेशनल हाई-वे को टू-लेन और फोर-लेन कौन करेगा, यह बिहार की सरकार तय नहीं करती है, यह भारत की सरकार तय करती है और उस समय यूपीए की सरकार थी, जो आपके भरोसे चल रही थी । जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिये ।

(व्यवधान)

वही तो बता रहा हूं यूपीए की सरकार थी । आपको इतनी भी जानकारी नहीं है ? उस क्षेत्र के कैसे विधायक हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं ?

महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं । महोदय, आप रजौली से चलेंगे, रजौली से बख्तियारपुर फोर-लेन पहले से स्वीकृत था, बनेगा भी । बख्तियारपुर से मोकामा जायेंगे फोरलेने से और मोकामा से खगड़िया जायेंगे फोरलेन है लेकिन खगड़िया से पूर्णयां जायेंगे तो टू-लेन से जाना पड़ेगा और पूर्णियां से अगर नॉर्थ-ईस्ट जाना है तो फिर फोर-लेन है महोदय । कैसी विडम्बना है महोदय और जब हमारी सरकार बनी, याद होगा, मोकामा में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आये थे, मैंने उस भरी सभा में माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भारत सरकार ने बिहार की जनता की आवाज सुनने का काम किया, भारत सरकार ने तय किया है कि अब मोकामा-मुंगेर भी फोर-लेन बनाने का काम किया जायेगा ।

खगड़िया, पूर्णियां भी फोर-लेन बनाने का काम किया जायेगा और मुजफ्फरपुर, बेगुसराय भी फोर-लेन बनाने का काम किया जायेगा । महोदय, मैं इन बातों की केवल इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि आप इसको समझने की कोशिश कीजिये । बिहार के विकास के लिये कौन चिन्तित है ? कौन कर रहा है काम ? यह अगर आप ठीक से समझेंगे तो आपको सुविधा होगी ।

(व्यवधान)

महोदय, भारत सरकार की चर्चा मैंने बहुत कर दी, शायद इनको परेशानी हो रही होगी । मैं इनको पुराने जमाने में ले जाना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

आपका विश्वास मेरे ऊपर है, मैं करूंगा इस काम को । मैं आपसे कह रहा था, ये लोग पता नहीं कैसी-कैसी बात करते हैं । 20 महीना का गाना गाते हैं । कह रहे हैं उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, किसका काम किया ? महोदय, मैं अब केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं । विकास क्या होता है ? मैं उसका एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहता हूं । मैं सड़कों की बात मैं बाद में करूंगा । महोदय, मैं पुलों की बात करना चाहता हूं । महोदय, हमारे यहां 5-6 प्रमुख नदियां हैं । माननीय इलियास साहब को पुलों के निर्माण की की बात याद होगी । मैं जानता हूं । मैं चर्चा करूंगा उसकी । महोदय, बिहार के अंदर जो प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों में, हमारी सरकार बनने के पहले, 2005 की सरकार के पहले, महोदय, कितने पुल थे और आज कितने पुल हैं, कितने पर काम चल रहें हैं, मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। महोदय, अगर गंगा नदी का विचार करें तो 2005 के पहले केवल 4 पुल थे, एक बक्सर में था, जो बलिया को जोड़ता था, दूसरा महात्मा गांधी सेतु था, तीसरा राजेन्द्र सेतु, मोकामा था और चौथा, बिक्रमशीला सेतु, भागलपुर था । मगर आज जिस पुल के उद्घाटन के लिये वाह-वाही लूट रहे हैं, महोदय, इन्होंने कुछ किया है क्या ? महोदय, उसमें से दो पुल चालू हो गया, आरा-छपरा और दीघा-सोनपुर और 5 पुलों पर निर्माण का काम चल रहा है । कच्ची दरगाह बिदुपुर, बख्तियारपुर-ताजपुर, मुंगेर पुल,अगुवानी घाट पुल, मनिहारी-साहेबगंज पुल, इन पांच पुलों के निर्माण का काम चल रहा है । मुझे मालूम नहीं है अगर कल से ये कहने लगें कि साहब, कच्ची दरगाह-बिदुपुर तो तेजस्वी जी ने बनवाया है । मुझे मालूम नहीं, क्या-क्या कहनेवाले हैं ये ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह पूरक पूछने का समय नहीं है । मंत्री जी, आप जारी रखिये ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, मोकामा पुल के समानान्तर एक नया पुल का निविदा हो गया है । कार्य आवंटित हो गया है, अगले वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू

होनेवाला है महोदय, और चार पुल प्रस्तावित है । बक्सर पुल के समानान्तर एक नया पुल, दीघा पुल के समानान्तर एक और पुल, महात्मा गांधी सेतु के समानान्तर एक और पुल और बिक्रमशीला सेतु के समानान्तर एक और पुल । महोदय, मतलब क्या है ? मतलब है 2005 के पहले गंगा नदी पर केवल 4 पुल थे महोदय । अगर 5 साल के बाद गंगा नदी पर उस 4 पुल को लगाकर 16 पुल हो जायेंगे । बात करते हैं उत्तर बिहार के उपेक्षा की । आप आरोप लगाते हैं उत्तर बिहार की उपेक्षा की । एक पुल की बात करते हैं, हम तो यहां से वहां तक, बक्सर से लेकर साहेबगंज तक हमने पुलों का जाल बिछाने का काम किया है गंगा नदी पर ताकि उत्तर बिहार का समुचित विकास हो सके, उत्तर बिहार आगे बढ़ सके । आरोप लगाते हैं । महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं। गंडक नदी पर 2005 के पहले तीन पुल थे । डुमरिया घाट, रेवाघाट, और गंडक घाट, सोनपुर के पास । महोदय, उसमें से दो पुलों के निर्माण का काम हमने कर लिया, धनहा–रतवल, गोपालगंज–बेतिया, इन दो पुलों पर अभी काम चल रहा है– सत्तरघाट, बंगलाघाट । मतलब 3 पुल पहले था और 4 पुलों का काम और हम कर रहे हैं ।

क्रमश :

टर्न–26/सत्येन्द्र/12–3–18

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री(क्रमशः): कोशी पर दो पुल था डुमरिया घाट और कुरसेला में महोदय, तीन तो हमने चालू कर दिया कोशी महासेतु ,बलुआहा घाट और विजय घाट और महोदय, दो पुल और प्रस्तावित है जिसकी भी चर्चा मैंने आपके सामने की और दूसरा एन.एच. 106 के फुलौत घाट पर महोदय, सोन की जहां तक बात है, सोन पर पहले दो ही पुल था, एक डेहरी के पास, एक कोईलवर के पास और महोदय, हमने उसमें अरवल–सहार का पुल चालू कर दिया, दो पुल और चालू होने वाला है, काम लगा हुआ है महोदय, दाउदनगर और नासरीगंज जो शीघ्र इसी साल चालू होगा और दूसरा कोईलवर पुल के समानांतर एक नये पुल के निर्माण का काम हो रहा है महोदय, पण्डुका पुल हमारा प्रस्तावित है । बागमती की बात करिये, सीतामढ़ी के लोग पता नहीं, हैं तो क्या सोच रहे होंगे, सुनील जी है कि नहीं सीतामढ़ी से महोदय, क्या हाल था सीतामढ़ी के बागमती का महोदय, चार पुल थे महोदय, बेनीबाद, कोलुआ और बरियाही, करेह में महोदय, सात नये पुलों के निर्माण हमने बागमती के ऊपर किया है महोदय, पिपराही, बैरगनियां ढेंग, कंटरौंझा,डुब्बा घाट, मांडर घाट, बलतोरा घाट, सुनमखी घाट, महोदय, मतलब चार पहले के थे, सात हमने नया बना दिया मतलब कि ग्यारह हो जायेंगे । महोदय,उसी प्रकार फल्गु पर था पहले केवल एन0एच0बाईपास पर गया के मानपुर में, महोदय, चार हमने बनाकर पूरा काम कर लिया । मानपुर में सिक्स लेन का पुल, कंडी बंशी बिगहा, हुलासगंज और हमारा एक निर्माणाधीन है महोदय, एन0एच0–82 के

घूंघरीटाड़ के पास महोदय, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि ये जो पुलों का निर्माण का काम है, ये विकास की कहानी का गाथा है और इनमें से अगर किसी ने केवल उद्घाटन किया है मेरे पहले के मंत्री ने तो महोदय यह उनकी उपलब्धि नहीं है, ये तो हमने प्रारंभ किया है, चर्चा अगर होती इस बात की कि आपने क्या किया महोदय, एक बात ये लोग कह रहे थे छपरा के उस डबल डेकर पुल की बात, ये विकास का काम किसी पार्टी का काम नहीं होता है, सरकार का काम नहीं होता है, शुरू हुआ ? लेकिन आपको जानना चाहिए कि छपरा के डबल डेकर की प्रशासनिक स्वीकृति भी पूर्व मंत्री ने नहीं दिया था, इसकी स्वीकृति मैंने दिया, हमारी सरकार ने दिया और केवल स्वीकृति ही नहीं दिया, टेंडर किया लेकिन पहली बार के टेंडर में सिंगल टेंडर आया जिस कारण कैन्सिल किया गया लेकिन फिर से टेंडर किया है, विश्वास कीजिये इसी मार्च महीने में हम कॉन्ट्रेक्टर बहाल करने का काम पूरा करेंगे और उसके निर्माण का काम करेंगे । महोदय, किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, विकास का सवाल है । महोदय,मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जाम की समस्या की बात माननीय सदस्यों की है और इसके लिए हमने सुनियोजित प्रयास किया है, भारत सरकार की योजना है उसको जोड़कर के महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, हम एक बात और कहना चाहता हूँ सेतु के बारे में महोदय, आपको ध्यान में होगा जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भ्रमण किया तो बड़ी संख्या में लोग बिहार में बांस की चचरी से पुल पार करते थे महोदय तो हमलोगों ने तय किया कि इस चचरी को समाप्त करेंगे और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना हमलोगों ने प्रारम्भ किया और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत महोदय हमलोगों ने पांच हजार से अधिक पुलों का निर्माण कराया है महोदय, लेकिन अभी भी कहीं कहीं दिखलाई पड़ता है चचरी महोदय, कभी कभी मैं देखता हूँ, सदस्य हमारे प्रश्न करते हैं लेकिन दो साल से महोदय मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना बंद है लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से बात किया है और हमारे विभाग ने तय किया है कि अगले वित्तीय वर्ष से हम फिर से मुख्यमंत्री सेतु योजना प्रारम्भ करेंगे और पुलों के निर्माण का कार्य करेंगे । महोदय, जाम की समस्या का जिक्र बार-बार हो रहा है महोदय, ये ठीक बात है और हमने इसके लिए हमने बड़े पैमाने पर शहरों और कस्बों में बाईपास बनाने का निर्णय लिया, कई स्थानों पर ऐलीवेटेड रोड बनाने का तय किया है महोदय और आपको प्रसन्नता होगी कि आज मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मधुबनी, कटिहार, राजगीर, मुंगेर, नवादा, हिलसा, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, छपरा, आरा, बक्सर, सासाराम, भागलपुर, लखीसराय, जहानाबाद और गया महोदय, इन स्थानों पर बाईपास के निर्माण का काम, कुछ जगहों पर हो गया है और बाकी जगहों पर इसके निर्माण की योजना बन गयी है, कुछ जगहों पर काम चल रहा है । हम इन स्थानों के अलावा महोदय और भी कई स्थानों पर हम एलीवेटेड रोड

बनाने की योजना बना रहे हैं, बाईपास की योजना बना रहे हैं ताकि जो लक्ष्य हमने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पांच घंटे में पटना पहुंचने का महोदय तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें ।

श्री प्रह्लाद यादवः अध्यक्ष महोदय, लखीसराय में चार दिन से जाम है, गाड़ी चार दिन से वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, बड़हिया से लखीसराय जाने का कोई उपाय नहीं है चार दिन से जाम है ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, ये पता नहीं लखीसराय का क्या भला किये हैं मुझे पता नहीं लेकिन हम इनको बतलाते हैं लखीसराय बाईपास का काम महोदय, जून महीने तक लखीसराय बाईपास का काम हम पूरा कर देंगे । चिन्ता मत कीजिये आप नहीं कीजियेगा तो हम करने वाले हैं ।

श्री प्रह्लाद यादवः अध्यक्ष महोदय, बालू की बात होती है..

अध्यक्षः कहां बात हो रही है सड़क और पुल की ! बालू की बात कोई नहीं कर रहा है, सड़क पुल की बात हो रही है ।

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्रीः महोदय, ये स्वाभाविक रूप से पटना जो राजधानी है और राजधानी में केवल पटना के लोग नहीं रहते हैं बल्कि लाखों लोग रोज पटना के अन्दर देश के विभिन्न हिस्से से आते हैं और महोदय, अगर राजधानी का विकास नहीं हुआ, राजधानी के जाम की समस्या का समाधान नहीं हुआ महोदय, राजधानी का विकास भी एक प्राथमिकता है, राजधानी हमारे पूरे प्रदेश की पहचान बन जाती है तो राजधानी के अन्दर उसका समुचित विकास हो, उसके अन्दर जाम की समस्या का समाधान हो इसके लिए भी हमलोगों ने कई प्रकार की योजना बनायी है और महोदय, हमने भविष्य की योजना देखी महोदय, जो जनगणना है जो 2031 का उसके अनुसार पटना शहर की अनुमानित जनसंख्या है 60 लाख होने वाली है तो इन 60 लाख की जनसंख्या को कैसे हम सुगम साधन दे सकें तो उसके लिए हमने बड़े पैमाने पर काम प्रारम्भ किया है महोदय, पटना रिंग रोड के निर्माण अब प्रारम्भ होगा, उसका डी0पी0आर0 महोदय बन रहा है पहले महोदय, पटना रिंग रोड का जो बना था उसका मार्गरेखन हुआ था वह केवल दक्षिण में हुआ था, ये बिहटा से दनियावां होते हुए कच्ची दरगाह तक हुआ था महोदय लेकिन मैंने उसे माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर के उसमें परिवर्त्तन किया है महोदय और अब जो मार्गरेखन उसका है महोदय, यह बिहटा एयरपोर्ट से प्रारम्भ होगा, वहां से नौबतपुर, बेलदारीचक, दनियावां, कच्ची दरगाह, बिदुपुर, हाजीपुर, सोनपुर, दीघा, मनेर के रास्ते से बिहटा तक जायेगा महोदय, ये पूरा रिंग रोड जब बन जायेगा महोदय, तो इसका 165 कि0मी0 का कुल लम्बाई होगा और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इस रिंग रोड के अन्दर 1337 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्रफल पड़ेगा महोदय, जो पटना शहर के वर्त्तमान क्षेत्रफल से 13 गुणा अधिक है तो महोदय, यह जो रिंग रोड बनेगा इसमें

वैशाली, पटना के विकास के साथ-साथ वैशाली और सारण का भी विकास होगा और महोदय, बिहार का कोई आदमी जिसे बिहार के किसी कोने से अगर पटना एयरपोर्ट पर जाना है तो उसको पटना शहर के अन्दर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह रिंग रोड के माध्यम से बिना जाम को झेले हुए, वे सीधे वहां पहुंच जायेंगे ।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादवः महोदय..

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, ये जुमलेबाज लोग मुझे कह रहे हैं, इनके नेता ने बयान दिया था कि 40 हजार, एक लाईन सुन लो तो जाना, इनके नेता ने बयान दिया था कि वाट्स-अप पर 40 हजार शादी का मैसेज आया है । महोदय, झूठ का ऐसा पहाड़ हमने नहीं देखा । शक्ति जी, आपके नेता ने कहा था कि जो वाट्स-अप जारी किया है पथ निर्माण विभाग ने उसमें 40 हजार लड़कियों ने शादी का मैसेज दिया है । महोदय, मैं आज बतलाना चाहता हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ बतलाना चाहता हूँ, मैने सारे वाट्स-अप मैसेज को देखा है, एक भी मैसेज शादी का नहीं आया है महोदय, ये झूठा प्रचार किया गया महोदय, झूठा प्रचार किया गया । महोदय, लड़का घर का है, घर के लड़के के शादी की चिन्ता हमें भी है, घर के बच्चे की शादी हो जाय, हम भी चाहते हैं लेकिन झूठ का पहाड़ कर के ये राजनीति करना चाहते हैं, कौन सी राजनीति करना चाहते हैं बताओ मुझे। महोदय,हम गंगा पथ के निर्माण का काम कर रहे हैं, एम्स से दीघा तक एलीवेटेड रोड निर्माण का कार्य कर रहे हैं, महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं महोदय, हमने कई आर0ओ0बी0, कई फ्लाईओवर बनाने का काम तय किया है महोदय । महोदय, पटना शहर के विकास के लिए हमने शिवाला बिहटा पथ के ..

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गये)

महोदय, मैंने कोई दुर्भावना से यह बात नहीं कही है, घर का बच्चा है, मुझे भी उसकी चिन्ता है महोदय लेकिन मुझे मालूम पड़ा है...

अध्यक्षः आप दुर्भावना से नहीं कहे थे तो किस भावना से कहे थे ?

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्रीः महोदय, मेरे घर का बच्चा है, मुझे भी चिन्ता थी महोदय, उम्र अधिक हो जाने से बहकने का खतरा होता है महोदय इसलिए वह चिन्ता हमारी भी थी लेकिन ये दुष्प्रचार कर के वाहवाही लूटना, ऐसे प्रचार का कोई औचित्य नहीं है ।(क्रमशः)

टर्न-27/मधुप/12.03.2018

...क्रमशः..

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैं कह रहा था कि बिहटा एयरपोर्ट जब बनेगा, वहाँ आसानी से पहुँचा जा सके, इसके लिये हमलोगों ने एक एलिवेटेड रोड बनाने का भारत सरकार

से आग्रह किया है । भारत सरकार ने शिवाला से बिहटा तक उसके लिये सहमति दे दी है।

अध्यक्ष : वैसे भी माननीय मंत्री जी, कोई सरकारी साईट, विभाग का ऑफिशियल साईट जो होता है, वह तो कोई मैट्रिमोनियल साईट होता नहीं है !

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : पता नहीं क्यों ? महोदय, आपको याद होगा कि यहाँ खूब चर्चा हुई है। कैसी-कैसी चर्चा होती थी, महोदय, मैं उसको दुहराना नहीं चाहता हूँ ।

महोदय, मैं कह रहा था, पटना के विकास के लिये जहाँ हमने कई नालों को पाटकर भी सड़क बनाने का अभी तय किया है । साथ-ही-साथ, हमने कई फ्लाई-ओवर बनाने का तय किया है, मैं उसकी चर्चा करूंगा । लोहिया पथ चक्र के काम को हमने तेज करने की कोशिश की है । महोदय, जो स्टेट हाईवे-1 हमारा है, पहाड़ी मोड़ से लेकर मसौढ़ी तक, उस सड़क को भी 4-लेन बनाने का हमलोगों ने तय किया है । महोदय, अगर आप तुलना करेंगे आर0ओ0बी0 और फ्लाई-ओवर का, मेरे पास समय कम है । महोदय, 2005 के पहले पटना शहर के अन्दर केवल 4 आर0ओ0बी0 थे । 2005 के बाद हमलोगों ने 7 आर0ओ0बी0 का निर्माण का काम पटना शहर के अन्दर किया । हमलोगों ने 3 बड़े-बड़े फ्लाई-ओवर बनाकर जनता को समर्पित कर दिया, 3 फ्लाई-ओवर अभी निर्माण की प्रक्रिया में चल रहे हैं और 4 फ्लाई-ओवर ऐसे हैं जो हमारा प्रस्तावित है ।

महोदय, आज अगर सड़कों के बारे में आप गौर कर रहे होंगे, ये लोग जब हमारी सड़कों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके विरोध में दम नहीं था क्योंकि जब घर से निकलते होंगे तो अच्छी सड़कों से चलते होंगे । अच्छी सड़कों से केवल इसलिये चल पा रहे हैं क्योंकि बिहार के अन्दर सड़कों के रख-रखाव के लिये एक निश्चित नीति बनाई गई । महोदय, आपको ध्यान में होगा, बिहार पथ सम्पदा अनुरक्षण नीति, 2013 हमने बनाई, जिसके तहत ओ0पी0आर0एम0सी0 के तहत बिहार की 8 हजार कि0मी0 सड़कों के रख-रखाव का जिम्मा हमलोगों ने दिया । उसके कारण सड़कों की स्थिति ठीक है । लेकिन हमने तय किया है, अब उनका 5 साल पूरा हो गया है, अनुभव हमारा अच्छा है, हम अगली बार अब 7 साल के लिये फिर एक बार टेन्डर करने वाले हैं और अगले 7 साल के लिये अब केवल 8 हजार कि0मी0 ही नहीं बल्कि हम और ज्यादा, लगभग दोगुणी सड़कों को ओ0पी0आर0एम0सी0 के तहत देने वाले हैं ताकि लगातार बिहार की सड़कें संधारित रहें, बेहतर बनी रहें, लोग उसका लाभ उठा सकें । महोदय, यह हमारा विचार है ।

महोदय, आप जानते हैं कि जमीन अधिग्रहण हमारे लिये बड़ी समस्या है, हम कई प्रकार की चीजों से जूझते रहते हैं । हमने तय किया है, हम एक नई नीति जमीन अधिग्रहण की बना रहे हैं जिसको हम लैंड पूलिंग नीति कहते हैं । इसके तहत सड़क

के लिये जितनी जमीन की हमें आवश्यकता है, हम उससे दोगुणी जमीन किसानों से लेंगे और आधी जमीन फिर से डेवलप करके किसानों को सड़क के किनारे हम वापस कर देंगे जिसके कारण किसानों के जो जमीन की कीमत है, वह अपने-आप कई गुणा बढ़ जायेगी । इस नीति के तहत हम आने वाले दिनों में काम करने की कोशिश करने वाले हैं । साथ-साथ, भू-अधिग्रहण के लिये हमलोगों ने तीन लोगों की बहाली की है जिसमें मुख्य भूमि अधिग्रहण विशेषज्ञ और दो विशेषज्ञों को बहाल किया है, उनके बीच में जिलों का हमलोगों ने बँटवारा किया है ताकि जल्दी से जल्दी जिलों के अन्दर इस काम को पूरा कर सकें ।

महोदय, सीतामढ़ी के अन्दर बच्चों के दुर्घटना का समाचार हम सबके लिये दुखद था और राज्य सरकार सड़क सुरक्षा पर भी विशेष जोर देने का काम कर रही है । इस समय जो एन0एच0 हैं उसपर 101 और अन्य पथों पर 23 ब्लैक स्पॉट हमलोगों ने पाये हैं । इनमें से 54 ब्लैक-स्पॉट का हमलोगों ने संरचनात्मक सुधार कर दिया है, शेष स्थानों के संरचनात्मक सुधारों का काम किया जा रहा है । महोदय, आने वाले दिनों में हम जरूर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इस स्पॉट को चिन्हित करें और मुझे महोदय, प्रसन्नता है, एन0एच0ए0आई0 से जब हमलोगों ने बातचीत किया है, एन0एच0ए0आई0 ने एन0एच0 77 पर जो एक्सीडेंटल स्पॉट है, वहाँ एक अंडरपास बनाने का उनलोगों ने निर्णय कर लिया है । आने वाले दिनों में उसका निर्माण का काम किया जायेगा ।

महोदय, आप जानते हैं कि पथ विकास निगम और पुल निर्माण निगम हमारी जान हैं, दो बाँह हैं और इनके बल पर ही हम विकास के काम को अंजाम दे पाते हैं । ये दोनों संस्थाएँ हमारी बेहतर ढंग से बिहार के अन्दर विकास के काम को अंजाम दे रही हैं, जो काम इनको हम दे रहे हैं, उसको ये पूरा कर रहे हैं ।

महोदय, उनके झूठ के पहाड़ के बारे में कितनी बात कहूँ, आप जानते हैं कि जो कच्ची दरगाह में बिदुपुर पुल है, लोग इसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं । महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, कच्ची दरगाह में बिदुपुर पुल के बारे में शुरूआत की जहाँ तक बात है, इसके बारे में 27 जून, 2012 में हुई, उस समय ये नहीं थे, हम ही दोनों थे । उसके बाद से जो प्रक्रिया पूरी होती रही, जो टेन्डर खुला, मजेदार बात है कि जो टेन्डर खुला 23/11 को और तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री जी ने ज्वॉयन किया था 20/11 को । बताइये महोदय, क्या 20/11 को पथ निर्माण मंत्री बनकर कोई तीन दिन के बाद किसी पुल के निर्माण का टेन्डर खोल सकता है ? महोदय, लम्बी प्रक्रिया चली और यह इसलिये चली, जब महात्मा गाँधी सेतु के जीर्णोद्धार के लिये भारत सरकार ने पैसा देने से इनकार कर दिया, कम पैसा देती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें विकल्प खोजना चाहिये, नहीं चलेगा गंगा सेतु तो क्या होगा उत्तर बिहार का और उनके निदेश

और सुझाव के कारण एक नये पुल के निर्माण के बारे में हमलोगों ने काम आगे बढ़ाया और जब काम आगे बढ़ा दिया तो मजा लेने के लिये ये आ गये, वाहवाही लूटने के लिये आ गये ।

महोदय, मैं भारत सरकार के सहयोग के बारे में कितनी चर्चा करूं आपसे । भारत सरकार के सहयोग के बारे में विस्तार से चर्चा हो गई है । महोदय, मैं कुछ प्रमुख बातें आपके सामने जरूर बताना चाहता हूँ । महोदय, मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, मेरी बातें पूरी नहीं हो पायेंगी चूंकि समय की भी सीमा है, इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि मेरा जो प्रिंटेड भाषण है, उसको भी प्रोसिडींग का पार्ट बना दिया जाय ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

मैं तीन-चार बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । महोदय, ए0डी0बी0 के तहत 6 सड़कों का 2-लेनिंग का निर्णय हो चुका है । उसकी सहमति मिल गई है, 5 का डी0पी0आर0 बनाकर हमलोगों ने जमा कर दिया है, 1 और का डी0पी0आर0 बन रहा है। वह बिहियां-जगदीशपुर-बिहटा रोड है, कादरीगंज-खैरा रोड है, घोघा-पंजवारा रोड है, अकबर नगर-अमरपुर रोड है, उदाकिशुनगंज-भटगामा रोड है और बेतिया-नरकटियागंज-भीखना ठोढी रोड है । महोदय, हमने यह तय किया है, अगर 5 घंटे में दूरी प्राप्त करनी है तो हमें कहीं न कहीं सड़कों को जोड़ना पड़ेगा । हमने यह निर्णय लिया है कि जितना अनुमंडल मुख्यालय हैं, सभी अनुमंडल मुख्यालय को हम जिला मुख्यालय से 2-लेन सड़क से जोड़ने का काम करेंगे । महोदय, हमने सर्वे कराया है और सर्वे में दिखाई पड़ा है, केवल 10 अनुमंडल ऐसा है जो 2-लेन सड़क से जिला मुख्यालय से नहीं जुड़ा है । उसमें 1 अनुमंडल ऐसा है जो ग्रामीण पथ से जुड़ा हुआ है तो जो 9 अनुमंडल अभी कहीं से 2-लेन से नहीं जुड़ा हुआ है, उन अनुमंडल की सड़कों का निर्माण हम करेंगे, हम 2-लेन सड़कों का निर्माण का काम करेंगे । उसी प्रकार हम प्रखंड मुख्यालय को अनुमंडल मुख्यालय से जोड़ने का काम करेंगे ताकि गॉव का आदमी अपने काम के लिये अगर कहीं जाना चाहता है, एस0डी0ओ0 कोर्ट में यदि जाना चाहता है तो सहजता से जा सके । उसकी भी कार्य योजना हमने बनाई है, हमने उसका भी सर्वे किया है, 184 प्रखंड ऐसे हैं जो अभी जिला मुख्यालय से जुड़े हुये नहीं हैं, हम उसके उपर भी काम कर रहे हैं ।

महोदय, मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ । आप जानते हैं कि बिहार के अन्दर बड़े पैमाने पर पुलों के निर्माण का काम हमने किया था । महोदय, उन पुलों पर टॉल लगने का भी काम होता था । 116 पुल पर टॉल लगने का निर्णय किया था पुल निर्माण निगम ने लेकिन बहुत सारे पुलों पर टॉल के लिये कोई टेन्डर नहीं आया । 54 पुल पर टेन्डर हुआ था और 54 पुल पर टॉल की वसूली का काम होता था । लेकिन अब राज्य सरकार ने तय किया है पथ निर्माण विभाग की सहमति से, 01 अप्रैल से

बिहार में बने हुये बिहार सरकार और पुल निर्माण निगम के किसी भी पुल पर अब कोई टॉल नहीं लगेगा । यह निर्णय राज्य सरकार ने किया है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमने एक बात का और निर्णय लिया है, हम यह चाहते हैं, पथ निर्माण विभाग के जो हमारे बड़े-बड़े मेगा ब्रीजेज हैं और पथ निर्माण विभाग की जो सड़कें शहर के अन्दर से गुजरती हैं, हमने निर्णय लिया है कि सभी मेगा ब्रीजेज पर और पथ निर्माण विभाग की जो सड़कें शहर के अन्दर से गुजरती हैं उन सड़कों पर लाईट लगाने के बारे में भी हम एक नीति बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण निगम उन पर लाईट लगाने का काम करे ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके ।

महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ । बिहार के अन्दर पेट्रोल पम्प खोलने के लिये सर्विस-लेन चाहिये, सर्विस-लेन के लिये बड़े पैसे लगते थे लेकिन अब हमने तय किया है, एन0एच0ए0आई0 की नीति के तहत भारत सरकार जो पैसा लेती है, वही पैसा अब राज्य सरकार लेगी । मैं केवल एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा चूंकि मेरे पास समय की कमी भी है । (व्यवधान) तारा चंडी के बारे में बेचैन हो रहे हैं, तारा चंडी जाने के लिये सड़क स्टेट हाईवे घोषित होगा, चिन्ता करने की जरूरत नहीं है ।

महोदय, बिहार के अन्दर एक विशेष बात थी, यह मारा-मारी करते थे कि एन0एच0 बनाओ, एन0एच0 बनाओ । लेकिन महोदय, हमारी सरकार कुछ और सोचती है । 52 सड़कों के बारे में इन-प्रिंसपुल भारत सरकार ने तय किया था लेकिन महोदय, मुझे यह बात कहने में गर्व हो रहा है कि बहुत सारी हमारी स्टेट हाईवे ऐसी हैं जो भारत सरकार के एन0एच0 से बेहतर हैं । हमने कहा है कि जो सड़कें हमारी बेहतर हैं उन सड़कों को हम एन0एच0 घोषित नहीं होने देंगे । महोदय, जहॉ लोग एन0एच0 बनाने के लिये मार करते थे, 52 सड़कों के बारे में भारत सरकार ने कहा कि हम इन-प्रिंसपुल तैयार हैं लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया, हमने केवल 34 सड़क स्वीकार किया है । उन 34 सड़क के डी0पी0आर0 बनाने का काम चल रहा है, हम भारत सरकार को क्रमबद्ध ढंग से भेजने का काम कर रहे हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-28/आजाद/12.03.2018

.... क्रमशः ....

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्री : महोदय, यह जो सरकार है, मैंने कहा शुरू में महोदय कि सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, हम विकास के लिए समर्पित हैं । हम आने वाले दिनों में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार रोड के मामले में, पुल-पुलिया

के मामले में एक नई ऊँचाई पर पहुँचने का काम करेगी, इस बात का भरोसा देते हुए, अगर रहते वे लोग तो कह देते कि साहेब वापस ले लीजिए कटौती प्रस्ताव लेकिन नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान मांग राशि 41 के अधीन पथ निर्माण विभाग का 68,89,12,83,000/-रू0 का स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि कृपया इस प्रस्ताव को स्वीकृत करें ताकि बिहार के सड़कों के विकास के मामले में हम और आगे बढ़ सकें और ज्यादा काम कर सकें । बहुत,बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''पथ निर्माण विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 68,89,12,83,000/-(अड़सठ अरब नवासी करोड़ बारह लाख तिरासी हजार) रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 12 मार्च, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-21 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक दिनांक मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

श्री सुशील कुमार मोदी
उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

श्री नन्द किशोर यादव
मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

श्री नन्द किशोर यादव

मंत्री, पथ निर्माण विभाग

का

सदन में

बजट भाषण

2018 - 2019

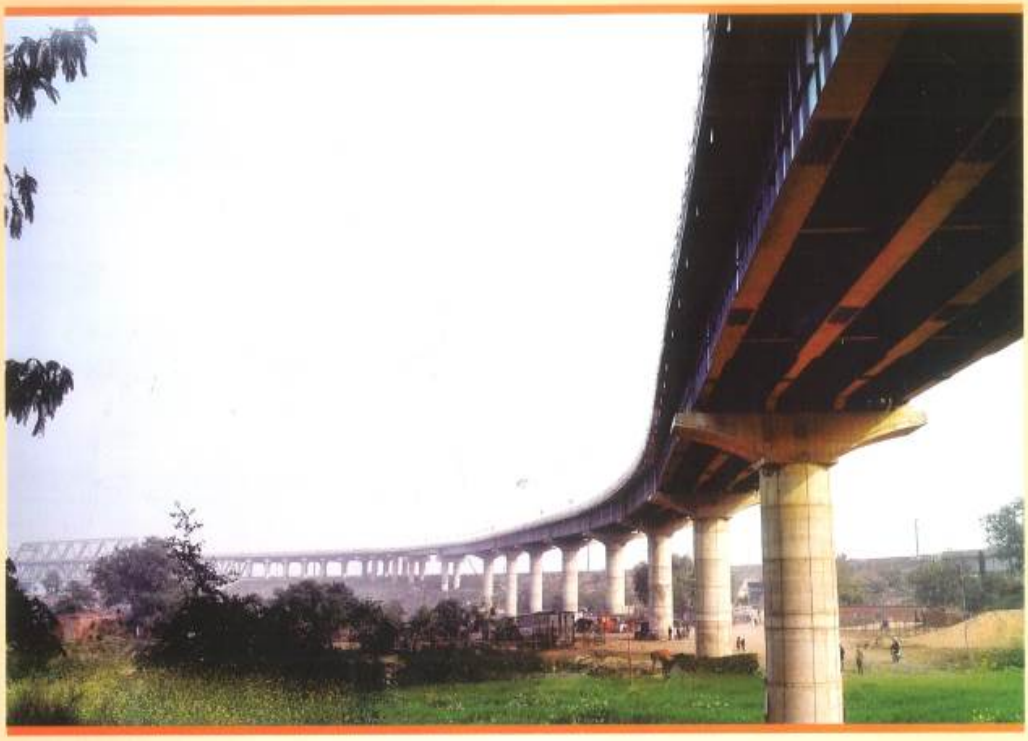

पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांग पर
श्री नन्द किशोर यादव, माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग
का बजट भाषण (2018-19)

माननीय अध्यक्ष महोदय,

पथ निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 के अनुदान मांग प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। राज्य सरकार द्वारा आवागमन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के प्रयोजन से रोड नेटवर्क का सुनियोजित विकास किया जा रहा है।

राज्य सरकार का यह प्रयास है कि राज्य में तीव्रतम संभव गति पर आवागमन हो तथा राज्य के किसी भी हिस्से से 5 घंटे के अंदर राजधानी पटना से आना–जाना संभव हो सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार पथों की चौड़ाई बढ़ायी जा रही है। जिन स्थानों पर सीधे सम्पर्कता सुनिश्चित करने के लिए नये पुल बनाने की आवश्यकता है, उन नदियों पर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। जो पथांश सघन आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरते हैं, वहाँ आवश्यकतानुसार बाईपास या एलिवेटेड पथों का निर्माण किया जा रहा है। पटना राजधानी क्षेत्र में आवागमन में कम समय लगे इस हेतु आधारभूत ढांचे को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है।

महोदय, मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि इस कार्य में भारत सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नीतीन गडकरी जी ने पटना में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गहन समीक्षा बैठक की है।

मुझे सदन को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सड़कों के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए घोषित PM पैकेज के अंतर्गत 54700 करोड़ रु० की

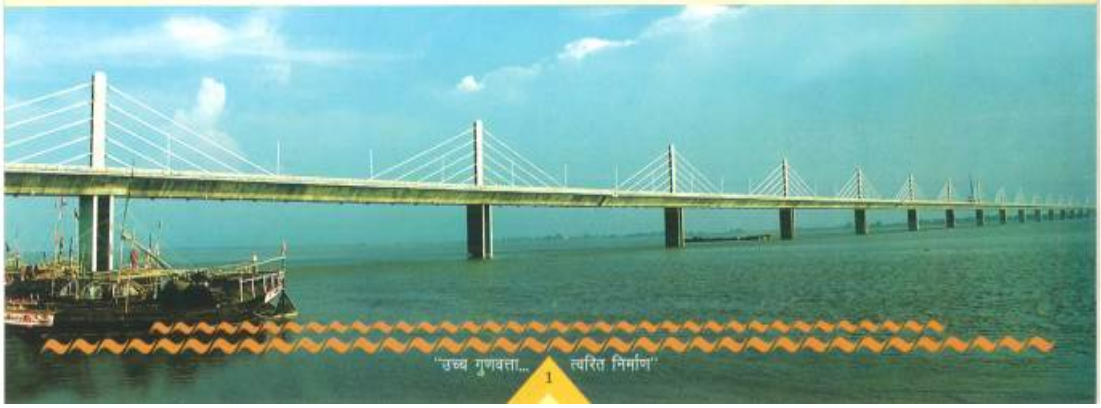

योजनाओं पर कार्य होना है। इस पैकेज के अंतर्गत कुल 82 योजनाओं का कार्यान्वयन होना है, जिनमें से 45 योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आवंटित किया जा चुका है। आवंटित अधिकांश योजनाओं में कार्य आरंभ किया जा चुका है। 12 योजनाएँ निविदा या स्वीकृति की प्रक्रिया में है। 25 योजनाओं का डी०पी०आर० निर्माण प्रक्रिया में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्ष 2018–19 के अंत तक PM पैकेज में घोषित सभी योजनाओं में सरजमींन पर कार्य आरंभ हो जाएगा। इससे अगले 2 वर्षों में राज्य में बेहतरीन स्तर की परिवहन व्यवस्था विकसित हो सकेगी।

PM पैकेज के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य आरंभ हो चुका है, उनमें पटना–बक्सर फोरलेन, पटना–गया फोरलेन, बख्तियारपुर–मोकामा फोरलेन, गया–बिहारशरीफ फोरलेन, बिहारशरीफ–बरबीघा–मोकामा टू लेन, गंगा नदी पर औंटा–सिमरिया नया Six Lane Bridge, सिमरिया से खगड़िया फोरलेन पथ, साहेबगंज से मनिहारी के बीच गंगा पुल, मुजफ्फरपुर से छपरा टू लेन, छपरा–सीवान–गोपालगंज टू लेन आदि शामिल है।

जिन महत्वपूर्ण योजनाओं पर वर्ष 2018–19 में कार्य आरंभ होना है, उनमें प्रमुख तौर पर पटना रिंग रोड, मुजफ्फरपुर–बरौनी फोरलेन, खगड़िया–पूर्णिया फोरलेन, मोकामा–मुंगेर –भागलपुर –मिर्जाचौकी फोरलेन, सोन नदी पर पंडुका में पुल का निर्माण, उच्चैट–भगवती स्थान–बेनीपट्टी–मधुबनी–भेजापुल–महिषी–बनगाँव–बरियाही, यू.पी. सीमा (मेहरौना)–मैरवा–सीवान–मशरख–सत्तरघाट–केसरिया–चकिया–मधुबन–सीतामढ़ी–सुरसंड–(भीट्ठामोड़) नेपाल सीमा (रामजानकी पथ), रक्सौल–सोनवर्षा पथ आदि शामिल है।

सैद्धांतिक रूप से घोषित 52 NH में से 34 पथों को, जिनकी लंबाई लगभग 1943 कि०मी० है, NH के रूप में विकसित करने की अनुशंसा की गई है। इन 34 पथों में से 12 पथों, जिनकी लंबाई लगभग 514 कि०मी० है, की अनुशंसा PM पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार को भेज दी गई है। शेष पथों का डी.पी.आर. बनाकर शीघ्र भारत सरकार को भेजा जाएगा।

जिला मुख्यालयों की फोरलेन पथों से सम्बद्धता :–

यातायात सुगम, सुरक्षित एवं तीव्र हो, इस हेतु राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को यथासंभव फोरलेन पथों से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है।

जिला मुख्यालयों की प्रखंड मुख्यालयों से दो लेन पथों से सम्बद्धता :–

राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण ईकाई अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालय है। सभी जिला मुख्यालयों से अनुमंडल एवं अनुमंडलों को प्रखंड मुख्यालयों से दो लेन चौड़ा पथ से जोड़े जाने का प्रयास है।

पटना राजधानी क्षेत्र के आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण :–

पटना राजधानी क्षेत्र की वर्ष 2031 तक की अनुमानित जनसंख्या 60 लाख को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। प्रमुख परियोजनाओं जिस पर कार्य किया जा रहा है, वे निम्नवत् हैं–

1. **पटना रिंग रोड :–**

   राज्य सरकार द्वारा पटना रिंग रोड के आरेखन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह रिंग रोड बिहटा में स्थापित हो रहे नये एयरपोर्ट के पास कन्हौली से प्रारंभ होगा जो नौबतपुर, डुमरी, बेलदारीचक, दनियावां, कच्ची दरगाह, बिदुपुर, हाजीपुर, सोनपुर, दीघा, शेरपुर के रास्ते से कन्हौली तक गुजरेगा। इस रिंग रोड की कुल लंबाई लगभग 141 कि०मी० होगी। इस रिंग रोड के दक्षिणी हिस्से की कुल लंबाई लगभग 48 कि०मी० है, जिसमें 60 मी० चौड़ाई का भू–अर्जन कार्य, राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से पूर्ण कर लिया गया है।

पटना रिंग रोड राज्य के विभिन्न हिस्सों से पटना की ओर आनेवाली सड़कों को आपस में जोड़ेगा। इसके निर्माण हो जाने से पटना शहर में वैसे वाहनों की आवक नहीं होगी जिन्हें अपने मंजिल तक जाने हेतु पटना आने की आवश्यकता नहीं है। इस रिंग रोड के बन जाने से नव निर्माणाधीन बिहटा एयरपोर्ट तक सम्पूर्ण बिहार के लोग सीधे रिंग रोड के माध्यम से, बिना पटना में प्रवेश किए, आवागमन कर सकेंगे। राजधानी के नये महत्वाकांक्षी रेलवे स्टेशन पाटलीपुत्र पर भी आवागमन अधिकाधिक सुगम हो पायेगा। रिंग रोड के अंदर अनुमानित तौर पर 1337 वर्ग कि०मी० का क्षेत्रफल पड़ेगा जो पटना शहर के वर्त्तमान क्षेत्रफल से 13 गुणा अधिक होगा। यह रिंग रोड आने वाले समय में पटना राजधानी क्षेत्र, वैशाली एवं सारण जिला के सुनियोजित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

2. **गंगा पथ :–**

दीघा से महात्मा गांधी सेतु होते हुए दीदारगंज तक 21.5 कि०मी० लंबा फोरलेन गंगा पथ का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। इस पथ से गंगा नदी पर अवस्थित तीनों महत्वपूर्ण पुलों यथा– जे०पी० सेतु, महात्मा गांधी सेतु एवं कच्ची दरगाह–बिदुपुर सेतु आपस में जुड़ जाऐंगे। गंगा पथ से राजधानी के प्रमुख स्थानों यथा–एल०सी०टी० घाट, ए०एन० सिन्हा इंस्टीच्यूट, पी०एम०सी०एच०, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट एवं पटना घाट पर सम्पर्क रोड की व्यवस्था की जा रही है।

3. **दीघा एम्स एलिवेटेड रोड :–**

सरकार द्वारा जे०पी० सेतु के दक्षिणी भाग से 12.27 कि०मी० लंबाई का 4–लेन एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। इस रोड का निर्माण कार्य वर्ष 2018–19 में पूर्ण कर लिया जाएगा। इस रोड के समानांतर पटना नहर के पश्चिमी तटबंध पर अलग से 10 मीटर चौड़ा रोड बनाया जा रहा है। बेली रोड से दीघा तक के भाग को मार्च 2018 तक आवागमन हेतु खोल

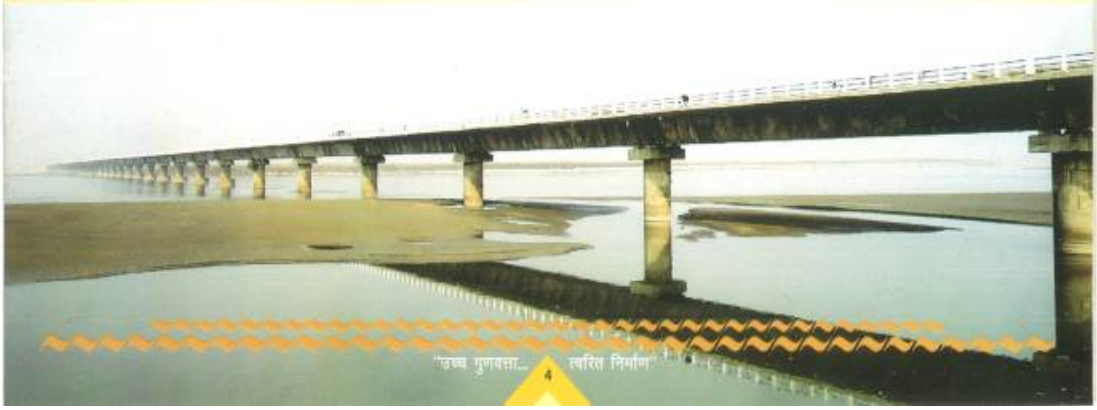

दिया जायेगा। इस प्रकार दीघा से एम्स तक सिक्स लेन कनेक्टिीभिटी होगी। फलस्वरूप महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों के आवागमन में व्यापक कमी आएगी।

4. **महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार :** –

महात्मा गांधी सेतु के समग्र जीर्णोद्धार के लिए लगभग 1300 करोड़ रु० की योजना की मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत तेजी से कार्य चल रहा है। मई 2019 तक पश्चिमी 2 लेनों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो जाएगा एवं उसके आगे डेढ़ वर्षों में पूर्वी दो लेनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। PM पैकेज के अंतर्गत महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नया फोरलेन ब्रिज प्रस्तावित है, जिसके लिए भूमि पूर्व से उपलब्ध है। इससे जीरो माईल पटना से पासवान चौक, हाजीपुर तक 8 लेन पथ की व्यवस्था हो पायेगी।

5. पटना शहर के अंतर्गत ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु अनेकों फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें मीठापुर एवं आर ब्लॉक फ्लाई ओवर निर्माणाधीन है। कंकड़बाग बाईपास फ्लाईओवर एवं ग़ांधी मैदान से पी०एम०सी०एच० तक फ्लाईओवर की योजना बन रही है।

6. पटना शहर के विभिन्न हिस्सों में "क्षेत्र आधारित" पथ विकास योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बेली रोड के उत्तर पुनाईचक, शास्त्री नगर, पटेल नगर, अंबेडकर नगर आदि क्षेत्रों की सम्पर्कता सुधारने के लिए 75 करोड़ की लागत से 13 कि०मी० लंबाई के पथों का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इसमें बेली रोड के समानान्तर नया पथ बनना है। पटना राजधानी क्षेत्र में अवस्थित ग्रामीण कार्य विभाग एवं नगर निकायों की सड़कों, जिनमें पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, उनका चरणबद्ध तरीके से हस्तांतरण करते हुए पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्माण की योजना को मंजूरी प्रदान की जा रही है।

7. बिहटा में प्रस्तावित एयरपोर्ट को राजधानी से जोड़ने के लिए शिवाला–बिहटा पथ पर एलिवेटेड रोड बनाये जाने की योजना है। सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन पथ को 6–लेन चौड़ीकरण किया जाएगा।

8. पटना शहर के प्रमुख नालों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें पक्कीकरण करते हुए उनके ऊपर आवागमन हेतु रोड बनाया जाना प्रस्तावित है। इसमें प्रमुख योजनाएँ यथा – सैदपुर नाले पर एलिवेटेड रोड का निर्माण, कुर्जी नाले पर रोड का निर्माण, बेली रोड से BMP तक नाले पर रोड का निर्माण समावेशित है।

9. राज्य के दक्षिणी हिस्सों से पटना रेलवे स्टेशन एवं राजधानी में आवागमन की सुगमता के दृष्टिकोण से मीठापुर फ्लाईओवर से मीठापुर फार्म होते हुए महुली तक पटना–गया रेल लाईन के पूरब एलिवेटेड पथ निर्माण की योजना का DPR बनाने की कार्रवाई की जा रही है।

10. **लोहिया पथ चक्र :–**

इन्कम टैक्स गोलम्बर से ललित भवन तक बेली रोड को सिग्नल–फ्री करने के लिए अत्यंत महत्त्वाकांक्षी लोहिया पथ चक्र की योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सर्कुलर रोड जंक्शन, पुनाईचक चौक एवं हड़ताली चौक पर अंडर पास एवं एलिवेटेड पथ का निर्माण होना है।

11. **SH-1 का 4–लेन चौड़ीकरण :–**

पहाड़ी जीरोमाईल से मसौढ़ी तक सादीकपुर–पभेढ़ा–मसौढ़ी पथ का 4–लेन चौड़ीकरण की योजना बनाई गई है, जिस पर स्वीकृति की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

12. पटना का अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड रामचक बैरिया में बनाया जा रहा है। इसकी पटना रेलवे स्टेशन से सुगम संपर्कता के लिए 2.83 कि०मी० लम्बाई का 4–लेन एलिवेटेड रोड बादशाही नाले से होकर बनाने का DPR बनाया जा रहा है।

नदियों पर पुलों का जाल :–

सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से राज्य की प्रमुख नदियों पर पुलों का जाल स्थापित किया गया है। राज्य के गंगा नदी पर जहाँ वर्ष 2005 से पहले मात्र बक्सर, पटना, मोकामा एवं भागलपुर में कुल चार पुल थे, वहीं आज इनके अतिरिक्त आरा–छपरा सेतु, जे.पी. सेतु बनकर तैयार हो गये हैं। जबकि महात्मा गाँधी सेतु का जीर्णोद्धार, कच्ची दरगाह–बिदुपुर 6 लेन पुल, बख्तियारपुर–ताजपुर पुल, मुंगेर पुल एवं अगुवानीघाट पुल पर कार्य चल रहे हैं।

उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार की बेहतर सम्पर्कता प्रदान करने के लिए गंगा नदी पर बक्सर पुल के समानान्तर , जे.पी. सेतु के समानान्तर, महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर, राजेन्द्र सेतु के समानान्तर, बिक्रमशीला सेतु के समानान्तर एवं मनिहारी–साहेबगंज के बीच नया पुल बनाने का निर्णय लिया गया है।

गंगा नदी के अतिरिक्त राज्य के अन्य प्रमुख नदियों पर भी विगत वर्षों में अनेकों पुलों का निर्माण कराया गया है।

गंडक नदी

जहाँ 2005 से पहले मात्र 3 पुल ही बने थे, वहीं अब धनहा–रतवल घाट एवं गोपालगंज–बेतिया पुल बनकर तैयार है तथा सतरघाट एवं बंगरा घाट का कार्य चल रहा है।

कोशी नदी

जहाँ 2005 से पहले मात्र 2 पुल ही बने थे, वहीं अब कोशी महासेतु, बलुआहा घाट, विजय घाट बनकर तैयार है। डुमरी घाट पुल का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। भेजा घाट एवं फुलौत घाट पर नये पुल बनाना प्रस्तावित है।

सोन नदी

जहाँ 2005 से पहले मात्र 2 पुल ही बने थे, वहीं अब अरवल–सहार पुल चालू है। दाउदनगर–नासरीगंज एवं कोईलवर पुल के समानान्तर नये 6 लेन का कार्य चल रहा है तथा पंडुका पुल का निर्माण कराने का प्रस्ताव है।

बागमती नदी

जहाँ 2005 से पहले मात्र 4 पुल ही बने थे, वहीं अब पिपराही, बैरगनियाँ, कटौंझा, डुब्बा घाट, माड़र घाट, फुलतोड़ा घाट एवं सोनमनखी घाट पुल बनकर तैयार है।

फल्गु नदी

जहाँ 2005 से पहले मात्र 1 पुल ही था, वहीं अब मानपुर 6 लेन पुल, कंडी (गया), वंशी बिगहा एवं हुलासगंज में पुल बनकर तैयार है जबकि एन०एच०–82 पर घुघड़ीटाँड़ एवं श्रीपुर–केनी में पुल निर्माणाधीन है।

भारत माला योजना में महत्वपूर्ण पथों का समावेश :–

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने इस वर्ष भारत माला योजना लागू की है। इसके अंतर्गत बिहार राज्य के अनेकों महत्वपूर्ण सड़कों को समावेशित किया गया है। इसके तहत् औरंगाबाद से दरभंगा तक नये 4–लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा इसका

मार्गरेखण निर्धारित कर भारत सरकार को संसूचित कर दिया गया है। औरंगाबाद से जहानाबाद होते हुए कच्चीदरगाह–बिदुपर पुल पार करते हुए ताजपुर से दरभंगा होते हुए जयनगर तक इस पथ का निर्माण किया जायेगा। इस मार्गरेखण से दक्षिण एवं उत्तर बिहार के नये इलाकों में 4–लेन पथों का जाल बिछ सकेगा।

भारतमाला में सासाराम–पटना 4–लेन पथ के निर्माण की योजना समावेशित है। राज्य सरकार द्वारा इसका भी मार्गरेखण निर्धारित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत सासाराम से आरा होते हुए आरा से बिहटा, मनेर, जेपी सेतु मार्गरेखण प्रस्तावित है।

NHAI द्वारा रजौली–बख्तियारपुर पथ का रख–रखाव करते हुए इसको 4–लेन में चौड़ीकरण किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा आरा–मोहनियाँ के पथांश को NHAI के माध्यम से पुर्नविकास करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

इण्डो–नेपाल बॉर्डर रोड :–

राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क सुविधा के विकास तथा सुरक्षा बलों के सुगम आवागमन के लिए भारत सरकार द्वारा इण्डो–नेपाल बॉर्डर रोड की स्वीकृति दी गई थी। इसके अंतर्गत पश्चिमी चम्पारण जिले के मदनपुर से राज्य के पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हुए बिहार–पश्चिम बंगाल सीमा पर गलगलिया तक पथ निर्माण होना है, जिसकी कुल लम्बाई 679 कि०मी० होगी। भारतमाला योजना के लागू हो जाने पर बॉर्डर क्षेत्रों के पथों के सुदृढ़ीकरण घटक के अंतर्गत इस पथ का सघन विकास NHAI के माध्यम से कराने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस पथ के NHAI के माध्यम से विकास होने से 10 मीटर चौड़ा पथ बन सकेगा, जिससे राज्य के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों का चहुँमुखी विकास हो पायेगा।

पटना से वाराणसी के आवागमन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने वाराणसी से बक्सर तक नया 4–लेन पथ के निर्माण की योजना का प्रस्ताव दिया है, जिसका DPR बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार बक्सर से गाजीपुर तक पथ निर्माण का प्रस्ताव गठित किया गया है। इससे लखनऊ होते हुए दिल्ली तक एक्सप्रेस–वे के माध्यम से सम्पर्कता स्थापित हो पायेगी।

शहरी क्षेत्रों में पथ विकास :–

मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार राज्य के सभी शहरों में अवस्थित अन्य विभागों के चौड़े पथों को भी शनैः शनैः पथ निर्माण विभाग के अधीन हस्तानांतरण कर उनका विकास कर रही है।

कई शहरों एवं कस्बों के बाईपास की योजना मंजूर की गई है। प्रमुख तौर पर मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मधुबनी, कटिहार, राजगीर, मुंगेर, नवादा, हिलसा, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, छपरा, आरा, बक्सर, सासाराम, भागलपुर, लखीसराय, जहानाबाद, गया आदि शहरों के बाईपास की योजनाएँ प्रमुख है। चरणबद्ध तरीके से राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में बाईपास का निर्माण किया जाएगा ताकि शहरों का सुनियोजित विस्तार हो सके।

OPRMC (Output & Performance Based Road Maintenance Contract) पथों का रख–रखाव :–

राज्य सरकार पथों के निर्माण के साथ–साथ दीर्घकालीन रख–रखाव पर अत्यधिक ध्यान दे रही है। इसी क्रम में वर्ष 2013 से Output & Performance Based Road Maintenance Contract (OPRMC) व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था के 5 वर्ष, वर्ष 2018–19 के दौरान पूर्ण होंगे। यह व्यवस्था अत्यंत कारगर रही है। अतः अब अगले 7 वर्षों हेतु इसी तर्ज पर योजना बनाकर निविदा आमंत्रित की जाएगी।

निधि की व्यवस्था :–

राज्य के आधारभूत ढांचे के व्यापक विकास में विभिन्न स्त्रोतों से निधि की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से राज्य स्कीम के अंतर्गत बड़ी धनराशि उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा केन्द्र सरकार के सहयोग से LWE क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के साथ–साथ केन्द्रीय योजना के विशेष पैकेज, विश्व बैंक, JICA, HUDCO, NABARD एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी सहायता ली जा रही है।

नवाचार :–

पथों के चौड़ीकरण एवं नये पथों के निर्माण हेतु भू–अर्जन की आवश्यकता होती है। राज्य में भूमि पर जनसंख्या का अधिकाधिक दबाव है, फलस्वरूप भू–अर्जन अतिरिक्त खर्चीला एवं कठिन कार्य है।

सरकार का यह दृष्टिकोण है कि राज्य के विकास कार्यों में भू–अर्जन प्रक्रिया से प्रभावित भूमिधारकों को भी हिस्सेदार बनाकर Land Pooling Policy के अंतर्गत उनसे ली जाने वाली भूमि का एक हिस्सा विकसित करके वापस उपलब्ध कराया जाए। इससे भूमिधारकों की भूमि के मूल्य में अभिवृद्धि होगी एवं सरकार को बिना व्यय किये सड़क निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इस क्रम में राज्य सरकार एक नीति बना रही है, जिसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

पथों के निर्माण में भू–अर्जन के कारण आने वाली कठिनाइयों को समय पर हल करने हेतु तीन भू–अर्जन विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है।

बिहार राज्य सड़क अनुसंधान संस्थान :–

राज्य में सड़कों एवं पुलों के व्यापक नेटवर्क को देखते हुए नवीनतम तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित करने तथा देश एवं विदेश में हो रहे तकनीकी अनुसंधानों से अनवरत अवगत होने के

दृष्टिकोण से केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की तर्ज पर "बिहार राज्य सड़क अनुसंधान संस्थान" की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा भूमि चिन्हित कर ली गई है। इस संस्थान के बन जाने से जहाँ विश्व स्तर पर हो रहे तकनीकी अनुसंधानों से अभियंता/संवेदक अवगत होंगे वहीं दूसरी ओर इससे अभियंताओं को नये प्रयोग करने के अवसर मिलेंगे।

बिहार राज्य पथ विकास निगम लि० :–

बिहार राज्य पथ विकास निगम लि० द्वारा राज्य में राज्य उच्च पथों के विकास हेतु व्यापक पैमाने पर कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बिहार राज्य पथ विकास निगम लि० ने अपनी स्थापना के लगभग 9 वर्षों की अवधि में कुल 8938.00 (अग्रिम सहित) आठ हजार नौ सौ अड़तीस करोड़ रू० की राशि का उपयोग करते हुए लगभग 1280 कि०मी० पथों का निर्माण पूर्ण किया है एवं 397 कि०मी० पथों का निर्माण कार्य जारी है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने में इस निगम ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस निगम ने पथों के निर्माण में गुणवत्ता का सराहनीय कार्य किया है।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम :–

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० ने पिछले 10 वर्षों (वर्ष 2007 से 2017 तक) में लगभग 1765 पुलों का निर्माण कार्य संपन्न किया है। इस अवधि में निगम द्वारा कुल 10245.00 (दस हजार दो सौ पैंतालिस) करोड़ रू० की राशि का उपयोग किया गया है। राज्य की प्रमुख नदियों पर पुल निर्माण की महत्वांकांक्षी योजनाओं को वांछित गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करने में इस निगम का योगदान उल्लेखनीय रहा है। राज्य सरकार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० की क्षमतावर्द्धन हेतु कृत संकल्पित है।

क्षमता विकास :–

अभियंताओं की रिक्तियों को भरने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। नियुक्ति प्रक्रिया में होने वाले संभावित विलम्ब को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा 200 सहायक अभियंताओं को संविदा आधारित नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत अप्रैल माह के अंत तक अभियंताओं की संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने की योजना है। विभाग द्वारा विषयवस्तु विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) के गठन का निर्णय लिया गया है, इसमें संविदा प्रबंधन एवं विधि विशेषज्ञ भी होंगे।

स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी :–

तेल कंपनियों द्वारा स्थापित होने वाले पेट्रोल पंपों को पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति लेनी होती है। अनापत्ति की शर्तों में सार्वजनिक शौचालय की स्थापना का प्रावधान रहता है। पेट्रोल पंपों द्वारा इस प्रावधान का गंभीरता से पालन नहीं किये जाने के दृष्टांत प्रकाश में आये हैं। विभाग ने इस पर अत्यधिक कड़ाई की है। मार्च 2018 तक सभी पेट्रोल पंपों पर जन साधारण के उपयोग के लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाएगी। जो पेट्रोल पंप मालिक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं कराएंगे, उन्हें निर्गत की गई अनापत्ति प्रमाण–पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। पेट्रोल पंपों पर सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था होने से स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी होगी।

बिहार राज्य पथ विकास निगम, राजधानी पटना में सार्वजनिक स्थानों पर 10 आधुनिक शौचालयों के निर्माण कार्य पर काम कर रहा है।

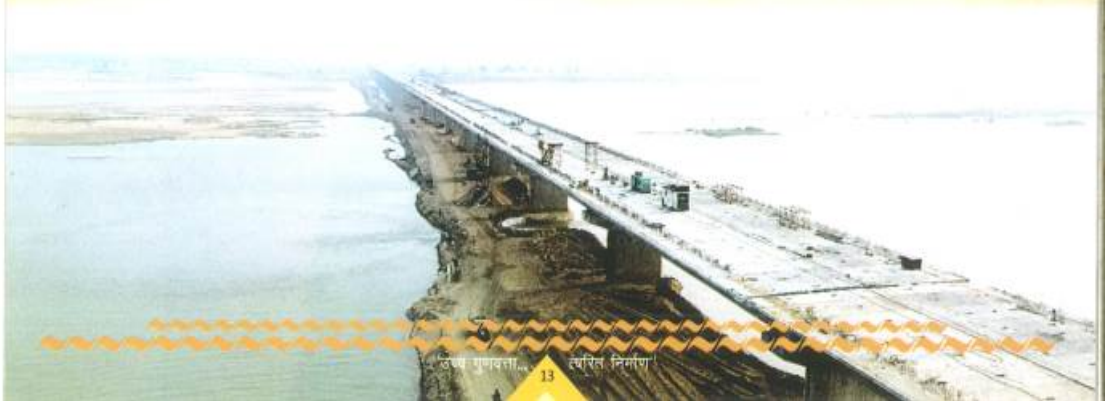

Way Side Amenities का विकास :–

राज्य सरकार द्वारा सभी स्टेट हाईवे के किनारे Way Side amenities की योजना बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत नागरिकों के आम उपयोग हेतु शौचालय, पेय जल की व्यवस्था एवं रेस्टोरेंट आदि का प्रावधान किया जायेगा।

सड़क सुरक्षा पर जोर :–

राज्य सरकार द्वारा सड़कों पर दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए सभी पथों का सुरक्षा अंकेक्षण कराया जाना है। वर्त्तमान में पथों पर सड़क सुरक्षा हेतु Traffic Calming के उपायों को लागू किया जा रहा है। इस क्रम में राष्ट्रीय उच्च पथों में 101 एवं अन्य पथों में 23 ब्लैक स्पॉट पाये गये है, जिनमें से 54 ब्लैक स्पॉट पर संरचनात्मक सुधार कर दिया गया है एवं शेष स्थानों पर संरचनात्मक सुधार किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा के दृष्टिकोण से 5 कि०मी० से अधिक के सभी कार्यों में डिजाईन के पूर्व सुरक्षा अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है।

निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता :–

विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु 15 लाख से ऊपर की सभी निविदा E-procurement के माध्यम से की जाती है। तकनीकी मूल्यांकन के परिणामों को विभागीय निविदा समिति के निर्णय के बाद 7 दिनों तक विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त होने वाले दावा/आपत्ति के निराकरण के उपरान्त ही निविदा का अग्रेतर निष्पादन किया जाता है। इस व्यवस्था से जहाँ लागत में कमी आयी है, वहीं न्यायालयों में निविदा संबंधी दायर होने वाले मामलों की संख्या प्रायः शून्य हो गयी है।

बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों / पुलों का पुनर्निर्माण :–

वर्ष 2017 के बाढ़ में उत्तर बिहार में सड़कों एवं पुलों की व्यापक क्षति हुई थी। आकलन के अनुसार 390 करोड़ की क्षति हुई थी। मुझे अवगत कराते हुए संतोष है कि 7 दिनों के अंदर सभी क्षतिग्रस्त पथांशों पर आवागमन चालू कर दिया गया एवं फरवरी के अंत तक अधिकांश पथों को स्थायी तौर पर पुनर्स्थापित कर दिया गया है। बाढ़ के फलस्वरूप जिन पथों में अतिरिक्त जल निकासी संरचना बनाना आवश्यक पाया गया, उनमें से कुल 182 स्थानों पर नये पुलों की आवश्यकता महसूस की गई, इन सभी स्थानों पर पुल निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

समयवद्ध कार्यपूर्णता एवं प्रभावी निविदा प्रंबधन :–

समय पर कार्य पूर्ण कराने पर जोर दिया गया है। अवधि विस्तार का निर्णय लेने हेतु अधिकतम 3 माह का समय निर्धारित किया गया है। जो संवेदक मूल समयसीमा या विस्तारित समयसीमा में कार्य पूर्ण नहीं करेंगे, उन्हें आगामी निविदाओं से वंचित किया जायेगा।

राज्य उच्च पथों / वृहद जिला पथों पर टॉल टैक्स की व्यवस्था को समाप्त करना :–

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बनाये गये अनेकों पुलों पर टॉल वसूली किया जाता है। एक आँकलन के अनुसार प्रति वर्ष लगभग रू० 37.66 करोड़ टॉल वसूली होती है। राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि इस टॉल को चुकाने में राज्य के नागरिकों को कठिनाई होती है। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल 2018 से राज्य के अंतर्गत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किसी भी पुल से टॉल वसूली नहीं की जाएगी।

रिटेल आऊट लेट / किसान सेवा केन्द्रों से पथों की भूमि के उपयोग हेतु एक मुश्त शुल्क लेने की व्यवस्था :–

राज्य सरकार द्वारा तेल कंपनियों के आंवटियों की सुविधा के लिए बाजार मूल्य आधारित सलामी एवं ग्राउण्ड रेंट की व्यवस्था को समाप्त करके, एक मुश्त शुल्क लागू करने की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब राज्य उच्च पथों एवं मुख्य जिला सड़कों पर अवस्थित रिटेल आऊटलेटों को ₹2,40,000 (दो लाख चालीस हजार) एक मुश्त जमा करना होगा एवं हर 5 साल पर ₹10,000 (दस हजार) नवीनीकरण शुल्क देय होगा। किसान सेवा केन्द्रों हेतु यह शुल्क 50% होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुदान माँग राशि संख्या –41 के अधीन पथ निर्माण विभाग का 68 अरब 89 करोड़ 12 लाख 83 हजार रूपये का अनुदान माँग स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।